48वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान (एनआईपीएफपी),

18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष इंस्टिट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू),
नई दिल्ली, भारत - 110067
दूरभाष संख्या: 011-26569303, 26569780, 26569784
ईमेल.: policy.communicatios@nipfp.org
वेब: https://www.nipfp.org.in

01 अप्रैल, 2023 – 31 मार्च, 2024

प्रकाशक:

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान)
18/2, सत्संग विहार मार्ग,
विशेष इंस्टिट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू),
नई दिल्ली 110067
दूरभाष.: 011 26569303, 26569780, 26569784
फैक्स: 91-11-26852548
ई-मेलI: policy.communications@nipfp.org
वेबसाइट: www.nipfp.org.in

संकलनकर्ता: अमिता मनहास
डिजाइनकार: रोहित दत्ता

मुद्रक: कुमार ब्रदर्स
ई-मेल: krbrotherdelhi@gmail.com

48वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान (एनआईपीएफपी),

18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष इंस्टिट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू),नई दिल्ली,- 110067

दूरभाष संख्या: 011-26569303, 26569780, 26569784

ईमेल.: policy.communicatios@nipfp.org

वेब: https://www.nipfp.org.in

विषय-सूची

प्रस्तावना 1

संस्थान का परिचय 1

शासी मण्डल 1

परियोजनाओं का सार : पूर्ण की गईं और चल रहीं 2

क्षमता-निर्माण कार्यक्रम 2

घटनाक्रम 4

अनुसंधान क्रियाकलाप 5

पूर्ण किए गए अध्ययन 5

केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्यकलाप 5

वित्त मंत्रालय के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्यकलाप 6

अन्य संस्थाओं/संगठनों केलिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप 8

चल रहे अध्ययन 13

केंद्रीय और राज्य सरकारों केलिए पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्यकलाप 13

वित्त मंत्रालय केलिए पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्यकलाप 14

अन्य संस्थाओं/संगठनों केलिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप 15

आरंभ की गईं नई परियोजनाएं 19

केंद्रीय और राज्य सरकारों केलिए पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्यकलाप 19

वित्त मंत्रालय केलिए पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्यकलाप 19

अन्य संस्थाओं/संगठनों केलिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप 20

कार्यशालाएं, बैठकें और सम्मेलन 21

प्रशिक्षण कार्यक्रम 22

प्रकाशन और संचार 24

पुस्तकालय और सूचना केंद्र 25

कंप्यूटर एकक 30

संकाय क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं 31

अनुबंध 58

अनुबंध I-अध्ययनों की सूचि 59

अनुबंध II-एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र श्रृंखला 67

अनुबंध III-एनआईपीएफपी आंतरिक सेमिनार श्रृंखला 69

अनुबंध IV- शासी निकाय के सदस्यों की सूची 70

अनुबंध V- समूल्य प्रकाशनों की सूची 75

अनुबंध VI- एनआईपीएफ संकाय सदस्यों की प्रकाशित सामग्री की सूची 79

अनुबंध VII-तक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार स्टॉफ सदस्यों की सूची 88

अनुबंध VIII- 2024 ,मार्च 31 तक की स्थिति के अनुसार प्रायोजक स्थायी और सामान्य ,कॉर्पोरेट ,सदस्यों की सूची 91

अनुबंध IX : वित्त एवं लेखा 92

प्रस्तावना

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट संस्थान में किए गए कार्यों का अवलोकन प्रस्तुत करती है तथा यह इसके शासी निकाय और जनता के प्रति इसके उत्तरदायित्व का प्रतिबिंब है। 48वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के दौरान एनआईपीएफपी के क्रियाकलापों का अवलोकन प्रस्तुत करती है। वर्तमान और विगत वार्षिक रिपोर्टों की डिजिटल प्रति का अवलोकन संस्थान की वेबसाइट पर किया जा सकता है।

संस्थान का परिचय

एनआईपीएफपी की स्थापना 1976 में सार्वजनिक अर्थशास्त्र और नीतियों में अनुसंधान के केंद्र के रूप में की गई थी। संस्थान की स्थापना वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, अनेक राज्य सरकारों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की संयुक्त पहल पर एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गई थी। एनआईपीएफपी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। संस्थान सार्वजनिक वित्त और अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, नीति संबंधी परामर्श और क्षमता निर्माण का कार्य करता है। संस्थान का एक मुख्य कार्य साक्ष्य-आधारित नीति इनपुट प्रदान करके सार्वजनिक नीतियों को तैयार करने और उनमें सुधार लाने में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की सहायता करना है।

अपने 48 वर्षों के अस्तित्व में, संस्थान भारत में एक प्रमुख चिंतक संस्थान के रूप में उभरा है और इसने सरकार के सभी स्तरों पर नीति सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने सदैव ही केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ कार्यात्मक संबंध स्थापित किए हैं, तथा भारत और विदेश, दोनों में अन्य शिक्षण और शोध संस्थानों के साथ निरंतर संबंध बनाए रखे हैं। हालाँकि संस्थान को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों से वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है, लेकिन इसने अनुसंधान और नीति के अपने प्रयासों में एक स्वतंत्र गैर-सरकारी चरित्र को कायम रखा है।

निदेशक मंडल

संस्थान के शासी निकाय ने 14 मार्च 2024 को आयोजित अपनी 117वीं बैठक में स्वयं को चार वर्ष की अवधि अर्थात 5 अप्रैल 2024 से 4 अप्रैल 2028 तक के लिए पुनर्गठित किया। शासी निकाय के अध्यक्ष डॉ. उर्जित पटेल हैं। वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा, सचिव (आर्थिक मामले) श्री अजय सेठ और मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व मौद्रिक नीति विभाग के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजीव रंजन कर रहे हैं और नीति आयोग द्वारा इसके लिए डॉ. प्रवाकर साहू, सीनियर लीड (आर्थिक और वित्त) को नामित किया है। प्रायोजक राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं: श्री एन. मुरुगनंदम, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार; श्री शाश्वत मिश्रा, आईएएस, प्रधान सचिव (वित्त विभाग), ओडिशा सरकार; और श्री जे.पी. गुप्ता, आईएएस, प्रधान सचिव, गुजरात सरकार। आईसीआईसीआई बैंक ने श्री प्रसन्ना बालाचंदर, वैश्विक प्रमुख-बाजार (बिक्री, व्यापार और अनुसंधान) को शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया है। श्री दीपक सूद, महासचिव, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), और डॉ. अनीश शाह, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) को इनसंस्थानों के ओर से नामित किया गया है।

शासी निकाय में तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं - डॉ. एम. गोविंदा राव, पूर्व सदस्य, चौदहवां वित्त आयोग; डॉ. ज्योत्सना जालान, प्रोफेसर-अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, कोलकाता; और डॉ. माला लालवानी, प्रोफेसर-राजनीतिक अर्थव्यवस्थ, मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई।

सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों में डॉ. पूनम गुप्ता, महानिदेशक, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) और डॉ. श्रीनिवास चोक्काकुला, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) शामिल हैं। सीए (सुश्री) केमिशा सोनी, काउंसिल सदस्य, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, शासी निकाय की सह-चयनित सदस्य हैं।

डॉ. आर. कविता राव वर्तमान निदेशक और शासी निकाय की पदेन सदस्य हैं । डॉ. मीता चौधरी, प्रोफेसर, बोर्ड में एनआईपीएफपी संकाय का प्रतिनिधित्व करती हैं।

शासी निकाय के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं – श्री रवि अग्रवाल, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, और श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार । (*विवरण के लिए अनुलग्नक IV देखें*)

परियोजनाओं का सारांश : पूर्ण की गईं और चल रही

वर्ष 2023-24 में, एनआईपीएफपी ने अनेक विषयों पर अध्ययन और शोधपत्र पूर्ण किए। इनमें व्यापक क्षेत्रों में कराधान, व्यय की समीक्षा, मध्यम अवधि की व्यय की योजनाएँ और राजकोषीय उत्तरदायित्व, विधि का अनुपालन, व्यापक आर्थिक मूल्यांकन, जलवायु अनुकूल बजट और जलवायु वित्त और राष्ट्रीय आय लेखांकन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

सोलहवें वित्त आयोग के गठन की प्रत्याशा में, राज्य वित्त पर ध्यान केंद्रित करने वाले अनेक अध्ययन संचालित किए गए। इनमें चुनिंदा राज्य करों के माध्यम से राजस्व जुटाने की गुंजाइश, चुनिंदा राज्यों की स्पष्ट सब्सिडी का विश्लेषण तथा सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक निवेश प्रबंधन का विश्लेषण शामिल हैं। इसके अलावा, घाटे, कर्ज और स्थिरता के क्षेत्र में, राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र की उधार संबंधी अपेक्षाओं की अवधारणा को समझने के लिए अध्ययन किए गए हैं, जो कि ऑफ-बजट उधार के संदर्भ में, आर्थिक विकास और ऋण स्थिरता के संदर्भ में इष्टतम ऋण के विचार पर और राज्यों के लिए उधार लेने में बाजार-प्रेरित अनुशासन के दायरे को मजबूत करने के लिए ऋण बाजारों के सुधारों के विश्लेषण पर आधारित हैं।

चल रहे कार्यों में, संस्थान ने शहरी वित्त पर डेटाबेस तैयार करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ एक शोध कार्यक्रम शुरू किया है और शहरी वित्त के मुद्दों पर व्यवस्थित शोध संचालित किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ चल रही एक और पहल यूएनएफसीसीसी के लिए 4वें राष्ट्रीय संचार और 4वीं द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट की तैयारी के लिए सहयोग प्रदान करने से संबंधित है।

राज्य वित्त की दिशा में, संस्थान उत्तराखंड के लिए सार्वजनिक व्यय और वित्तीय उत्तरदायित्व का आकलन कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और त्रिपुरा सरकार के अनुरोध पर राजस्व प्रदर्शन का आकलन करने और राजस्व में वृद्धि करने के विकल्पों की पहचान करने के लिए अध्ययन शुरू किए गए हैं। कर्नाटक सरकार के लिए जीएसडीपी में आधारभूत परिवर्तन से उत्पन्न पद्धतिगत मुद्दों पर अध्ययन संचालित किया गया है।

अन्य अध्ययनों में योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर लगातार चुनावों के प्रभाव पर एक अध्ययन तथा ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के स्रोत से राजस्व उत्पन्न करने के लिए एक व्यवहार्य वित्तीय मॉडल तैयार करने पर एक अध्ययन शामिल है।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के साथ हमारे चल रहे सहयोग से क्रिप्टोकरेंसी, ऋण प्रबंधन, वित्तीय तनाव, बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था की निगरानी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय मात्रा में अनुसंधान और नीतिगत परिणाम सामने आए हैं। कार्यक्रम में राज्य वित्त पर कुछ अध्ययन भी शामिल थे। *(सभी परियोजनाओं के विवरण के लिए अनुसंधान क्रियाकलापों का संदर्भ ग्रहण करें और अनुलग्नक-I देखें)।*

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

एनआईपीएफपी ने अपने अधिदेश से संबंधित मुद्दों पर वर्ष भर अनेक कार्यशालाएं, बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए।

संस्थान ने 2-3 नवंबर 2023 को एनआईपीएफपी में विश्व बैंक के सहयोग से 'राज्य मंच 2023: राज्य वित्त में विचार और नवाचार साझा करना'विषय पर एक दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। चर्चा और प्रस्तुतियों के प्रसार की प्रक्रिया के भाग के रूप में, राज्य मंच के पहले संस्करण में प्रस्तुत किए गए शोधपत्रों को 'राज्य मंच 2023: एक संकलन' नामक खंड में संकलित किया गया है। संकलन एनआईपीएफपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसका अवलोकन https://nipfp.org.in/media/medialibrary/2024/08/State_Forum_2023_-_A_Compendium.pdf पर किया जा सकता है।

संस्थान ने 23-24 नवंबर 2023 को एनआईपीएफपी में 'बेहतर परिणामों के लिए स्वास्थ्य वित्तपोषण के केंद्र-राज्य संरेखण' पर एक दो-दिवसीय वार्ता भी आयोजित की।

एनआईपीएफपी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया:

- यूनिसेफ इंडिया और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 8 अगस्त 2023 को 'योजना में बालकों की प्राथमिकताओं को मुख्यधारा में लाना – राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) हस्तांतरण फॉर्मूले में बालकों से संबंधित संकेतकों को एकीकृत करना' पर एक-दिवसीय परामर्श कार्यशाला।
- 11 अगस्त 2023 को एनआईपीएफपी में 'भारत की प्रगति क्या है? मध्य-वर्षीय मैक्रोइकॉनॉमिक समीक्षा' पर एक-दिवसीय चर्चा।
- फाउंडेशन फॉर यूरोपियन प्रोग्रेसिव स्टडीज (एफईपीएस) के साथ संयुक्त रूप से एनआईपीएफपीद्वारा 'रणनीतिक खुलापन? सीबीएएम के समावेशी कार्यान्वयन की दिशा में', 12 अक्टूबर 2023 को आधे दिन का सम्मेलन (ऑनलाइन)।
- अर्चना द्विवेदी, कार्यकारी निदेशक, निरंतर ट्रस्ट द्वारा एनआईपीएफपी में 'लिंग संवेदीकरण' पर आधे दिन का वार्ता सत्र, 20 दिसंबर 2023।

संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए:

- अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति – प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन), डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से। 24-26 मई 2023.
- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर 15वां पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम। 5-16 जून 2023.
- अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, वित्त विभाग, असम सरकार, गुवाहाटी के सेवारत अधिकारियों के लिए 'जीएसडीपी आकलन और ग्रीन बजट की तैयारी के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित मुद्दों' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 26-28 जुलाई 2023.
- भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी), दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 18-22 सितंबर 2023.
- बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला बैंक प्रबंधकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम । 20-24 नवंबर 2023.
- अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से 'राजकोषीय नीति – प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम । 4-8दिसंबर2023।
- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईएएंडएएस), एनएएए, शिमला के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम । 11-12 दिसंबर 2023.
- मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवा (एमएफए) अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत बनाने' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम । 8-12 जनवरी 2024.
- बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला बैंक प्रबंधकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम । 15-19 जनवरी 2024.

आत्म-निर्भरता हासिल करने पर रिपोर्ट

एनआईपीएफ को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अपने मुख्य कर्मचारियों के कुल वेतन व्यय के 90 प्रतिशत के बराबर वार्षिक अनुदान मिलता है। वेतन व्यय तथा अन्य प्रशासनिक और पूंजीगत व्यय का शेष भाग संस्थान के अपने संसाधनों से पूरा किया जाता है। अनुदान के अलावा, संस्थान विभिन्न मंत्रालयों के लिए परियोजनाओं और विभिन्न

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करके राजस्व अर्जन भी करता है। संस्थान के अपने संसाधनों से पूरा किया गया व्यय प्रतिशत 2022-23 में 58.30 प्रतिशत था, जो 2023-24 में घटकर 55.37 प्रतिशत रह गया।

घटनाक्रम

नियुक्तियाँ

- डॉ. मुकेश कुमार आनंद ने 6 मार्च 2024 को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. सुरांजलि टंडन ने 29 मई 2023 को एसोसिएट प्रोफेसरके पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. सुकन्या बोस ने 29 मई 2023 को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. राधिका पांडे ने 31 मई 2023 को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. आकांक्षा श्रवण ने 28 जुलाई 2023 को सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. रेशम नागपाल ने 7 अगस्त 2023 को सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री आकाश गुप्ता ने 11 अप्रैल 2023 को अर्थशास्त्री के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री एसके मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने11 जुलाई 2023 को अर्थशास्त्री के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री रॉबी थॉमस ने 13 मार्च 2024 को ईडीपी मैनेजर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री पंकज कुमार सिन्हा ने 11 अप्रैल 2023 को सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

सेवानिवृत्ति

- श्री मोहन सिंह बिष्ट, फोटोकॉपी ऑपरेटर, 29 फरवरी 2024 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

त्यागपत्र

- डॉ. सुप्रियो डे, प्रोफेसर (आरबीआई चेयर) 19 मई 2023 को त्यागपत्र देकर कार्यमुक्त हो गए।
- डॉ. रेणुका साने, एसोसिएट प्रोफेसर 31 दिसंबर 2023 को देकर देकर कार्यमुक्त हो गईं।

अनुसंधान कार्यकलाप

पूर्ण किए गए अध्ययन

केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्यकलाप

1. **मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम 2019-20 और 2020-21 के उपबंधों के अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा (जुलाई 2023 से मार्च 2024)**

   प०रायोजक: मध्य प्रदेश सरकार
   दल: प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
   उद्देश्य: यह मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य के वित्त एवं राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम अधिनियम) के अनुपालन की एक स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार और प्रस्तुत की गई थी। मूल्यांकन रिपोर्ट ने इन दो वर्षों के लिए राजकोषीय प्रबंधन प्रक्रिया के प्रमुख निष्कर्षों और सीखे गए सबकों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम लक्ष्यों के संबंध में राज्य के अनुपालन को प्रकाश में लाने के अलावा, रिपोर्ट ने राजकोषीय प्रबंधन की व्यापक प्रवृत्ति का आकलन किया। बजटीय योजनाओं को लागू करने की सरकार की क्षमता का आकलन करने के लिए राजस्व और व्यय से संबंधित बजटीय अनुमानों का विश्लेषण परिणामों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

2. **सिक्किम के लिए मध्यम अवधि की राजकोषीय योजनाएं : 2023-24 से 2025-26 (अप्रैल 2023 से मई 2023)**

   प्रायोजक: सिक्किम सरकार
   दल: प्रताप रंजन जेना
   उद्देश्य: रिपोर्ट ने सिक्किम सरकार के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए मध्यम अवधि की राजकोषीय योजनाएँ (एमटीएफपी) प्रस्तुत कीं। एमटीएफपी 2023-24 आगामी बजट वर्ष और अगले दो वर्षों में राजकोषीय नीतिगत उद्देश्य और अनुमानित राजकोषीय लक्ष्य प्रदान करता है। रिपोर्ट मौजूदा मैक्रो-राजकोषीय वातावरण के आधार पर और सिक्किम में एफआरबीएमए अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। रिपोर्ट ने एफआरबीएम अधिनियम की शर्तों के साथ संरेखित बजट वर्ष सहित तीन वर्षों के लिए राजकोषीय परिवर्तियों का अनुमान लगाया।

3. **वर्ष 2020-21 (जनवरी 2023 से जून 2023) के लिए सिक्किम सरकार द्वारा राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा**

   प्रायोजक: सिक्किम सरकार
   दल: प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
   उद्देश्य: रिपोर्ट का उद्देश्य सामान्यत: राज्य वित्त और विशेषत: राजकोषीय उत्तरदायित्व विधि से संबंधित इन मुद्दों का समाधान करना था: 1) वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफआरबीएम अधिनियम के उपबंधों के लिए राज्य सरकार का अनुपालन; 2) व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण का आकलन; और 3) राजस्व प्रयास, केंद्रीय हस्तांतरण, खर्च पैटर्न और ऋण प्रबंधन के संदर्भ में राज्य के वित्त का आकलन।

4. **वर्ष 2021-22 के लिए सिक्किम सरकार द्वारा राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा (मार्च 2024)**

   प्रायोजक: सिक्किम सरकार
   दल: प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
   उद्देश्य: वित्तीय वर्ष 2021-22 में एफआरबीएम अधिनियम के उपबंधों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन।

वित्त मंत्रालय के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्यकलाप

1. **वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधि प्रभाग (1अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 *तक*) ।** *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*

   प०्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

   दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशिम कपूर, उत्सव सक्सेना, राम्या राजाश्री कुमार, रितिका सिंह, सिमरन कौर, राधिका अग्रवाल, मधुर मेहता, कृति वट्टल, आनंदिता गुप्ता, फिरदौस अहमद मलिक, लता बालासुब्रमण्यम, प्रवीण सिंह, एस. भुवनकौशिक, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन, यशोवर्धन चतुर्वेदी, पुलकित शर्मा, अंकित सिंह, अनुकृति चौबे, आशीष राज और सुशील कुमार मोदी।

   उद्देश्य: (1) वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के लिए विधायी मसौदा, शोध टिप्पण और प्रस्तुतियाँ; (2) वित्तीय क्षेत्र विकास और विनियमन (संकल्प) विधेयक के लिए विधायी मसौदा, अनुसंधान टिप्पण और प्रस्तुतियाँ।

2. **अन्य बहुपक्षीय संस्थान प्रभाग (अप्रैल *2022* से मार्च *2024* तक) ।** *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*

   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

   दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशिम कपूर, उत्सव सक्सेना, राम्या राजश्री कुमार, रितिका सिंह, सिमरन कौर, राधिका अग्रवाल, मधुर मेहता, कृति वट्टल, आनंदिता गुप्ता, फिरदौस अहमद मलिक, लता बालासुब्रमण्यम, प्रवीण सिंह, एस. भुवनकौशिक, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन, यशोवर्धन चतुर्वेदी, पुलकित शर्मा, अंकित सिंह, अनुकृति चौबे, आशीष राज और सुशील कुमार मोदी।

   उद्देश्य: (1) भारत के ऊर्जा क्षेत्र में उन्नति का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से तकनीकी सहायता और निजी पूंजी जुटाने के संदर्भ में एआईआईबी के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना; (2) एमडीबी और आईएफआई द्वारा स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण (एलसीएफ) संचालन पर टिप्पण, जिसमें एआईआईबी, आईबीआरडी, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) पर ध्यान केंद्रित किया गया है; और (3) बाहरी वाणिज्यिक उधार और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश चैनलोंके माध्यम से एलसीएफ के लिए भारतीय विनियामक फ्रेमवर्क पर टिप्पण।

3. **सिक्का और मुद्रा प्रभाग (अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक) ।** *(एनआईपीएफपी-डीईएअनुसंधानकार्यक्रमका भाग)*

   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

   दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशिम कपूर, उत्सव सक्सेना, राम्या राजाश्री कुमार, रितिका सिंह, सिमरन कौर, राधिका अग्रवाल, मधुर मेहता, कृति वट्टल, आनंदिता गुप्ता, फिरदौस अहमद मलिक, लता बालासुब्रमण्यम, प्रवीण सिंह, एस भुवनकौशिक, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन, यशोवर्धन चतुर्वेदी, पुलकित शर्मा, अंकित सिंह, अनुकृति चौबे, आशीष राज और सुशील कुमार मोदी।

   उद्देश्य: (1) क्रिप्टोकरेंसी बाजार और विनियामक विकास पर मासिक रिपोर्ट, और क्रिप्टोस्पेस में रिपोर्ट/चर्चा; और (2) अधिकार क्षेत्र, विनियामक विकास में सीबीडीसी परियोजनाओं की स्थिति का पता लगाने वाली सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) पर मासिक रिपोर्ट; और रिपोर्ट/चर्चाएं।

4. **वित्तीय स्थायित्व और साइबर सुरक्षा प्रभाग (अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक) ।** *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*

   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशिम कपूर, उत्सव सक्सेना, राम्या राजश्री कुमार, रितिका सिंह, सिमरन कौर, राधिका अग्रवाल, मधुर मेहता, कृति वट्टल, आनंदिता गुप्ता, फिरदौस अहमद मलिक, लता बालासुब्रमण्यम, प्रवीण सिंह, एस. भुवनकौशिक, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन, यशोवर्धन चतुर्वेदी, पुलकित शर्मा, अंकित सिंह, अनुकृति चौबे, आशीष राज और सुशील कुमार मोदी।

उद्देश्य: (1)भारत के वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न खंडों के लिए वित्तीय तनाव सूचकांकों क विश्लेषणको कवर करने वाले वित्तीय स्थिरता के मुद्दों पर मासिक रिपोर्ट; (2) वित्तीय भेद्यता के प्रारंभिक संकेतों को प्राप्त करने के लिए मासिक मैक्रो डैशबोर्ड। पहचानी गई सीमाओं के आधार पर, प्रमुख वित्तीय क्षेत्र चर को भेद्यता/तनाव के हल्के, मध्यम और गंभीर स्तरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5. **वित्तीय बाजार प्रभाग (अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक)** । *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशिम कपूर, उत्सव सक्सेना, राम्या राजश्री कुमार, रितिका सिंह, सिमरन कौर, राधिका अग्रवाल, मधुर मेहता, कृति वट्टल, आनंदिता गुप्ता, फिरदौस अहमद मलिक, लता बालासुब्रमण्यम, प्रवीण सिंह, एस. भुवनकौशिक, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन, यशोवर्धन चतुर्वेदी, पुलकित शर्मा, अंकित सिंह, अनुकृति चौबे, आशीष राज और सुशील कुमार मोदी।

उद्देश्य: संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ वार्ता के लिए अनुसंधान समर्थन, अर्थात्: 1) अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुति; 2) सचिव (ईए) के लिए वार्ता-बिंदु; और3) रेटिंग एजेंसियों से प्राप्त प्रश्नावली/चर्चा विषयों पर प्रतिक्रियाएँ।

6. **पूंजीगत व्यय पर डीईए परियोजना(अगस्त2023 से फरवरी 2024 तक)** । *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह

उद्देश्य: अध्ययन ने वित्त वर्ष 2013-14 से उनके बजटीय लक्ष्यों की तुलना में केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के वास्तविक पूंजीगत व्यय में अंतर के रुझानों और कारणों का अलग-अलग (क्षेत्रवार और घटकवार) विश्लेषण किया। अध्ययन ने निम्नलिखित शोध उद्देश्यों को संबोधित किया: 1) वित्त वर्ष 2013-14 से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय के रुझानों और संरचना की जांच करना; 2) वित्त वर्ष 2013-14 से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विश्लेषण करना; और 3) केंद्र और राज्यों में वास्तविक बनाम आवंटित पूंजीगत व्यय के बीच अंतर के कारणों की जांच करना।

7. **संविधान के अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 74 के तहत राज्य सरकारों द्वारा संबंधित स्थानीय निकायों को वित्त के रुझान और हस्तांतरण तंत्र पर राज्यवार रिपोर्ट (अप्रैल 2022से जनवरी 2024)** । *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: मनीष गुप्ता और प्रियांशी गर्ग

उद्देश्य: इस परियोजना में बजट दस्तावेजों, वित्त आयोग की रिपोर्टों और सूचना के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 के तहत राज्य सरकारों द्वारा संबंधित स्थानीय निकायों को वित्त के रुझानों और हस्तांतरण तंत्र की जांच करना शामिल है।

8. **भारत में सेवानिवृत्ति लाभ और सामाजिक पेंशन पर सार्वजनिक व्यय (दिसंबर 2022)** । *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: मुकेश कुमार आनंद और पुलकित कुमार शर्मा

उद्देश्य: शोध रिपोर्ट तीन भागों में संचयी रूप से पेंशन प्रणाली पर सार्वजनिक व्यय का निर्माण करती है। प्रत्येक भाग पिछले भाग की तुलना में क्रमशः (क) राज्यों द्वारा अपने नागरिक प्रतिष्ठानों को चलाने पर व्यय, (ख) संघ सरकार द्वारा अपने नागरिक और रक्षा प्रतिष्ठानों को चलाने में व्यय, जिसमें विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (दूरसंचार, डाक और रेलवे) शामिल हैं, और (ग) सरकार के सभी स्तरों द्वारा निजी और सामाजिक पेंशन का समर्थन करने के लिए व्यय, जिसमें सरकारी बांड और प्रतिभूतियों में पेंशन निधि निवेश के लिए सेवा लागत शामिल है, का विश्लेषण शामिल है।

9. **राज्यों के स्वयं के कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व पर राज्य-स्तरीय विश्लेषण– वर्ष (अप्रैल 2022 से मार्च 2024) के दौरान डीईए-एमओएफ के लिए दो रिपोर्ट पूरी की गईं ।** *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: भवेश हजारिका, दिनेश कुमार नायक और अंकित सिंह

उद्देश्य: इस राज्य स्तरीय अध्ययन का उद्देश्य भारत के राज्यों में स्वयं के कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व के रुझानों और पैटर्न का विश्लेषण करना है। अध्ययन में राजस्व के प्रमुख स्रोतों और राज्यों के समग्र राजस्व में उनके योगदान की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना शामिल है। इस अध्ययन के निष्कर्ष राज्यों में नीति निर्माताओं और हितधारकों को उनकी राजस्व संरचना को बेहतर ढंग से समझने, राजस्व सृजन और आवंटन के बारे में निर्णय लेने और अंततः राज्यों के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करेंगे।

10. **भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी के लिए नियमावली तैयार करना एवं तालिकाएँ तैयार करना (2022 से मार्च 2024) ।** *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: अमरनाथ एच.के. और श्रीहरि नायडू ए.

उद्देश्य: भारतीय सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी संकलित करने के लिए नियमावली तैयार की और वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक के लिए डेटा तालिका तैयार की।

11. **राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की तृतीय पक्ष पारदर्शिता संपरीक्षा: 2022-23 (जून - अक्तूबर 2023)।**

प्रायोजक: राजस्व विभाग(डीओआर), वित्त मंत्रालय ने एनआईपीएफपी को यह कार्य सौंपा है (कल्याणार्थ)

दल: सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला

उद्देश्य: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (डीओआर) ने एनआईपीएफपी को विभाग के अंतर्गत 78 सार्वजनिक प्राधिकरणों के तृतीय-पक्ष पारदर्शिता संपरीक्षा का कार्य सौंपा है। अब तक, एनआईपीएफपी ने 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए कार्य पूरा कर लिया है।

अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप

1. **एल्कोहॉलिक पेय पदार्थों पर कर से राजस्व जुटाना (18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक)**

प०्रायोजक: यूनाइटेड किंगडम सरकार का विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करता है।

दल: आर. कविता राव, सच्चिदानंद मुखर्जी, शिवानी बडोला और विवेक जाधव

उद्देश्य: राज्य उत्पादशुल्क, राज्य के माल और सेवा कर (जीएसटी) और बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) के बाद उन वस्तुओं पर जो वर्तमान में जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं (जैसे, पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन

ईंधन, या एटीएफ, कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और मानव उपभोग के लिए मादक पेय), राज्य के स्वयं के कर राजस्व (ओटीआर) का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। राज्य उत्पादशुल्क का कर आधार राज्य में मादक पेय (जैसे, भारतीय निर्मित विदेशी शराब, या आईएमएफएल, देशी शराब, बीयर) और अन्य मादक पदार्थों (अफीम, भारतीय भांग, और अन्य मादक दवाएं और मादक पदार्थ) की खपत है। कुछ राज्य राज्य उत्पादशुल्क के अलावा मादक पेय पदार्थों पर बिक्री कर भी वसूलते हैं। मादक पेय पदार्थों पर राज्य उत्पादशुल्क और बिक्री कर से संयुक्त राजस्व ओटीआर का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए, यह अध्ययन राज्यों के लिए मादक पेय पदार्थों से राज्य उत्पाद शुल्क संग्रह को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए उपयोगी हो सकता है।

2. भारतीय राज्यों में यात्री और माल कर (पीजीटी) की राजस्व क्षमता (18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक)

प्रायोजक: यूनाइटेड किंगडम सरकार का विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करता है।

दल: आर. कविता राव, सच्चिदानंद मुखर्जी, शिवानी बडोला और विवेक जाधव

उद्देश्य: इस अध्ययन में, हम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यात्री और माल कर (पीजीटी) संग्रह में राज्यों की राजस्व क्षमता का अनुमान लगाते हैं। माल और यात्रियों पर कर (जिसे यात्री और माल कर या पीजीटी के रूप में भी जाना जाता है) सड़क या अंतर्देशीय जलमार्गों पर ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर एक कर है। यह कर जीएसटी में शामिल नहीं है, सिवाय इसके कि राज्य सूची (भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II) की प्रविष्टि 52 के तहत "उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर" को संविधान के एक सौ एकवें संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार जीएसटी में शामिल किया गया है।

3. प्रमुख भारतीय राज्यों के लिए कितना ऋण इष्टतम है? आर्थिक विकास बनाम ऋण स्थिरता (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)

प्रायोजक: यूनाइटेड किंगडम सरकार का विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करता है।

दल: रुद्रानी भट्टाचार्य, सी. प्रशांत और आर. कविता राव

उद्देश्य: वित्त अधिनियम 2018 के तहत संशोधित एफआरबीएम अधिनियम 2003 ने राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत तक सार्वजनिक ऋण रखने की अनुमति दी। इस संदर्भ में, प्रस्तुत अध्ययन ऋण से उत्पादन अनुपात की एक इष्टतम सीमा का पता लगाता है जो आर्थिक विकास के लिए अनुकूल है और आर्थिक और राजकोषीय स्थितियों में राज्य-स्तरीय विविधताओं पर विचार करते हुएराजकोषीय स्थिरता के लिए उपयुक्त है। वर्ष 2001-02 से 2019-20 की अवधि के साक्ष्य के आधार पर, कुल मिलाकर, भारत के 18 प्रमुख राज्यों के लिए, सार्वजनिक ऋण 25 प्रतिशत के इष्टतम ऋण-जीएसडीपी अनुपात तक संधारणीय है। सार्वजनिक ऋण वित्तपोषित व्यय ऋण-जीएसडीपी अनुपात के 22 प्रतिशत की सीमा और जीएसडीपी अनुपात के लिए 2 प्रतिशत पूंजीगत व्यय की सीमा से परे वास्तविक आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है। ऋण-जीएसडीपी अनुपात को निर्धारित 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का विकास बढ़ाने वाला प्रभाव, उच्च आर्थिक वृद्धि वाले राज्यों की तुलना में कम आर्थिक वृद्धि वाले राज्यों में अधिक होगा। यह उच्च सामाजिक व्यय वाले राज्यों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाएगा, जबकि कम सामाजिक व्यय वाले राज्यों में आर्थिक वृद्धि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋण-जीएसडीपी अनुपात को बढ़ाने का विकास बढ़ाने वाला प्रभाव आर्थिक सेवाओं पर व्यय के कम और उच्च भाग वाले राज्यों के लिए समान होगा।

4. **चयनित राज्यों (ओडिशा और तमिलनाडु) में सार्वजनिक निवेश के प्रबंधन पर जायजा (मार्च 2023 से जून 2023)**

प्रायोजक: विश्व बैंक

दल: सुप्रियो डे, लेखा चक्रवर्ती, आर. कविता राव, पियाली दास, मयूराक्षी सिन्हा, सीमा मौर्य और दिव्या रुद्र

उद्देश्य: भारत सरकार (जीओआई), यह मानते हुए कि प्राथमिक विकास बाधा मजबूत अवसंरचना की कमी है, अवसंरचना की कमी को पाटने के लिए अनेक पहलों को क्रियान्वित कर रही है। चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेश को देखते हुए, राजकोषीय समेकन जारी रहने की उम्मीद है, जिससे अवसंरचना पर व्यय बढ़ाने के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी। इसके परिणामस्वरूप, अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निवेश की दक्षता को अधिकतम करना और अवसंरचना में निजी निवेश को जुटाना महत्वपूर्ण है। इस चुनौती से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस विषय पर जुड़ाव के लिए विश्लेषणात्मक आधार में योगदान करने के लिए विश्व बैंक द्वारा नैदानिक कार्य प्रस्तावित किया गया है। चयनित राज्यों में सार्वजनिक निवेश के प्रबंधन का जायजा लेने का प्रस्ताव है। यह कार्य एक प्रश्नावली और विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर किया जाएगा जो भारतीय संदर्भ के अनुरूप होगा, जिसमें राज्यों से अच्छे अभ्यास और सबक पर प्रकाश डाला जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाया जाएगा।

5. **राज्यों के ऋण और बांड बाज़ार का विश्लेषण (18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक)**

प्रायोजक:यूनाइटेड किंगडम सरकार का विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करता है।

दल: राधिका पांडे, उत्सव सक्सेना, मधुर मेहता, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन और कृति वट्टल

उद्देश्य: 'राज्यों के ऋण और बांड बाजारों का विश्लेषण' शीर्षक वाली रिपोर्ट भारत में राज्य बांड बाजार से संबंधित मुद्दों की जांच करने का प्रयास करती है। गुणात्मक पक्ष पर, यह राज्य उधारों को नियंत्रित करने वाले विधायी और विनियामक ढांचे की पड़ताल करती है, साथ ही इसमें शामिल विभिन्न संस्थानों के बारे में चर्चा करती है, जिसमें राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (राज्यों का ऋण प्रबंधक), वित्त आयोग (एफसी), साथ ही ऋण प्रबंधन के लिए आंतरिक विभाग शामिल हैं। मात्रात्मक पक्ष पर, रिपोर्ट राज्य विकास ऋण (एसडीएल) बाजारों के बारे में महत्वपूर्ण शैलीगत तथ्य प्रस्तुत करती है, जिसमें राज्यों की देयता प्रोफ़ाइल (घाटे और ऋण), राज्य सरकार के बांडों का स्वामित्व पैटर्न, जारी किए गए बांड, मौजूदा और नए ऋण की लागत और एसडीएल की तरलता शामिल है।

पहचाने गए कुछ मुद्दे एसडीएल बाजार में तरलता, राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आधार पर उधार की लागत और केंद्रित एसडीएल उधार के बीच पर्याप्त भिन्नता की कमी के इर्द-गिर्द घूमते हैं। उपरोक्त मुद्दों के विश्लेषण के आधार पर, रिपोर्ट राज्य सरकार के ऋण बाजार में सुधार और भारत में राज्य प्रतिभूतियों के लिए अधिक कुशल और कार्यात्मक बाजार के लिए आवश्यक विनियामक ढांचे के लिए कुछ नीतिगत सुधारों का प्रस्ताव करती है ।

6. **ओडिशा में बाल संरक्षण की सार्वजनिक व्यय समीक्षा (अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023)**

प्रायोजक: यूनिसेफ

दल: लेखाचक्रवर्ती, अमनदीपकौर, जितेशयादवऔरबालामुरलीबी।

उद्देश्य: अध्ययन के ध्यान-केंद्रण में (i) बाल संरक्षण योजनाओं की सार्वजनिक व्यय समीक्षा (पीईआर) और (ii) बाल संरक्षण योजनाओं का राजकोषीय लक्ष्य विश्लेषण और बाल संरक्षण योजनाओं का पीईएफए (सार्वजनिक व्यय और वित्तीय उत्तरदायित्व) विश्लेषण शामिल है। अध्ययन ओडिशा के चयनित जिलों में बाल देखभाल संस्थानों की क्षेत्र-स्तरीय सार्वजनिक व्यय ट्रैकिंग, जवाबदेही और संस्थागत समीक्षा भी प्रदान करता है।

7. **राज्य स्तर पर स्पष्ट बजटीय सब्सिडी का युक्तिकरण (नवंबर 2023)**

प्रायोजक: नीति आयोग

दल: अमरनाथ एच.के., श्रीहरि नायडू ए., मिताली गुरदत्ता, किशन, आशीष राजन और रोहित दत्ता

उद्देश्य: हमने स्पष्ट सब्सिडी को परिभाषित किया और आठ चयनित राज्यों के लिए राज्य वित्त पर स्पष्ट सब्सिडी के बोझ का अनुमान लगाया।

8. राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के संदर्भ में स्पष्ट सब्सिडी और राजकोषीय स्थान को परिभाषित करना (18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक)

प्रायोजक: यूनाइटेड किंगडम सरकार का विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करता है।

दल: अमरनाथ एच.के., स्मृति बनती और मीना

उद्देश्य: भारत के स्थिर राजस्व और राज्य स्तर पर बढ़ते व्यय एक प्रमुख राजकोषीय चिंता रहे हैं। कल्याण व्यय और स्पष्ट सब्सिडी में वृद्धि हाल के दिनों में राज्य वित्त की बहस का मुद्दा है। भारत सरकार द्वारा अवसंरचना और पूंजीगत व्यय पर महत्वपूर्ण व्यय की आवश्यकता पर बल प्रदान किए जाने के साथ ही, प्रतिबद्ध व्यय, राजकोषीय स्थान और स्पष्ट सब्सिडी की अवधारणाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 'सब्सिडी' को हमेशा योजनाओं पर व्यय के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है या सरकारी लेखा प्रणाली में सहायता या अनुदान के रूप में दरकिनार कर दिया जाता है। सिकुड़ता राजकोषीय स्थान और कोविड-19 महामारी से प्रेरित कल्याण व्यय और स्पष्ट सब्सिडी ऐसे प्रमुख कारक हैं जो राज्यों के बिगड़ते सरकारी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह पत्र प्रतिबद्ध व्यय को संरचनात्मक तरीके से परिभाषित करने और स्पष्ट सब्सिडी को परिभाषित करने का प्रयास करता है ताकि समान व्यय को शामिल किया जा सके जो सब्सिडी की तरह हैं लेकिन सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं। समग्र विश्लेषण से पता चलता है कि जिन राज्यों में राजस्व घाटा है, उन्हें न केवल प्रतिबद्ध व्यय को सीमित करने के बारे में सोचना चाहिए बल्कि सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के बारे में भी विचार करना चाहिए। उधार के माध्यम से सब्सिडी और कल्याण व्यय का वित्तपोषण लंबे समय में संधारणीय नहीं है और इसके परिणामस्वरूप अवसंरचना पर व्यय में कमी आती है। इस प्रकार, राजकोषीय स्थान में सुधार करने और नि:शुल्क के रूप में सब्सिडी को तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है।

9. राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र की उधार आवश्यकताएं (18 सितंबर 2023 से 15 अप्रैल 2024 तक)

प०रायोजक: यूनाइटेड किंगडम सरकार का विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करता है।

दल: मनीष गुप्ता, मालविका महेश और एसकेएम अजहरुद्दीन

उद्देश्य: अध्ययन भारत में चुनिंदा राज्यों द्वारा कुल सार्वजनिक क्षेत्र उधार के अधिक व्यापक और यथार्थवादी आकलन के लिए डेटा एकत्र करने का एक तंत्र विकसित करने का प्रयास करता है। यह चयनित राज्यों द्वारा कुल सार्वजनिक क्षेत्र उधार का अनुमान भी प्रदान करता है। ऐसा करने में, यह इन राज्यों की ऑफ-बजट देनदारियों को निर्धारित करता है और उनके संबंधित एफआरबीएम अधिनियमों के उपबंधों के आलोक में उनके द्वारा प्रदान की गई गारंटियों की जांच करता है।

10. भारतीय राज्यों में राज्य वित्त आयोगों के कामकाज की समीक्षा और मूल्यांकन (2024 में पूर्ण)

प्रायोजक: यूनिसेफ इंडिया

दल: मनीष गुप्ता

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा करना और भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने में उनकी सिफारिशों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है। अध्ययन में देश के सभी राज्यों के एसएफसी की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्टों की जांच करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को धन और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण की स्थिति को और अधिक समझने के लिए, छह राज्यों (बिहार, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और तमिलनाडु) का क्षेत्र दौरा किया गया और सभी हितधारकों, अर्थात्, संबंधित

राज्य सरकार के विभागों, एसएफसी के अध्यक्षों और सदस्यों और ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के साथ बैठकें और चर्चाएँ की गईं।

चल रहे अध्ययन

केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए चल रहे अध्ययन

1. **उत्तराखंड राज्य के लिए सार्वजनिक व्यय और वित्तीय उत्तरदायित्व (पीईएफए) आकलन (अप्रैल 2023 – जून 2024)**

   प्रायोजक: उत्तराखंड सरकार

   दल: प्रताप रंजन जेना, दिनेश कुमार नायक और अभिषेक सिंह

   उद्देश्य: पीईएफए मूल्यांकन, प्रदर्शन को मापने के लिए मात्रात्मक संकेतकों का उपयोग करके सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएम) की ताकत और कमजोरियों का आकलन करने और उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन और स्कोरिंग पद्धति के साथ प्रमुख पीएफएम तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रदर्शन संकेतक, वर्तमान में कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में प्रवेश बिंदुओं सहित उचित भविष्य के सुधार एजेंडे की पहचान करने में सुविधा प्रदान करेंगे। इसलिए, पीईएफए मूल्यांकन उत्तराखंड सरकार को आगे के पीएफएम सुधारों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अगले स्तर की पहचान करने में मदद करेगा।

2. **कर संग्रह, राजस्व और विभिन्न अन्य मापदंडों पर मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन (मार्च 2024 - जारी)**

   प्रायोजक: मध्य प्रदेश सरकार

   दल: सच्चिदानंद मुखर्जी, शिवानी बडोला और विवेक जाधव

   उद्देश्य: इसमें हम इन शोध प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करेंगे - क) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कर आधार कैसे बढ़ाया जाए ? ; ख) जीएसटी में कर दक्षता कैसे सुधारी जाए ? ; और ग) जीएसटी के तहत कर संग्रह बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए?

3. **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और स्थानीय सरकार के वित्त पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना (2021 - जारी)**

   प्रायोजक: पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (पीडीयू-सीटीआरएफए), उत्तराखंड सरकार

   दल: मनीष गुप्ता

   उद्देश्य: परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और स्थानीय सरकार के वित्त पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना शामिल है

4. **कर्नाटक के जीएसडीपी में पद्धतिगत मुद्दे और आधार वर्ष परिवर्तन (नवंबर 2023 - जारी)**

   प्रायोजक: कर्नाटक सरकार

   दल: अमेय सप्रे

   उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के आकलन में पद्धतिगत और गणना संबंधी मुद्दों को उजागर करना है, विशेष रूप राष्ट्रीय खातों के आधार वर्ष को 2011-12 में संशोधित किए जाने के बाद से।

5. **चौथे राष्ट्रीय संचार, चौथे बीयूआर, प्रथम बीटीआर की तैयारी और सीबीआईटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अग्रिम लामबंदी (2023 - जारी)**

   प्रायोजक: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

   दल: सुरंजलि टंडन

   उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रवाह के प्रवाह को मापना और रिपोर्ट के वित्त अध्याय का मसौदा तैयार करना।

6. **भारत में किगाली संशोधन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीतिगत ढांचे और रणनीति का विकास (2023 - जारी)**

प्रायोजक: ओजोन प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार

दल: सुरंजलि टंडन, अर्चिता श्रीधर, रिधि वर्मा और ज्योत्सना चिक्कारा

उद्देश्य: ओजोन प्रकोष्ठ, एमओईएफ एंड सीसी और एनआईपीएफपी भारत में किगाली संशोधन के कार्यान्वयन के लिए रणनीति सहित एक राष्ट्रीय नीतिगत ढांचे के विकास से संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे। असाइनमेंट का उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के तहत अनुपालन दायित्वों और ओडीएस (ओजोन-घटाने वाले पदार्थ) फेज़-आउट के लिए भारत के देश कार्यक्रम में निहित सिद्धांतों पर विचार करते हुए एचएफसी (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन) फेज़-डाउन को लागू करने के लिए बिना औद्योगिक और आर्थिक विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए और उपभोक्ता और सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हुए एक नीतिगत ढांचा और रणनीति विकसित करना है।

7. **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-एनआईपीएफपी अनुसंधान कार्यक्रम, नवंबर 2022 (तीन वर्ष की अवधि के लिए)**

प्रायोजक: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार

दल: आर. कविता राव, मनीष गुप्ता, अमेय सप्रे, आकाश गुप्ता, नीति गुप्ता, सिराज येजदानी और सौम्या अग्रवाल

उद्देश्य: इस कार्यक्रम में भारत में शहरी वित्तपोषण और सेवा वितरण में अनुसंधान और नवाचारों का भंडार बनाने के लिए शहरी सार्वजनिक वित्त में अनुसंधान केंद्र (सीईआरयूपीएफ) की स्थापना करना शामिल है। कार्यक्रम के भाग के रूप में, वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा है वह है:1) खातों का विश्लेषण: शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के राजस्व और व्यय में रुझानों की झलक प्रदान करने के लिए आधार अध्ययन। वर्तमान में, 4,000 से अधिक यूएलबी के वित्त का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है;2) यूएलबी द्वारा बांड जारी करने पर स्थिति पत्र: यूएलबी द्वारा नगर निगम बांड जारी करने की स्थिति पर एक पत्र पर काम किया जा रहा है। यह पत्र बांड जारी करने के लिए विधायी और विनियामक ढांचे और नगर निगम बांड जारी करने वाले यूएलबी की वित्तीय स्थिति का दस्तावेजीकरण करता है। स्थानीय निकाय से संबंधित करों को जीएसटी में शामिल किए जाने की पृष्ठभूमि में, इस दस्तावेज में यूएलबी की कराधान शक्तियों, जीएसटी क्षतिपूर्ति और यूएलबी के समग्र राजस्व से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत किया गया है।

वित्त मंत्रालय के लिए चल रहे अध्ययन

1. **योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर बार-बार होने वाले चुनावों का प्रभाव (जनवरी 2023 – फरवरी 2024)**

प्रायोजक: व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, अजय नारायण झा, मालविका महेश और रोली कुकरेजा

उद्देश्य: लगातार चुनाव किस हद तक परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं? क्या देश के लिए संभावित "नुकसान" का पता लगाने के लिए इनका परिमाणन किया जा सकता है? अध्ययन का उद्देश्य चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर लगातार होने वाले चुनावों के प्रभाव का आकलन करना है। एम.सी.सी. के कार्यान्वयन से नीतिगत कार्रवाइयों और किसी भी प्रकार के नए या नए व्यय पर रोक लगाने पर निर्विवाद प्रभाव पड़ता है। साथ ही, चुनाव ड्यूटी के लिए बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने से सामान्य राजस्व संग्रह और चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन दोनों पर असर पड़ता है। आसन्न चुनावी कैलेंडर सत्तारूढ़ व्यवस्था को मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों, योजनाओं और सब्सिडी और/या कर छूट या रियायतों की घोषणा करने के लिए भी लुभा सकता है। ये कार्यक्रम चुनावी वर्ष में बजटीय घोषणाओं या बजट के बाद की घोषणाओं का हिस्सा हो सकते हैं। इनके लिए संसाधन कुछ अन्य व्यय आवंटन में निहित कटौती करके पाए जा सकते हैं। आसन्न चुनावी कैलेंडर से चुने हुए क्षेत्रों और एजेंटों के पक्ष में संबंधित आउटपुट या परिणामों से मेल न खाने वाले व्यय की होड़ लग सकती है।

2. **2017-18 से 2022-23 के लिए भारत सरकार के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण (ईएफसी) बजट के लिए मैनुअल तैयार करना** (**अक्टूबर** 2022 – **मई** 2024) *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: अमरनाथ एच.के., श्रीहरि नायडू ए., आशीष राज और रोहित दत्ता

उद्देश्य: वर्ष 2017-18 से 2022-23 (बीई) के लिए भारत सरकार के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण (ईएफसी) बजट के लिए टेम्पलेट और मैनुअल का संशोधन।

3. **राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की तृतीय-पक्ष पारदर्शिता संपरीक्षा: 2022- 23 (2023-24)**

प्रायोजक: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (डीओआर) ने एनआईपीएफपी को यह कार्य सौंपा है (कल्याणार्थ)

दल: सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला

उद्देश्य: राजस्व विभाग (डीओआर) ने एनआईपीएफपी को विभाग के अंतर्गत 78 सार्वजनिक प्राधिकरणों की तृतीय-पक्ष पारदर्शिता संपरीक्षा करने के लिए कहा है। अब तक, एनआईपीएफपी ने 2023-24 के लिए यह कार्यभार संभाला है।

संस्थाओ/संगठनों के लिए चल रहे अध्ययन

1. **कर नीति और अनुपालन के प्रति दृष्टिकोण का आकलन (जनवरी 2023 - दिसंबर 2024)**

प्रायोजक: स्वयं-प्रारंभित

दल: आर.कविता राव

उद्देश्य: करदाताओं की धारणाओं से जीडीपी अनुपात में कर वृद्धि के प्रश्न पर विचार करते हुए, अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या नागरिकों द्वारा कर अनुपालन के बारे में भारत में लोगों की धारणाएँ एक ओर निष्पक्षता और अनुपालन में आसानी के बारे में उनकी धारणाओं से संबंधित हैं, और दूसरी ओर क्या ये सरकारी खर्च से कथित लाभों से संबंधित हैं। अध्ययन में विभिन्न पृष्ठभूमि के 150-200 व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ताकि यह पता लगाया जा सके कि धारणाओं में अंतर है या नहीं। इस अध्ययन को प्रायोगिक माना जा सकता है जिसे बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण में विस्तारित किया जा सकता है, यदि प्रारंभिक परिणाम दिलचस्प पाए जाते हैं।

2. **ब्याज दर की अवधि संरचना और आरबीआई मौद्रिक नीति रुख (जनवरी 2023 – दिसंबर 2024)**

प्रायोजक: स्व-प्रारंभिक

दल: लेखा चक्रवर्ती और नेहला के शिहाब

उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य आरबीआई की नई मौद्रिक नीति के रुख की पृष्ठभूमि में भारत में ब्याज दरों की अवधि संरचना की जांच करना है।

3. **अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण (आईजीएफटी) के निर्धारकों का विश्लेषण (जनवरी 2024 – सितंबर2024)**

प्रायोजक: स्व-प्रारंभिक

दल: लेखा चक्रवर्ती

उद्देश्य: परियोजना अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण के निर्धारकों की जांच करती है तथा समानता और दक्षता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उल्लेखनीयपरिवर्तियों को एकीकृत करके प्रति-तथ्यात्मक अभ्यासों का सुझाव देती है।

4. **पृथक भारतीय विनिर्माण उद्योगों के लिए प्रभावी कर दरों के निर्धारक (अगस्त 2023 – मई 2024)**

प्रायोजक: स्व-प्रारंभिक

दल: आर. कविता राव और एस.के.एम. अजहरुद्दीन

उद्देश्य: हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित दो अलग-अलग डेटासेट मैप करने का प्रस्ताव करते हैं: राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी से प्राप्त सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और प्राप्ति बजट से निकाले गए कॉर्पोरेट आयकर डेटा। हमारा उद्देश्य अलग-अलग स्तर के विश्लेषण को लागू करकेअलग-अलग विनिर्माण क्षेत्रों में प्रभावी कर दरों को आकार देने वाले कारकों को उजागर करना है। अध्ययन में प्रभावी कर दरों और उद्योग के आकार के बीच एक प्रतिलोमित-यू संबंध पाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह वैधानिक दर, शासन सूचकांक और वैकल्पिक कर व्यवस्था जैसे अन्य निर्धारकों की पहचान करता है।

5. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धन के उपयोग में सुधार करने में एकल नोडल खाते (एसएनए) की भूमिका को समझना (नवंबर2022 – अगस्त2024)**

प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)

दल: मीता चौधरी, प्रीतम दत्ता और नित्या चुटानी

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बजट निष्पादन में सुधार करने में एकल नोडल खाते (एसएनए) की भूमिका की जांच करना है। इस मुद्दे की जांच दो राज्यों - बिहार और ओडिशा में कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों (राज्य, जिला, ब्लॉक) पर की जा रही है।

6. **कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध के दोहरे झटकों के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की गतिशीलता (अगस्त 2023 - अगस्त 2024)**

प्रायोजक: राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली

दल: रुद्रानी भट्टाचार्य और शेषाद्री बनर्जी (आरबीआई)

उद्देश्य: कोविड-19 महामारी जैसे 'सदी में एक बार' आने वाले झटके की शुरुआत के साथ, भारत को विश्व का सर्वाधिक गहन संकुचन झेलना पड़ा। जैसे ही अर्थव्यवस्था पारंपरिक और अपरंपरागत राजकोषीय और मौद्रिक नीति उपायों के समर्थन से महामारी से उबरने लगी, यूक्रेन में युद्ध के प्रकोप ने स्थिति को उलट दिया। इसने विश्व अर्थव्यवस्था के प्रक्षेपवक्र को काफी हद तक बदल दिया है। अंतरराष्ट्रीय पण्यों की कीमतों, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमत में काफी उछाल आया। वैश्विक और घरेलू स्तर पर, आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बना, जिससे इनपुट लागत में वृद्धि हुई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ा। तेजी से बदलते वृहद आर्थिक परिवेश की इस पृष्ठभूमि में, हम यह जांच करते हैं कि क्या मुद्रास्फीति की गतिशीलता ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया है। न्यू कीनेसियन ढांचे का उपयोग करते हुए, हम जांच करते हैं कि क्या मुद्रास्फीति प्रक्रिया की विशेषताओं, जैसे नाममात्र घर्षण, विगत मुद्रास्फीति के लिए सूचकांक और मुद्रास्फीति के दीर्घकालिक स्तर में संरचनात्मक बदलाव आया है; और यदि ऐसा है, तो इसके संभावित व्यापक आर्थिक परिणाम क्या हैं। सबसे पहले, हम महामारी से पूर्व और बाद की अवधि के बीच हमारे सीपीआई बास्केट के मूल्य डेटा में अनुभवजन्य नियमितताओं की तुलना करते हैं। इसके बाद, हम प्रासंगिक दृष्टांतों के साथ एक प्रोटोटाइप डीएसजीई मॉडल का उपयोग करके शैलीबद्ध तथ्यों के संभावित परिणामों का पता लगाते हैं।

7. **सामाजिक व्यय और व्यापक अर्थव्यवस्था: भारत के लिए एक नीति सिमुलेशन मॉडल (अक्टूबर 2023 - दिसंबर 2024)**

प्रायोजक: एनआईपीएफपी अनुदान

दल: सुकन्या बोस और सैकत बनर्जी

उद्देश्य: वर्तमान अनुसंधान भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक मैक्रोइकॉनोमिक मॉडल के माध्यम से सामाजिक व्यय और मैक्रोइकॉनोमिक परिणामों के बीच संबंधों की खोज करता है। इसका मूल मॉडल कीन्स-कालेकी परंपरा में है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ संरचनात्मक विशेषताएं जोड़ी गई हैं। सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय विकास को मानव विकास से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मानव विकास का सामान्य विकास पर प्रतिपुष्टि प्रभाव होता है।

8. **स्कूल शिक्षा में लिंग बजट (दिसंबर 2023 – सितंबर 2024)**

प्रायोजक: राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन (एनसीई)

दल: सुकन्या बोस, मोहम्मद यासीन (आईआईएचएस और एनआईपीएफपी), अर्चना (एनसीई) और नूपुर (एनसीई)

उद्देश्य: अध्ययन लिंग बजट की नौकरशाही और एकाकी प्रक्रिया की ओर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है। दिल्ली में माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में, इस सहभागी शोध ने कामकाजी वर्ग के परिवारों की महिला छात्राओं को उनके अनुभवों, प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए सहयोगात्मक रूप से एक मंच बनाने के लिए एकजुट किया है। इन चर्चाओं से विकसितछात्र प्रतिक्रिया से परिष्कृत और छात्रों द्वारा प्रशासित एक सर्वेक्षण प्रश्नावलीअनुसंधान की मुख्य चर्चाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अनुसंधान में कक्षा के आकार, शिक्षकों की क्षमता, छात्रवृत्ति, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसे कई मुद्दों को शामिल किया गया है, और महत्वपूर्ण डेटा और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की गई हैं, जिनके आधार पर कार्योत्तर लेखाकरण अभ्यास के स्थान पर लिंग बजट को आधार बनाया जा सकता है। इससे प्रभावित होकर, अध्ययन लिंग बजटिंग के लिए अधिक सहभागी होने की आवश्यकता और दायरे का प्रस्ताव करता है और लिंग बजटिंग और सहभागी बजटिंग के बीच तालमेल के लिए चर्चा का विस्तार करता है।

9. भारत में राज्य वित्त के मुद्दों पर पुनर्विचार: कतिपय अनुभवजन्य जांच (नवंबर 2021-चल रही)

प्रायोजक: स्व-प्रारंभिक

दल: दिनेश कुमार नायक और भबेश हजारिका

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य राज्य वित्त पर विभिन्न मुद्दों और निहितार्थों का विश्लेषण करना है।

10. सतत विकास में सार्वजनिक व्यय, शासन और क्षेत्रीय असमानता: असम में जिला-स्तरीय विश्लेषण। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित (अप्रैल 2022 - जून 2024)

प्रायोजक: आईसीएसएसआर, नई दिल्ली

दल: भावेश हजारिका और अंकित सिंह

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य जिलों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि के विचलन को स्पष्ट करने में सार्वजनिक व्यय की भूमिका और शासन की गुणवत्ता का विश्लेषण करना है, जिसकी नीतिगत उपायों के लिए महत्वपूर्ण विवक्षाएं हैं।

11. भारत में जेंडर बजटिंग के आकलन के लिए एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (जनवरी 2024 - चल रही)

प्रायोजक: स्व-आरंभिक

दल:भाबेश हजारिका

उद्देश्य : भारत में लिंग बजट के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियांऔर चुनौतियाँ शामिल हैं। भारत ने 2005-06 में लिंग-संवेदनशील आवंटन का पता लगाने के लिए लिंग बजट विवरण (जीबीएस) प्रस्तुत करते हुए औपचारिक रूप से लिंग बजट नीति को अपनाया। भारत में लिंग बजट की स्थिति निरंतर प्रगति और संस्थागतकरण को दर्शाती है। भारतीय संदर्भ में लिंग बजट का आकलन करने की दिशा में पहले कदम के रूप में, यह अध्ययन लिंग आधारित दृष्टिकोण से सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है।

12. भारतीय राज्यों का आर्थिक और सामाजिक प्रदर्शन अलग-अलग क्यों है ? (जुलाई 2022 - चल रही)

प्रायोजक: स्व-प्रारंभिक

दल: रुद्रानी भट्टाचार्य, सुदीप्तो मुंडले (सीडीएस) और दिनेश कुमार नायक

उद्देश्य: आर्थिक विकास और मानव विकास के मामले में भारतीय राज्यों में काफी विविधता है। यह अध्ययन इस विविधता को स्पष्ट करने वाले कारकों की पहचान करने का प्रयास करता है जैसे प्रारंभिक स्थिति, पूंजी स्टॉक, भौतिक अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना की गुणवत्ता और स्तर और शासन की गुणवत्ता।

13. राजकोषीय प्रभुत्व और संप्रभु ऋण प्रबंधन (2023 - चल रही)

प्रायोजक: स्व-प्रारंभिक

दल: पियाली दास, चेतन घाट और सुभादीप हलधर

उद्देश्य: यह पत्र संप्रभु ऋण और पोर्टफोलियो प्रबंधन के प्रभाव को उजागर करने में मदद करता है।

14. अमेरिका के लिए राजकोषीय कुशन का परिमाणीकरण: 1960-2013 (2023 - चल रही)

प्रायोजक: स्व-प्रेरित

दल: पियाली दास

उद्देश्य: यह पत्र बॉन्ड मूल्य परिवर्तन और संप्रभु ऋण पर औचक मुद्रास्फीति द्वारा निभाई गई भूमिका को समझने में मदद कर सकता है।

15. यूनाइटेड किंगडम के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात का विघटन: 1984-2009 (2023 - चल रही)

प्रायोजक:स्व-प्रेरित

दल: पियाली दास

उद्देश्य: यह पत्र यह समझने में मदद कर सकता है कि नाममात्र ब्याज दर और प्राथमिक घाटे ने यूनाइटेड किंगडम के लिए ऋण की स्थिति को प्रभावित करने में कैसे भूमिका निभाई। साथ ही, यह पत्र यूके में ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में संप्रभु ऋण पर चर्चा करता है। यह देश का अनुभव (यूके से) भारत को सूचित करने में मदद कर सकता है क्योंकि यह एक उच्च संप्रभु ऋण व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

आरंभ की गईं नई परियोजनाएं

केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए नई परियोजनाएं

1. **स्वयं के स्रोत से राजस्व सृजन के लिए व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी (31 मार्च - चल रही)**

   प्रायोजक:पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

   दल: अमरनाथ एच.के., आकांक्षा श्रवण, सीमा मौर्य, मयूराक्षी मित्रा और स्मृति बनती

   उद्देश्य: राज्य पंचायती राज अधिनियमों का सारांश तैयार करना और स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के मार्ग और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के क्रियाकलाप का मानचित्रण करना। कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना-सह-रोड मैप तैयार करना (जनशक्ति, प्रशिक्षण आवश्यकता, वित्तीय विवक्षा और राज्य पंचायती राज अधिनियमों में आवश्यक परिवर्तनों के संदर्भ में); पंचायत राजस्व बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक और टिकाऊ वित्तीय मॉडल का प्रस्ताव करना और; ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर राजस्व के उच्चतर संग्रहण के लिए संस्थागत सुधार और क्षमता निर्माण मॉड्यूल का सुझाव देना।

2. **त्रिपुरा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के संभावित उपायों पर अध्ययन (मार्च 2024 - चल रही)**

   प्रायोजक: त्रिपुरा सरकार

   दल: सच्चिदानंद मुखर्जी, आर. कविता राव, शिवानी बडोला और विवेक जाधव

   उद्देश्य: यह अध्ययन त्रिपुरा सरकार की अतिरिक्त राजस्व जुटाने की संभावनाओं का पता लगाएगा। अध्ययन का मुख्य ध्यान राज्य के अपने कर राजस्व पर होगा। इस अध्ययन में राज्य जीएसटी, राज्य बिक्री कर/वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर और यात्री और माल कर शामिल हैं।

3. **त्रिपुरा में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का पुनर्गठन (फरवरी 2024 – सितंबर 2024)**

   प्रायोजक: त्रिपुरा सरकार

   दल: रुद्रानी भट्टाचार्य और आर. कविता राव

   उद्देश्य: यह अध्ययन त्रिपुरा के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के प्रदर्शन को सुधारने/पुनर्जीवित करने के लिए रणनीतियों की पहचान करने के लिए किया गया है, जिसमें उत्पादन/उत्पादों की प्रकृति, वित्तीय स्थिति और संभार-तंत्र संबंधी मुद्दों में क्षेत्रीय स्तर पर भिन्नता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वित्त मंत्रालय के लिए नई परियोजनाएं

1. **एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम (अप्रैल 2024 – मार्च 2026)**

   प०रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

   दल: आर कविता राव, राधिका पांडे, रचना शर्मा, आशिम कपूर, मधुर मेहता, उत्सव सक्सेना, आनंदिता गुप्ता, यशोवर्धन चतुर्वेदी, निपुण वर्मन, मनल शाह, अभिजीत सिंह, निकिता सिंह और एस भुवनकौशिक

   उद्देश्य: क्रिप्टो परिसंपत्तियों, वित्तीय भेद्यता, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) के विनियामक ढांचे, जलवायु जोखिम प्रकटीकरण ढांचे, वित्तीय बाजार स्थिरता पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रभाव, उपभोक्ता व्यवहार सेवाओं, अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) समूह और यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) और भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के साथ सहयोग को मजबूत करने सहित मुद्दों से संबंधित विभाग को अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना।

अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए नई परियोजनाएं

1. **जेंडेर और माइक्रोइक्रॉमिक्स (मई 2024)**
   प्रायोजक : यूएन विमेन
   दल: लेखा चक्रवर्ती
   उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को जेंडेर और माइक्रो इक्रॉमिक्स पर प्रशिक्षण देना है, जिसमें वित्तीय और मौद्रिक नीतियां शामिल हैं तथा इसमें संयुक्त राष्ट्र बैंकॉक और ऑनलाइन में असंदत्त देखभाल अर्थव्यवस्था का मापन भी शामिल है।

2. **क्या भारत में मौद्रिक नीति संचरण का अपेक्षित चैनल मौजूद है? पारंपरिक बनाम अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों की भूमिका (अप्रैल 2024 – चल रही)**
   प्रायोजक: स्व-प्रारंभिक
   दल: रुद्रानी भट्टाचार्य और शेषाद्री बनर्जी (आरबीआई)
   उद्देश्य: वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच 20 फरवरी 2015 को हुए समझौते के माध्यम से भारत को औपचारिक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (आईटी) व्यवस्था में आए लगभग एक दशक हो गया है, जिसमें मध्यम अवधि में +/−2 प्रतिशत के बैंड के साथ 4 प्रतिशत की सीपीआई मुद्रास्फीति प्राप्त करने की प्रतिबद्धता है। वैचारिक रूप से, यह व्यवस्था इस नियम-आधारित मौद्रिक नीति व्यवस्था के तहत, अर्थव्यवस्था के वास्तविक पक्ष को मौद्रिक नीति के आघात को प्रेषित करने के लिए दूरदर्शी अपेक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रास्फीति के परिदृश्य में, जब केंद्रीय बैंक आईटी व्यवस्था के तहत अपनी नीति दर में वृद्धि करता है, तो परिवार और फर्म यह जानते हैं कि केंद्रीय बैंक की कार्रवाई निकट भविष्य में मुद्रास्फीति दर को लक्ष्य पर स्थिर कर देगी, साथ ही अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के बारे में उनकी भविष्य की धारणा को भी कम करती है, जिससे वर्तमान मुद्रास्फीति दर कम हो जाती है (गैली और गर्टलर, 2007; गैली, 2008)। इसलिए आईटी व्यवस्था की सफलता एक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति संचरण (एमपीटी) के अपेक्षा चैनल के अस्तित्व पर निर्भर करती है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या पारंपरिक और अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरणों के तहत मौद्रिक नीति आघात, अपेक्षा चैनल के माध्यम से अर्थव्यवस्था के वास्तविक पक्ष में संचारित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की सर्वेक्षण-आधारित घरेलू मुद्रास्फीति अपेक्षा हमारे विश्लेषण में इस चैनल को कैप्चर करती है।

3. **भारत में राज्य वित्त के साथ कारक विश्लेषण (मार्च 2024 - चल रही)**
   प्रायोजक: स्व-प्रारंभिक
   दल: पियाली दास और पियाली बनर्जी
   उद्देश्य: कुछ भारतीय राज्य उच्च ऋण-जीएसडीपी अनुपात का सामना कर रहे हैं और इस संबंध में समय श्रृंखला विश्लेषण का उपयोग करते हुए यह पत्र भारत में राज्यों की ऋण स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने का प्रयास करता है।

कार्यशालाएं, बैठकें और सम्मेलन

क्रम सं.	शीर्षक	आयोजक	तारीख और स्थान
1	'योजना में बालकों की प्राथमिकताओं को मुख्यधारा में लाना – राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के हस्तांतरण फार्मूले में बालकों से संबंधित संकेतकों को एकीकृत करना' विषय पर एक-दिवसीय परामर्श कार्यशाला	यूनिसेफ इंडिया द्वारा एनआईपीएफपी और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के सहयोग से समन्वयक: मनीष गुप्ता	8 अगस्त 2023 भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली
2	भारत कैसी प्रगति कर रहा है ? मध्य-वर्षीय मैक्रो इकॉनॉमिक्स समीक्षा' पर एक-दिवसीय चर्चा	एनआईपीएफपी समन्वयक: रुद्राणीभट्टाचार्य	11 अगस्त 2023 एनआईपीएफपी
3	'रणनीतिक खुलापन? सीबीएएम के समावेशी कार्यान्वयन की दिशा में' विषय पर आधे दिन का क्लोजड़ हाइब्रिड सम्मेलन	एनआईपीएफपी और एफईपीएस (फाउंडेशन फॉर यूरोपियन प्रोग्रेसिव स्टडीज़) समन्वयक : सुरांजली टंडन	12 अक्तूबर 2023 ऑनलाइन
4	'राज्य फोरम 2023: राज्य वित्त में विचारों और नवाचार को साझा करना' के पहले संस्करण में दो-दिवसीय सम्मेलन	एनआईपीएफपी दवारा विश्व बैंक की भागीदारी में समन्वयक : आर कविता राव	2-3 नवम्बर 2023 एनआईपीएफपी
5	'बेहतर परिणामों के लिए स्वास्थ्य वित्तपोषण का केंद्र-राज्य संरेखण' पर दो-दिवसीय वार्ता	एनआईपीएफपी समन्वयक: मीता चौधरी	23-24 नवंबर 2023 एनआईपीएफपी
6	निरंतर ट्रस्ट की कार्यकारी निदेशक अर्चना द्विवेदी द्वारा 'लिंग संवेदनशीलता' पर आधे दिन का सत्र	एनआईपीएफपी समन्वयक : आर कविता राव	20 दिसंबर 2023 एनआईपीएफपी

प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	शीर्षक	दिन और तारीख	स्थान	कार्यक्रम समन्वयक
1	अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए' राजकोषीय नीति – प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	24-26 मई 2023	एनआईपीएफपी (ऑनलाइन)	मुकेश कुमार आनंद
2	विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के लिए' सार्वजनिक वित्त' पर 15वां पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम।	5-16 जून 2023	एनआईपीएफपी	अमय सप्रा
3	असम सरकार के वित्त विभाग के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के सेवारत अधिकारियों के लिए 'जीएसडीपी अनुमान से संबंधित मुद्दे और ग्रीन बजट की तैयारी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	26-28 जुलाई 2023	गुवाहाटी, असम	अमय सप्रा
4	भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	18-22 सितंबर 2023	एनआईपीएफपी	मालविका महेश
5	बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख जिला बैंक प्रबंधकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	20-24 नवंबर 2023	एनआईपीएफपी	अमय सप्रा और राधिका पांडे
6	अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से' राजकोषीय नीति – प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	4-8 दिसंबर 2023	एनआईपीएफपी	मुकेश कुमार आनंद
7	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस), एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।	11-22 दिसंबर 2023	एनआईपीएफपी	अमय सप्रा
8	मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवाओं (एमएफए) अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करने' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	08-12 जनवरी 2024	एनआईपीएफपी	प्रताप रंजन जेना
क्र. सं.	शीर्षक	दिन और तारीख	स्थान	कार्यक्रम समन्वयक

9	बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख जिला बैंक प्रबंधकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	15-19 जनवरी 2024	एनआईपीएफपी	अमय सप्रा और राधिका पांडे

प्रकाशन और संचार

जुलाई 2022 से संस्थान ने द्वि-वार्षिक न्यूज़लेटर प्रकाशित करने के स्थान पर प्रत्येक दो माह में एक न्यूजलेटर प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। इन न्यूज़लेटरों द्वारा परियोजनाओं, संकाय क्रियाकलापों और घटनाओं पर अद्यतन जानकारी प्रदान की गई।

एनआईपीएफपी के अनुसंधान संकाय और उनके सहयोगियों द्वारा लिखे गए कुल 12 कार्यकारी पत्र एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे। रिपोर्ट के वर्ष में विभिन्न विषयों पर आधारित कुल 17 ब्लॉग लेख प्रकाशित किए गए। ब्लॉग http://nipfp.org.in/blog/ पर उपलब्ध है। प्रकाशन इकाई संस्थान की वेबसाइट http://www.nipfp.org.in को नियमित रूप से अद्यतन बनाने का कार्य भी करती है।

ट्विटर पर एनआईपीएफपी के सोशल मीडिया अकाउंट, @nipfp.org का उपयोग इसके शोध कार्य और आयोजनों की जानकारी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति के क्षेत्रों में प्रचारित-प्रसारित करने के लिए प्रभावी ढंग से किया गया था।

संस्थान के प्रसार-प्रसार प्रयासों के भाग के रूप में, अकादमिक पत्र वेबसाइट अपडेटों और ईमेलर्स के माध्यम से हितधारकों के बीच व्यापक रूप से वितरित किए गए थे। *(एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्रों की सूची के लिए अनुलग्नक II, मूल्य प्रकाशनों के लिए अनुलग्नक V और संकाय-प्रकाशित सामग्री के लिए अनुलग्नक VI देखें)।*

पुस्तकालय और सूचना केंद्र

एनआईपीएफपी पुस्तकालय और सूचना केंद्र लोक वित्त और नीति के क्षेत्र में एक शोध पुस्तकालय के रूप में विकसित है जिसमें लोक वित्त;राजकोषीय नीति; सूक्ष्म और वृहद अर्थशास्त्र; उद्योग अध्ययन; योजना और विकास; आर्थिक सिद्धांत और कार्यप्रणाली; भारतीय अर्थव्यवस्था; राजनीतिक अर्थव्यवस्था; पर्यावरणीय और प्राकृतिक अर्थशास्त्र; शहरी अर्थशास्त्र और शहरी वित्त; स्वास्थ्य अर्थशास्त्र; तथा संघवाद और विकेंद्रीकरण पर समृद्ध संसाधन सामग्री उपलब्ध है।

पुस्तकालय आवश्यक अवसंरचना के साथ तीन तलों में फैला हुआ है। भूतल पर स्थित विशाल पाठक क्षेत्र लैपटॉप और वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ पाठकों को वाचन सुविधाएं प्रदान करता है। पुस्तकालय पूर्णत; स्वचालित है तथा इसके कार्यकरण और सेवाओं के सभी परिचालन पहलुओं को कोहा-ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर पैकेज का उपयोग करते हुए कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

पुस्तकालय सभी कार्यदिवसों पर प्रात: 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक और एक छोड़कर दूसरे शनिवार को प्रात: 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक खुला रहता है।

पुस्तकालय संग्रहण

पुस्तकालय में 66,466 से अधिक पुस्तकें और अन्य दस्तावेज़ हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, पुस्तकालय ने अपने संग्रह में 385 नए दस्तावेज़ (पुस्तकें, कार्यकारी पत्र और जर्नलों के जिल्दबंद खंड) शामिल किए हैं, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही स्तर की सोसाइटियों, अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के प्रकाशनों का एक अत्यंत व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है।

पुस्तकालय ने प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशनों की ई-सदस्यता भी ग्रहण की है जैसे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फिस्कल डॉक्यूमेंटेशन (आईबीएफडी), इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैन्स (आईआईपीएफ) और सेंटर फॉर इकनॉमिक पॉलिसी रिसर्च। इस सदस्यता के माध्यम से, संस्थान ने एनआईपीएफपी संकाय और शोधकर्ताओं को ई-जर्नल्स, ई-बुक्स, आदि की सुविधा प्रदान की है।

जर्नल

पुस्तकालय निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों, अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता जर्नलों, डेटाबेस जर्नलों और अन्य ऑनलाइन जर्नलों की सदस्यता लेता है/प्राप्त करता है और उनका रखरखाव करता है।

विवरण	कुल संख्या
अंतर्राष्ट्रीय जर्नल	32
राष्ट्रीय जर्नल	41
पत्रिकाएं	14
निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सदस्यताओं के अंतर्गत जर्नल: 1) अमेरिकन इकॉनॉमिक्स एसोसिएशन 2) अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3)इंस्टिट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीज़ 4)इंटर्नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस	12
निम्नलिखित ऑनलाइन डेटाबेसों के अंतर्गत जर्नल: 1) साइंस डाइरेक्ट : इकॉनॉमिक्स, इकॉनॉमीट्रिक्स एंड फाइनेंस बंडल 2) ओयूपी ऑनलाइन इकॉनॉमिक्स जर्नल बंडल कलेक्शन 3) जेएसटीओआर (बिजनेस कलेक्शन I एवं II) 4) इकोलिट विथ फुल टेक्स्ट वर्जन 5) दि स्टाटा जर्नल	3418

समाचारपत्र और पत्रिकाएं

क्र. सं.	राष्ट्रीय समाचारपत्र	प्रिंट/अनलाइन
1.	*बिजनेस लाइन*	प्रिंट + ऑनलाइन
2.	*बिजनेस स्टैंडर्ड*	प्रिंट + ऑनलाइन
3.	*दि इकॉनॉमिक टाइम्स*	प्रिंट + ऑनलाइन
4.	*एम्प्लॉयमेंट न्यूज़*	प्रिंट
5.	*दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस*	प्रिंट
6.	*दि इंडियन एक्सप्रेस*	प्रिंट
7.	*मिंट*	प्रिंट + ऑनलाइन
8.	*नवभारत टाइम्स (हिंदी)*	प्रिंट
9.	*दि टेलीग्राफ (कोलकाता संस्करण)*	प्रिंट
10.	*दि हिंदू*	ऑनलाइन
11.	*दि हिंदुस्तान टाइम्स*	प्रिंट
12.	*दि स्टेटमैन*	प्रिंट
13.	*दि टाइम्स ऑफ इंडिया*	प्रिंट + ऑनलाइन
	अंतर्राष्ट्रीय समाचारपत्र	
1.	*फाइनेंशियल टाइम्स*	ऑनलाइन

ई-संसाधन

ई-जर्नल डेटाबेस

क्र. सं.	डेटाबेस का नाम	वेबलिंक	पहुंच का माध्यम
1.	ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन इकॉनॉमिक जर्नल	http://www.oxfordjournals.org	आईपी-आधारित
2.	जेएसटीओआर (बिजनेस कलेक्शन I एवं II)	http://www.jstor.org	आईपी-आधारित
3.	एल्सेवियर साइंस जर्नल : इकॉनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट	http://www.sciencedirect.com	आईपी-आधारित
4.	इकोनलिट विद फुल टेक्स्ट	http://www.search.ebscohost.com	आईपी-आधारित

ई-डेटाबेस

क्र. सं.	डेटाबेस का नाम	वेबलिंक	पहुंच का माध्यम
1.	ओईसीडी कराधान आई-पुस्तकालय	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी-आधारित
2.	ओईसीडी अर्थशास्त्र आई-पुस्तकालय	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी-आधारित
3.	ओईसीडी शासन आई-पुस्तकालय	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी-आधारित
4.	आईबीएफडी इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन	http://www.ibfd.org	(चुनिंदा प्रयोक्ताओं के लिए)

क्र. सं.	डेटाबेस का नाम	वेबलिंक	पहुंच का माध्यम
5.	आईएमएफ ई-पुस्तकालय	http://www.elibrary.imf.org	आईपी-आधारित
6.	दि स्टाटा जर्नल	http://www.stata-journal.com	पीडीएफ उपलब्ध
7.	ईपीडब्ल्यूआरएफ इंडिया टाइम सीरीज	http://www.epwrfits.in	आईपी-आधारित
8.	सीईपीआर (चर्चा पत्र)	http://www.cepr.org	(चुनिंदा प्रयोक्ताओं के लिए)
9.	अंतर्राष्ट्रीय कराधान	http://www.internationaltaxation.taxmann.com	(चुनिंदा प्रयोक्ताओं के लिए) यूजर आईडी/ पासवर्ड आधारित पहुंच

कार्पोरेट डेटाबेस

क्र. सं.	डेटाबेस का नाम	वेबलिंक	पहुंच का माध्यम
1.	सीएमआईई: इकॉनॉमिक आउटलुक	http://www.economicoutlook.cmie.com	आईपी-आधारित
2.	सीएमआईई: प्रोवेसआईक्यू	http://www.prowess.cmie.com	आईपी-आधारित
3.	सीएमआईई: केपेक्स	http://www.capex.cmie.com	आईपी-आधारित

ई-पुस्तक डेटाबेस

क्र.सं.	डेटाबेस का नाम	वेबलिंक	पहुंच का माध्यम
1.	एडवर्ड एलगर ई-बुक्स	https://www.elgaronline.com/browse?access=user level=parent	आईपी-आधारित
2.	स्प्रिंगेर ई-बुक्स सबजेक्ट बंडल ऑन इकॉनॉमिक्स	http://www.link.springer.com	आईपी-आधारित

वर्तमान जागरूकता सेवाएं

पुस्तकालय में प्राप्त सभी नए दस्तावेज़, लेख और समाचारपत्र लेख नियमित रूप से डेटाबेस में जोड़े जा रहे हैं और निम्नलिखित वर्तमान जागरूकता बुलेटिन के रूप में जारी किए जा रहे हैं:

- न्यूजपेपर आर्टिकल एलर्ट सेवा (समाचारपत्र कतरनों के नवीनतम संस्करण)
- बुक एलर्ट सेवा (पुस्तकों के नवीनतम संस्करण)
- बजट पूर्व और पश्चात विशेष बुलेटिन (बजट के पहले और बाद में संबंधित समाचारों और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों के विचारों का बुलेटिन)
- नवीनतम विषय-वस्तु सेवा (पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं की विषय-वस्तु के पृष्ठों के लिए मासिक बुलेटिन)
- डीस्पेस रिपोजिटरी (इस रिपोजिटरी पर समाचारपत्र के लेख अपलोड किए जाते हैं, जिन्हें इस लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: http://192.100.100.11:8080/jspui/)

इसके अलावा, पुस्तकालय सभी संकाय सदस्यों और शोध कर्मियों को ग्रंथसूची सेवा और संदर्भ सेवा भी प्रदान करता है।

संसाधन साझाकरण

एनआईपीएफपी पुस्तकालय व्यापक संसाधन साझाकरण और दस्तावेज़ वितरण सेवा के लिए डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (डेलनेट) के साथ सदस्यता बनाए रखता है। वर्ष के दौरान, पुस्तकालय ने विभिन्न प्रतिष्ठित पुस्तकालयों से तीनदस्तावेज़ उधार लिए और अंतरपुस्तकालय संसाधनों के व्यापक प्रसार के लिए समान प्रतिष्ठित पुस्तकालयों को 20दस्तावेज़ उधार दिए। वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 674प्रयोक्ताओं ने पुस्तकालय का दौरा किया और वे इसके समृद्ध संसाधनों से लाभान्वित हुए।

आरईपीईसी (अर्थशास्त्र में अनुसंधान पत्र)

आरईपीईसी अर्थशास्त्र और संबंधित विज्ञान में अनुसंधान के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए 103 देशों में सैकड़ों वैश्विक स्वयंसेवकों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। परियोजना का केंद्र कार्यकारी पत्रों, जर्नल लेखों, किताबों, पुस्तक अध्यायों का एक ऑनलाइन, विकेन्द्रीकृत ग्रंथसूची डेटाबेस संग्रहित करना है, जो ऐसे स्वयंसेवकों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। एनआईपीएफपी पुस्तकालय ने संस्थान के कार्यकारी पत्रों के मेटाडेटा को अपलोड करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विषय भंडार आरईपीईसी (अर्थशास्त्र पर शोध पत्र) में भी भाग लिया है। वर्ष 2023-24के दौरान, आरईपीईसीमें 17 कार्यकारी पत्र अपलोड किए गए हैं। इन एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्रों की 1,418बार सर्च, एक्सेस की गई और इन्हें डाउनलोड किया गया तथा इनके उद्धरणों को वैश्विक स्तर पर 6,380 बार देखा गया।

आरईपीईसी कार्यकारी पत्र श्रृंखला 2023-2024 के एक्सेस आंकड़े

डाउनलोडों और उद्धरण व्यूज की संख्या (अप्रैल 2023 – मार्च 2024)

माह	डाउनलोड	उद्धरण व्यूज
2023-04	177	756
2023-05	148	574
2023-06	159	519
2023-07	115	526
2023-08	98	461
2023-09	98	539
2023-10	134	553
2023-11	142	525
2023-12	79	483
2024-01	87	519
2024-02	89	450
2024-03	92	475
योग	1418	6380

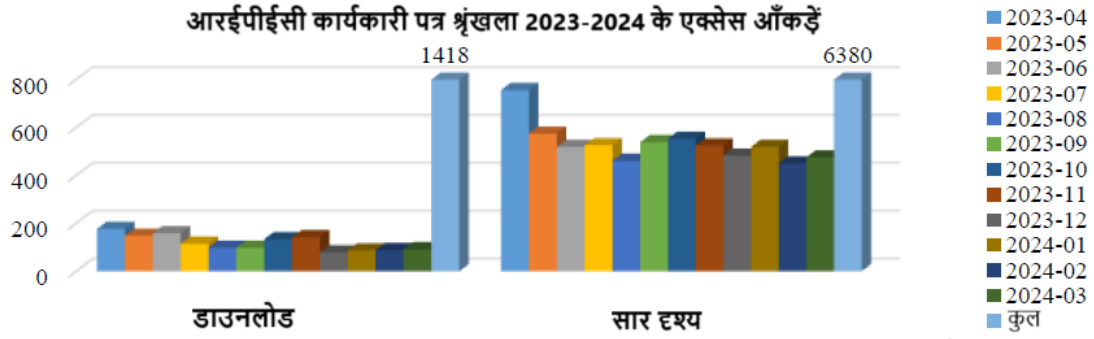

उपरोक्त तालिका और चार्ट से पता चलता है कि अप्रैल 2023 में कार्यकारी पत्रों के डाउनलोड और उद्धरण व्यूज की अधिकतम संख्या अर्थात क्रमश:177 और 756 थी।

रेप्रोग्राफिक सेवाएं

एनआईपीएफपी पुस्तकालय संकाय सदस्यों और बाह्य अनुसंधान स्कॉलरों को पुस्तकालय संसाधन सामग्री की पारंपरिक रिप्रोग्राफिक सेवा प्रदान करता है। किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए एनआईपीएफपी लाइब्रेरी में रिप्रोग्राफिक नयाचार का पालन किया जाता है।

पुस्तकालय स्टाफ क्रियाकलाप : 2023-24

प्रकाशित/प्रस्तुत पत्र

सिंह, सोनम, और कुमार, मनीष (2024)। उत्तर भारत के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संकाय और शोध विद्वानों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के उपयोग पर एक जांच। *वीथिका-एक अंतर्राष्ट्रीय अंत:विषय अनुसंधान पत्रिका, खंड 10(1):32-41.* https://doi.org/10.48001/veethika.2024.10.01.004

संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम

- सिंह, सोनम. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा एसएलजीसी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली के सहयोग से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 'ज्ञान तक पहुंच और भारत में डिजिटल लाइब्रेरी का भविष्य: प्रौद्योगिकी, कानून और नीति' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया, 17 मई 2023.
- सिंह, सोनम. नई दिल्ली के डेलनेट में डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (डेलनेट) की 32वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। 15 दिसंबर 2023.
- सिंह, सोनम. अशोका विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा द्वारा आयोजित 'ओपन एक्सेस एक ज्ञान मंच सतत विकास लक्ष्यों के लिए' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। 6 मार्च 2024.
- सिंह, सोनम. एनआईपीएफपी में दिल्ली विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बीएलआईएससी) के आठ छात्रों के लिए लाइब्रेरी इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया। अगस्त-सितंबर 2023.
- सिंह, सोनम. एनआईपीएफपी में संकाय और शोध कर्मचारियों को लाइब्रेरी का एक नया डिज़ाइन किया गया वेबपेज (कोहा लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत) प्रस्तुत किया। 29 जनवरी 2024. लाइब्रेरी वेबपेज को इस लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: https://nipfp-opac.tiss.co.in/
- सिंह, सोनम. एनआईपीएफपी में संकाय/शोध कर्मचारियों के लिए 'सीएमआईई डेटाबेस' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 4 मार्च 2024.

कंप्यूटर एकक

एनआईपीएफपी का कंप्यूटर सेंटर अकादमिक सहयोगियों के साथ-साथ संस्थान के अन्य पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण सहायता सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें लेखा, प्रशासन, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी, प्रकाशन और संचार विभाग शामिल हैं। यह केंद्र संकाय और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम तकनीकों से लैस है और एनआईपीएफपी परिसर पूरी तरह से वाई-फाई सक्षम है।

संस्थान की इंटरनेट सुविधा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा समर्थित है। एनआईपीएफपी एक साथ कई वीडियो कॉन्फ्रेंस चलाने में सक्षम है। वेबसाइट (nipfp.org.in) के प्रबंधन की देखरेख एक प्रोफेसर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है। नियमित संचालन के लिए पुस्तकालय और लेखा विभाग को विशेष सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाता है। पुस्तकालय को कोहा और विभिन्न अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से तकनीकी सहायता का लाभ मिलता है, जबकि लेखा विभाग टैली, ईएक्स अकाउंट्स और पेरोल सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, स्टाटा का उपयोग अनुसंधान प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

कंप्यूटर केंद्र समय-समय पर कंप्यूटर समिति द्वारा तैयार किए गए समग्र नीति मार्गदर्शन के तहत काम करता है। एनआईपीएफपी में 12 सिस्टम की क्षमता वाली एक डेटा एंट्री प्रयोगशाला भी है।

संकाय कार्यकलापों की मुख्य विशेषताएं

आर. कविता राव

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए दो सप्ताह के 15वें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक वित्त' पर आरंभिक व्याख्यान दिया। 5 जून 2023.
- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर 15वें रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'प्रत्यक्ष कर: नीति और परिप्रेक्ष्य' पर व्याख्यान दिया। 7 जून 2023।
- एनआईपीएफपी में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान, दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) अधिकारियों के लिए 'गैर-वित्त अधिकारियों के लिए वित्त' पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान दिया। 18 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख जिला बैंक प्रबंधकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरंभिक व्याख्यान दिया। 20 नवंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति: प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कर प्रणाली: कर परिक्षेत्र, नीतिगत सुधार' विषयपर एक व्याख्यान दिया। 5 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति: प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन व्याख्यान दिया। 8 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईए एंड एएस), शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक व्याख्यान दिया। 11 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में आईए एंड एएस, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक व्याख्यान दिया। 18 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में आईए एंड एएस, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक समापन व्याख्यान दिया। 22 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में बैंक ऑफ इंडिया के लीड डिस्ट्रिक्ट बैंक मैनेजरों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरंभिक व्याख्यान दिया। 15 जनवरी 2024.
- एनआईपीएफपी में बैंक ऑफ इंडिया के लीड डिस्ट्रिक्ट बैंक मैनेजरों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन व्याख्यान दिया। 19 जनवरी 2024.

आमंत्रित व्याख्यान

- मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई), गुड़गांव के 15वें पीजीडीएम-पीपीएम 2022 कार्यक्रम में अतिथि व्याख्यान दिया। 5 जुलाई 2023.
- एमडीआई गुड़गांव के 16वें पीजीडीएम-पीपीएम 2023 कार्यक्रम में अतिथि व्याख्यान दिया। 29 फरवरी 2024.
- जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के सामाजिक विज्ञान संकाय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा प्रायोजित 'सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर वैश्विक सम्मेलन: प्रगति, चुनौतियां और भावी मार्ग' विषय पर कार्यक्रममें 'मानव विकास और इसके वित्तपोषण' पर पूर्ण सत्र में एक वक्ता के रूप में भाग लिया। 6-7 मार्च 2024.

बैठकों/सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सचिव वी. श्रीनिवास, आईएएस द्वारा लिखित पुस्तक 'जी20@2023 दि रोडमैप टु इंडियन प्रेसीडेंसी' पर चर्चा में मुख्य पैनलविद। 1 अप्रैल 2023.
- माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए नीति आयोग द्वारा 'अमृतकाल के विजन को पूरा करने के लिए नीति आयोग की पुनर्कल्पना' विषय पर आयोजित चिंतक बैठक में भाग लिया। 18 अप्रैल 2023.
- ईंधन, भूमि और महासागरों जैसे प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में सब्सिडी के प्रभावों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 'डिटॉक्स डेवलपमेंट: रीपर्पसिंग डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी' पर चर्चा करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया। 15 मई 2023.
- दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया नीति संवाद में 'सतत विकास लक्ष्यों के लिए सार्वजनिक ऋण पर पुनर्विचार' पर पैनलविद सत्र: एशिया और प्रशांत 2023 का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण, 'सतत विकास लक्ष्यों के लिए सार्वजनिक ऋण पर पुनर्विचार' में प्रतिभागिता, संयुक्त राष्ट्र ईएससीएपी दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया (एसएसडब्ल्यूए) कार्यालय द्वारा ईएससीएपीएसएसडब्ल्यूए, नई दिल्ली में आयोजित। 8 जून 2023.
- राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा एनसीएईआर परिसर, नई दिल्ली में आयोजित 20वें भारत नीति मंच 2023 में 'क्या भारत में विद्युतीकरण वित्तीय रूप से टिकाऊ है?' विषय पर चर्चा। 6 जुलाई 2023.
- एनआईपीएफपी में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय-एनआईपीएफपी अनुसंधान कार्यक्रम के तहत संचालन समिति की पहली बैठक में प्रतिभागिता। 7 जुलाई 2023.
- भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के लिए 'अमृतकाल के लिए अवसंरचना के वर्गीकरण और वित्तपोषण' के लिए पृष्ठभूमि नोट पर राधिका पांडे के साथ एनआईपीएफपी की ओर से टिप्पणियों का सह-लेखन। 18 जुलाई 2023.
- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) आर्थिक मामलों की परिषद की 2023-24 के लिए पहली बैठक में ऑनलाइन भाग लिया। 1 अगस्त 2023.
- बिहार के वाणिज्यिक कर विभाग की वर्चुअल बैठक में सच्चिदानंद मुखर्जी के साथ प्रतिभागिता की, जिसमें राज्य में जीएसटी की वास्तविक कर क्षमता का आकलन करने पर चर्चा की गई। 13 सितंबर 2023.

- ताज पैलेस, नई दिल्ली में टैक्स इंडिया ऑनलाइन (टीआईओएल) टैक्स कांग्रेस 2023 के 'राज्य राजकोष के समक्ष राजकोषीय चुनौतियों' पर एक तकनीकी सत्र में पैनलविद। 4 अक्टूबर 2023.
- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), नई दिल्ली में विद्युत वितरण उपयोगिताओं की 12वीं एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए समिति (विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित) की बैठक में भाग लिया। 5 अक्टूबर 2023.
- एनआईपीएफपी द्वारा विश्व बैंक के साथ साझेदारी में एनआईपीएफपीमें आयोजित 'राज्य फोरम 2023: राज्य वित्त में विचारों और नवाचारों को साझा करना' पर दो-दिवसीय सम्मेलन में 'राज्य वित्त' पर एक प्रस्तुतीकारण पेश किया। 2 नवंबर 2023.
- एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित 'बेहतर परिणामों के लिए स्वास्थ्य वित्तपोषण के केंद्र-राज्य संरेखण' पर दो-दिवसीय वार्ता में उद्घाटन भाषण दिया। 23 नवंबर 2023.
- विद्युत वितरण उपयोगिताओं की 12वीं एकीकृत रेटिंग कवायद की समीक्षा के लिए समिति (विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित) की ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। 5 दिसंबर 2023.
- एनसीएईआर, नई दिल्ली द्वारा नीमराना फोर्ट पैलेस, नीमराना, राजस्थान में आयोजित 23वें वार्षिक नीमराना सम्मेलन में 'वैश्विक सार्वजनिक ऋण परिदृश्य' पर एक सत्र में पैनलविद। 16 दिसंबर 2023.
- आईसीआरआईईआर द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) और यूएनडीपी के सहयोग से इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 'कैसे बजट 2024 महिला-नेतृत्व वाले विकास को गति प्रदान कर सकता है' और 'महिला-नेतृत्व वाले विकास के लिए आर्थिक नीति पर नेटवर्क (ईपीडब्ल्यूडी)' के शुभारंभ पर एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 17 जनवरी 2024.
- पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में 'भारतीय अर्थव्यवस्था के भू-राजनीतिक फैलाव और लचीलेपन' विषय पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि। 19 दिसंबर 2023.
- अशोका विश्वविद्यालय में स्थापित नए आइज़ैक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 'अंतरिम बजट 2024 और उसके बाद' विषय पर चर्चा में पैनलविद। 27 जनवरी 2024.
- पीएफसी, नई दिल्ली में मैकिन्से द्वारा दी गई प्रस्तुति के संबंध में विद्युत वितरण उपयोगिताओं की 12वीं एकीकृत रेटिंग कवायद की समीक्षा के लिए समिति (विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित) की बैठक में भाग लिया। 29 जनवरी 2024
- 2023-24 के लिए सीआईआई आर्थिक मामलों की परिषद की तीसरी बैठक में ऑनलाइन भाग लिया। 12 फरवरी 2024.
- आईसीआरआईईआर, इंस्टीट्यूट फॉर न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग (आईएनईटी) और बीएमजीएफ द्वारा ताज मानसिंह होटल, नई दिल्ली संयुक्त रूप से आयोजित 'डिजिटल प्रौद्योगिकी, जनरेटिव एआई और उत्पादकता और विकास का भविष्य' विषय पर नोबल पुरस्कार विजेता ए. माइकल स्पेंस द्वारा दिए गए व्याख्यान में भाग लिया। 13 फरवरी 2024.
- जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में सोलहवें वित्त आयोग (XVI-एफसी) के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा आयोजित 'एनआईपीएफपी द्वारा XVIवें वित्त आयोग के लिए कार्य के लिए कुछ विचार' विषय पर एक बैठक में भाग लिया। 21 फरवरी 2024.

सरकारी तथा अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विद्युत वितरण उपयोगिताओं की 10वीं एकीकृत रेटिंग अभ्यास के लिए समिति की सदस्य।
- 2023-24 के लिए सीआईआईई आर्थिक मामलों की परिषद की सदस्य।

- नीति आयोग में फ्लेक्सी पूल के तहत वरिष्ठ सहयोगी के पदों पर भर्ती के लिए चयन समिति की सदस्य। मई 2023 से।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एफसी और ईओडीबी प्रभाग), भारत सरकार द्वारा गठित पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए विशेषज्ञ समिति की सदस्य।
- राजकोषीय क्षमता और प्रबंधन बढ़ाने पर छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग टास्कफोर्स की सदस्य।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तंबाकू कराधान पर विशेषज्ञ समूह की सदस्य।
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में पीएचडी थीसिस के लिए बाह्य रेफरी।
- जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता में पीएचडी थीसिस के लिए बाह्य रेफरी।
- एनईआर विजन डॉक्यूमेंट 2047 के सदस्य, एनईडीएफआई, को भारत सरकार के डोनर मंत्रालय के तहत उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी), शिलांग के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम सौंपा गया है। नवंबर 2023 से।

लेखा चक्रवर्ती

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवा (एमएफए) अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'जेंडर और चाइल्ड बजटिंग' पर एक व्याख्यान दिया।11 जनवरी 2024.
- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बजट विश्वसनीयता और राजकोषीय लक्ष्यसाधन' पर एक व्याख्यान दिया। 15 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति - प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन' पर एक व्याख्यान दिया। 6 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सरकार का अर्थशास्त्र' पर व्याख्यान दिया। 22 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय और मौद्रिक नीति विश्लेषण' पर व्याख्यान दिया। 21 मार्च 2023.

आमंत्रित व्याख्यान

- क्रीया विश्वविद्यालय, श्रीसिटी, आंध्र प्रदेश में 'बजट वार्ता: संघीय बजट को डिकोड करने पर व्याख्यान श्रृंखला' के भाग के रूप में जेंडर बजटिंग पर चर्चा की। 7 अप्रैल 2023.

- तिरुवनंतपुरम में केरल विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग के कृषि पारिस्थितिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में 'लैंगिक समानता के लिए राजकोषीय नीति' पर व्याख्यान दिया। 19 जुलाई 2023.
- तिरुवनंतपुरम में गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन (जीआईएफटी) और केरल इकोनॉमिक एसोसिएशन द्वारा 'भारत में संघ-राज्य संबंध' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम की आरंभिक पैनल चर्चा में भाग लिया। 21-23 जुलाई 2023,
- केरल डायलॉग्स दुबई द्वारा फ्लोरा होटल गढ़ौद, दुबई में आयोजित 'जेंडर बजटिंग और महिला वित्तीय सशक्तिकरण' पर व्याख्यान दिया। 30 जुलाई 2023.
- केरल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में 'भारत के मैक्रोइकॉनोमिक फ्रेमवर्क' विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। 16 अक्टूबर 2023.
- भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरुवनंतपुरम में 'वैश्विक आर्थिक चुनौतियों' पर व्याख्यान दिया। 9 नवंबर 2023.
- ह्यूमैनिटीज कलेक्टिव, आईआईएसईआर, तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र श्रृंखला में 'वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ और भारत' पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 9 नवंबर 2023.
- जनआग्रह, नई दिल्ली द्वारा आयोजित शहरों के लिए सार्वजनिक वित्त में महिला फैलोशिप इंडक्शन वर्कशॉप में 'अभिनव बजट-लिंग और जलवायु बजट' पर व्याख्यान दिया। 18 जनवरी 2024.
- अर्थशास्त्र विभाग, कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर, केरल में 'केंद्रीय बजट 2024 के मैक्रोइकॉनोमिक फ्रेमवर्क का विश्लेषण' पर व्याख्यान दिया। 14 फरवरी 2024.
- निर्मलागिरी, कन्नूर में 'केंद्रीय बजट 2024 की राजनीतिक अर्थव्यवस्था' पर व्याख्यान दिया।15 फरवरी 2024.
- आंध्र प्रदेश सरकार के लिए जेएनयू मानव संसाधन विकास केंद्र (एचडीआरसी) क्षमता निर्माण कार्यक्रम में जेएनयू, नई दिल्ली में 'लिंग और आर्थिक विकास: समान रूप से अविश्वसनीय समतुल्य पद्धति का उपयोग करके भारत में परिणाम-लिंक्ड लिंग बजट' पर व्याख्यान दिया। 29 फरवरी 2024.
- जीआईएफटी, तिरुवनंतपुरम में पीएचडी कार्यक्रम के लिए 'नीति संकट के लिए मैक्रोइकॉनोमिक प्रतिक्रिया' पर एक विशेष व्याख्यान दिया। 12 मार्च 2024.
- तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन में इकोविंग्स व्याख्यान श्रृंखला के 88वें सत्र में 'जस्ट ट्रांजिशन: मौद्रिक राजकोषीय चुनौतियां हरित अर्थव्यवस्था की ओर' विषय पर व्याख्यान दिया। 12 मार्च 2024.
- केरल इकोनॉमिक एसोसिएशन और जीआईएफटी, तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा में 'सोलहवें वित्त आयोग और राजनीतिक अर्थव्यवस्था' पर एक व्याख्यान दिया। 16 मार्च 2024.
- ड्यूक विश्वविद्यालय, अमेरिका में वसंत सेमेस्टर में 'लैंगिक आसमानताएं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राजकोषीय नीतियां' विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 21 मार्च 2024.
- अकादमिक स्टाफ कॉलेज, तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में 'राजकोषीय नीति' पर व्याख्यान दिया। 18 जून 2023.
- सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पुणे में 'जेंडर बजटिंग' पर आयोजित वेबिनार में व्याख्यान दिया। 4 नवंबर 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी, लोगान, यू.एस. में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस की 79वीं वार्षिक कांग्रेस में ऑनलाइन भाग लिया। 13-16 अगस्त 2023.

- मुंबई में 'नीति-निर्माता 2023 की आर्थिक चुनौतियों को कैसे देखते हैं'पर आयोजित 10वें एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में 'सीमाओं से परे भारतीय अर्थव्यवस्था' विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया। 9 जनवरी 2024.
- तुर्की के इस्तांबुल में 'लैंगिक समानता के लिए सार्वजनिक वित्त और कर' पर पहली यूएनडीपी वैश्विक वार्ता में भाग लिया। 6-8 फरवरी 2024.
- तिरुवनंतपुरम के कनककुन्नू पैलेस में मातृभूमि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में 'लैंगिक और समानता' पैनल में भाग लिया। 8 फरवरी 2024.
- मातृभूमि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, तिरुवनंतपुरम में 'राज्य वित्त' पर आयोजित बहस में केरल के वित्त मंत्री के साथ सह-पैनलविद। 10 फरवरी 2024.
- अर्थशास्त्र विभाग, निर्मलागिरी, कन्नूर, केरल द्वारा 'राजकोषीय संघवाद और केंद्रीय बजट' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। 15 फरवरी 2024.
- केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान, त्रिशूर द्वारा 'केरल शहरी संवाद: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध' विषय पर आयोजित चर्चा में चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया। 29 फरवरी 2024.
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर द्वारा 'ब्रिक्स विकास और शासन' पर आयोजित 6वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'डिजिटलीकरण और सुशासन' पर एक सत्र की अध्यक्षता की। 6 मार्च 2024.
- मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई, तमिलनाडु में 'सार्वजनिक वित्त और नीति' पर आयोजित दूसरे वार्षिक सम्मेलन में 'भारत में हरित अर्थव्यवस्था के लिए जलवायु परिवर्तन और राजकोषीय नीति' पर सह-लिखित पत्र प्रस्तुत किया। 8 मार्च 2024.
- जनआग्रह और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा शहरों के लिए सार्वजनिक वित्त में महिला फेलोशिप के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेरण कार्यशाला में 'जेंडर बजटिंग और जलवायु बजटिंग' पर व्याख्यान दिया। 18 जनवरी 2024.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- सदस्य, गवर्निंग बोर्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, म्यूनिख।
- सदस्य, कार्यकारी बोर्ड, बजट अध्ययन केंद्र, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि।
- सदस्य, इंडो-कैनेडियन डेवलपमेंट काउंसिल।
- सदस्य, इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी।
- सदस्य, संचालन समिति, कॉप27, एमओईएफसीसी, भारत सरकार।
- सदस्य, जलवायु वित्तपोषण के लिए सलाहकार समिति, एमओईएफसीसी, भारत सरकार।
- सदस्य, सलाहकार समूह, स्पेन में विकास फोरम 2024 के लिए वित्तपोषण की तैयारी करने के लिए ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन, डी.सी. (बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई)।
- सदस्य, सलाहकार बोर्ड, बजट अध्ययन केंद्र, कोचीन विश्वविद्यालय।
- पीएच.डी. थीसिस के लिए बाह्य मूल्यांकनकर्ता, गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे।
- पीएच.डी. थीसिस के लिए बाह्य मूल्यांकनकर्ता, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।
- पीएच.डी. थीसिस के लिए बाहरी मूल्यांकनकर्ता, आईआईएमकोझिकोड।
- रूटलेज के लिए पुस्तक/पांडुलिपि के लिए समीक्षक।
- सदस्य, सलाहकार बोर्ड, अर्थशास्त्र विभाग, कुमारगुरु कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंस, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोयंबटूर।
- सदस्य, कार्यकारी बोर्ड, सलाहकार परिषद, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, तमिलनाडु, विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन (डीम्ड यूनिवर्सिटी)।

- सदस्य, *2024,* सलाहकार बोर्ड, केरल विश्वविद्यालय, चार वर्षीय बीए ऑनर्स की शुरूआत पर पाठ्यक्रम समिति, महाराजा कॉलेज फॉर विमेन, तिरुवनंतपुरम।
- सलाहकार सदस्य, पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र और डेटा विज्ञान विभाग, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, लवासा, पुणे।
- सदस्य, बीएससी और एमएससी अर्थशास्त्र और विश्लेषिकी के लिए समीक्षा समिति, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी।
- विशेष लेखों के लिए रेफरी, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक।

पुरस्कार

- मैक्रोइकॉनॉमिक्स टी92 एसकेओसीएच शिखर-सम्मेलन के लिए एसकेओसीएच पुरस्कार प्राप्त किया। 27 मई 2023.

प्रताप रंजन जेना

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए 15वें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' पर व्याख्यान दिया। 13 जून 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली: एक आकलन' पर व्याख्यान दिया। 22 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति-प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय नियम और स्थिरता: बजट प्रबंधन' पर व्याख्यान दिया। 4 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस, एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली: मुद्दे और नवाचार' पर व्याख्यान दिया। 18 दिसंबर, 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति-प्रबंधन और उभरते मुद्दों' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'एमटीईएफ और प्रदर्शन बजट' पर एक व्याख्यान दिया। 6 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवाओं (एमएफए) के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत बनाने' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली: मुद्दे और नवाचार' और 'सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही' विषयों पर दो व्याख्यान दिए। 9-10 जनवरी 2024.
- गुवाहाटी में असम सरकार के वित्त विभाग के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के सेवारत अधिकारियों के लिए 'जीएसडीपी अनुमान से संबंधित मुद्दे और ग्रीन बजट की तैयारी के लिए सर्वोत्तम

अभ्यास' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'ग्रीन बजटिंग फ्रेमवर्क' पर व्याख्यान दिया। 28 जुलाई 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- गोवा में 'गोवा वित्त' पर आयोजित सम्मेलन में चिंतन शिविर में 'गोवा के राज्य वित्त और राजस्व प्रयास' विषय पर वक्ता के रूप में भाग लिया। 9 जून 2023.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- सदस्य, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की सार्वजनिक एवं सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति।
- सदस्य, रक्षा मंत्रालय, रक्षा संपदा के महानिदेशक द्वारा गठित सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार समिति।

मीता चौधरी

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'हेल्थकेयर फाइनेंसिंग में सार्वजनिक नीति के मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 20 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति - प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्वास्थ्य प्रणाली: परिणाम, सार्वजनिक व्यय, बीमा' पर एक व्याख्यान दिया। 7 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के लिए आयोजित 15वें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'केंद्र प्रायोजित योजनाएं: औचित्य बनाम वास्तविकता' पर एक व्याख्यान दिया। 12 जून 2023.
- एनआईपीएफपीमें मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवाओं (MFAs) के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करना' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्वास्थ्य प्रणाली: परिणाम, सार्वजनिक व्यय, बीमा' पर व्याख्यान दिया।10 जनवरी 2024.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- सदस्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा गठित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के डिजाइन और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति।
- सदस्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों पर विशेषज्ञ समूह।

- दिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र स्कूल द्वारा 'ग्रामीण हरियाणा में आयुष्मान भारत' पर आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ/सलाहकार।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई में पीएच.डी. थीसिस के परीक्षक।

सच्चिदानंद मुखर्जी

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवा (एमएफए) अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कर वृद्धि के उपाय: राज्यों का परिप्रेक्ष्य' पर व्याख्यान दिया।8 जनवरी 2024.
- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस, एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कर: कराधान के सिद्धांत और सिद्धांत' और 'कर: जीएसटी – राजस्व निहितार्थ' विषयों पर दो व्याख्यान दिए। 11-12 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति – प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'माल और सेवा कर' पर एक व्याख्यान दिया। 5 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'माल और सेवा कर (जीएसटी): मुद्दे और चुनौतियां' पर एक व्याख्यान दिया। 20 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए 15वें रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): डिजाइन और संरचनात्मक मुद्दे' और 'जीएसटी का राजस्व प्रदर्शन आकलन' विषयों पर दो व्याख्यान दिए। 7-8 जून 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति-प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कराधान और मध्यम अवधि की राजस्व रणनीति' पर व्याख्यान दिया। 25 मई 2023.

आमंत्रित व्याख्यान

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अर्थशास्त्र में 'भारतीय अर्थव्यवस्था में नीतिगत मुद्दे' विषय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए 'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): मुद्दे और चुनौतियाँ' पर व्याख्यान दिया, मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई। 7 नवंबर 2023.
- इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा 'अमृत काल में भारत में सार्वजनिक नीति की रूपरेखा' पर आयोजित ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शरदकालीन स्कूल कार्यक्रम में 'भारत में वस्तु एवं सेवा कर: तर्कसंगतता और सुधार दिशाएँ' पर व्याख्यान दिया। 9 सितंबर 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी), नई दिल्ली द्वारा 'भारत में स्वास्थ्यवर्धक आहार के लिए राजकोषीय नीति: भारत में एचएफएसएस खाद्य पदार्थों पर कराधान के प्रभाव की मॉडलिंग' विषय पर आयोजित परामर्श बैठक में 'भारत में उच्च वसा वाले चीनी नमक (एचएफएसएस) की खपत और कराधान' पर पैनलविद सत्र। 16 जून 2023.
- सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र, नई दिल्ली में 'भारत में ऊर्जा संक्रमण के लिए राजकोषीय अवसर' विषय पर गोलमेज सम्मेलन' में चर्चा। 9 मई 2023.
- आईईजी, दिल्ली में 'उच्च वसा वाले चीनी नमक (एचएफएसएस) खाद्य पदार्थों और कराधान पर परामर्श बैठक' पर तकनीकी सत्र में चर्चा। 14 दिसंबर 2023.
- 'भारत के समकालीन मैक्रोइकॉनोमिक थीम' पर सम्मेलन में 'भारतीय राज्य वित्त पर जीएसटी की राजस्व विवकक्षाएं' पर एक पेपर प्रस्तुत किया, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई। 21-22 अप्रैल 2023।
- एनआईपीएफपी के राज्य फोरम 2023 में, 2-3 नवंबर 2023 को, एनआईपीएफपी में 'वर्तमान दशक में भारत में राज्य वित्त की स्थिति' पर पत्र प्रस्तुत किया।
- 'भारत में स्वास्थ्य कर: नीति और अभ्यास' पर विश्व बैंक कार्यशाला में 'स्वास्थ्य कर- वैश्विक परिप्रेक्ष्य' पर सत्र में पैनलविद, ताज मानसिंह, नई दिल्ली। 11 अक्टूबर2023.

सरकार और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- सदस्य, सार्वजनिक डोमेन में जीएसटीएन डेटा साझा करना संबंधी समिति, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

अमरनाथ एच. के.

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में आईएंडएएस, एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'व्यय का वर्गीकरण' और 'बजट और ऑफ-बजट उधार' पर व्याख्यान दिया।13-14 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए आयोजित15वें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारतीय सार्वजनिक वित्त डेटाबेस' और 'विकास व्यय/सब्सिडी के लिए राजकोषीय स्थान' पर व्याख्यान दिया। 5-16 जून 2023.
- एनआईपीएफपीमें भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक वित्त डेटाबेस में अनुभवजन्य मुद्दों' पर व्याख्यान दिया। 15 फरवरी 2023.
- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवाओं (एमएफए) के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करना' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बजट और ऑफ-बजट उधार' और 'सब्सिडी और राजकोषीय स्थान: राज्यों के लिए विवक्षाएं' पर व्याख्यान दिया। 9 जनवरी 2024.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- तमिलनाडु शहरी अध्ययन संस्थान कोयंबटूर के साथ समझौता ज्ञापन के तहत शहरी स्थानीय निकायों पर डेटाबेस विकसित करने के लिए एनआईपीएफपी के समन्वयक, पांच वर्षके लिए। 5 दिसंबर 2022 से.

मनीष गुप्ता

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवा (एमएफए) के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करना' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'यूएलबी के लिए नवाचार और वित्त के वैकल्पिक स्रोतों' पर व्याख्यान दिया। 10 जनवरी 2024.
- एनआईपीएफपी में आईए एंड एएस, एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राज्य वित्त की स्थिति' पर व्याख्यान दिया। 14 दिसंबर 2023.

- एनआईपीएफपी में आईए एंड एएस, एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'शहरी स्थानीय निकायों का वित्त: शहरों में निवेश' और 'यूएलबी के लिए वित्त के वैकल्पिक स्रोत' विषय पर दो व्याख्यान दिए। 21 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति – प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'उप-राष्ट्रीय सरकारों के वित्त' पर एक व्याख्यान दिया। 4 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राज्य-केंद्र वित्तीय संबंध' पर एक व्याख्यान दिया। 19 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति-प्रबंधन और उभरते मुद्दों' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'उप-राष्ट्रीय सरकारों के वित्त' पर व्याख्यान दिया। 25 मई 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एनआईपीएफपी में 'भारत का प्रदर्शन? मध्य-वर्षीय मैक्रोइकॉनोमिक समीक्षा' में 'केंद्र और राज्य सरकारों का राजकोषीय दृष्टिकोण' प्रस्तुत किया। 11 अगस्त 2023.

सरकार और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- सदस्य,सोलहवें वित्त आयोग के लिए शहरी ज्ञापन तैयार करने संबंधी समिति, आवासन और शहरी कार्यमंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार।
- सोलहवें वित्त आयोग, एमओएचयूए,भारत सरकार के तहत नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए विशेषज्ञ समिति में निदेशक, एनआईपीएफपीद्वारा नामित सदस्य।
- सदस्य, ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान पर टास्कफोर्स की सहायता के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह।

रुद्राणी भट्टाचार्य

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए 15वें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'इष्टतम ऋण: विकास बनाम मुद्रास्फीति व्यापार-बंद' पर व्याख्यान दिया। 9जून 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय-मौद्रिक नीति संबंधों' पर व्याख्यान दिया। 21 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले

अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति - प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'मुद्रास्फीति: माप और प्रबंधन' पर व्याख्यान दिया। 6 दिसंबर 2023.

आमंत्रित व्याख्यान

- यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (एमएमटीटीसी), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा एमएमटीटीसी, जेएनयू में आयुक्तालय ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन, आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित 'मौद्रिक नीति संचरण और विकास सिद्धांत' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'अर्थशास्त्र में एकल प्रमुख विषय पैटर्न में केआरपी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम' पर व्याख्यान दिया। 27 फरवरी 2024.
- नागपुर में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी द्वारा आयोजित 'सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक वित्त' पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कुल मांग और कुल आपूर्ति', 'बंद बनाम खुली अर्थव्यवस्था' और 'मूल्य हस्तक्षेप' पर व्याख्यान दिया। 4 जुलाई 2023.
- अरबिंदो कॉलेज, नई दिल्ली में वार्षिक अर्थशास्त्र व्याख्यान श्रृंखला अर्थ-संवाद में 'वित्तीय और आर्थिक संकट: भारत के लिए निहितार्थ' पर व्याख्यान दिया। 18 अप्रैल 2023.
- दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित 'आयकर घोषणा योजना 2016' पर कार्यशाला में 'भारत का व्यापक आर्थिक अवलोकन' पर व्याख्यान दिया। 12 फरवरी 2024.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एनआईपीएफपी में 'भारत का प्रदर्शन? भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्य-वर्षीय समीक्षा 2023-24' पर आयोजित एक-दिवसीय बैठक आयोजित की। 11 अगस्त 2023.
- एनआईपीएफपी में 'भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्य-वर्षीय समीक्षा 2023-24' पर आयोजित एक-दिवसीय बैठक में 'भारत के रियल सेक्टर, मुद्रास्फीति और बाहरी क्षेत्र की समीक्षा' पर प्रस्तुतीकरण पेश किया। 11 अगस्त 2023.
- सेंटर फॉर पब्लिक फाइनेंस, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई द्वारा 'पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी' पर आयोजित दूसरे वार्षिक सम्मेलन में 'जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन ने भारत को कैसे प्रभावित किया' पर पत्र प्रस्तुत किया। 8 मार्च 2024.
- जेएनयू में सीईएसपी द्वारा आयोजित सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग (सीईएसपी) गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस में चर्चाकर्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। 11 दिसंबर 2023.
- इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, जेएनयू और भारत कृषक समाज द्वारा संयुक्त रूप से 'आय प्रतिमानों से परे देखना: भारत के नीतिगत विमर्श में ग्रामीण सम्मान लाना' विषय पर आयोजित सेमिनार में एक सत्र की अध्यक्षता की। 29 जनवरी 2024.
- आईआईटी दिल्ली में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के पीएच.डी. (अर्थशास्त्र) छात्रों द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में चर्चा। 15 मार्च 2024.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- सदस्य, अनुसंधान सलाहकार समिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास केंद्र, जेएनयू, 2022 से अब तक।
- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (एम.फिल. थीसिस), सितंबर 2023; *अर्थनीति*, अप्रैल 2023; *जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट*, जून 2023; *एप्लाइड इकोनॉमिक लेटर्स*, अगस्त 2023; *जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक्स*, अगस्त 2023; *आईआईएमबी मैनेजमेंट रिव्यू*, सितंबर 2023; *सेज इंडियन इकोनॉमिक जर्नल*, सितंबर 2023; *जर्नल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट*, सितंबर 2023; *जर्नल*

ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्च 2024; *क्यूईआईओएस*, नवंबर 2023; *कॉजेंट फूड एंड एग्रीकल्चर*, दिसंबर 2023; *मानविकी और सामाजिक विज्ञान अध्ययन*, दिसंबर 2023 और; *आईआईएमबी मैनेजमेंट रिव्यू*, मार्च 2024 के लिए लेखों की समीक्षा की।

- आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के लिए पत्र समीक्षा। नवंबर 2023.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यक्रम'मौद्रिक नीति के लिए क्षेत्रीय अपेक्षा सर्वेक्षण' की प्रतिक्रिया में योगदान दिया। सितंबर 2023 और मार्च 2024.

अमय सप्रे

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में भारतीय बैंक के प्रमुख जिला बैंक प्रबंधकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'आधिकारिक सांख्यिकी में समकालीन मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 16 जनवरी 2024.
- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवाओं (एमएफए) के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करने' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'जीएसडीपी अनुमान में मुद्दे' पर व्याख्यान दिया।8 जनवरी 2024.
- एनआईपीएफपी में आईएए और एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राष्ट्रीय आय लेखांकन का परिचय' और 'राष्ट्रीय आय लेखांकन में मापन मुद्दे' विषयों पर दो व्याख्यान दिए। 15 दिसंबर 2024.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टार्फिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति - प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'विकास का मापन: सिद्धांत, अभ्यास और सांख्यिकी' पर व्याख्यान दिया। 8 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय बैंक के प्रमुख जिला बैंक प्रबंधकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'आधिकारिक सांख्यिकी में समकालीन मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 21 नवंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'जीडीपी अनुमान की मूल बातें' पर व्याख्यान दिया। 20 सितंबर 2023।
- गुवाहाटी में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, वित्त विभाग, असम सरकार के सेवारत अधिकारियों के लिए 'जीएसडीपी अनुमान से संबंधित मुद्दे और ग्रीन बजट की तैयारी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'जीएसडीपी अनुमान में अवलोकन और मुद्दे' और 'जीएसडीपी अनुमान के लिए डेटा गुणवत्ता, प्रक्रियाओं और सुधार की गुंजाइश पर चर्चा'विषयों पर दो व्याख्यान दिए। 26-27 जुलाई 2023.
- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए आयोजित 15वें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राष्ट्रीय आय लेखांकन का परिचय' और 'राष्ट्रीय आय लेखांकन में मापन मुद्दे' विषयों पर दो व्याख्यान दिए। 9 जून 2023.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा रहित)के लिए पांचवां वित्त आयोग। जनवरी 2024.

सुकन्या बोस

एनआई पीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के लिए आयोजित 15वें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्कूल शिक्षा का सार्वजनिक वित्तपोषण: कुछ प्रमुख प्रश्न और अनुभवजन्य साक्ष्य' पर व्याख्यान दिया। 13 जून 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति: प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'शिक्षा और कौशल विकास' पर एक व्याख्यान दिया। 7 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस, एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'आरटीई: वित्त पोषण और लेखा परीक्षा के लिए परिप्रेक्ष्य' पर एक व्याख्यान दिया। 21 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवा (एमएफए) अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'आरटीई: राज्य बजट के लिए वित्त पोषण और परिप्रेक्ष्य' पर व्याख्यान दिया।11 जनवरी 2024.

  नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एमएलए कार्यशाला में 'भारत में सार्वजनिक शिक्षा के वित्तपोषण' पर व्याख्यान दिया। 9-10 अक्टूबर 2023.

नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एमएलए कार्यशाला में 'भारत में सार्वजनिक शिक्षा के वित्तपोषण' पर व्याख्यान दिया। 9-10 अक्टूबर 2023.

- नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एमएलए कार्यशाला में 'भारत में सार्वजनिक शिक्षा के वित्तपोषण' पर व्याख्यान दिया। 9-10 अक्टूबर 2023.

आमंत्रित व्याख्यान

- नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एमएलए कार्यशाला में 'भारत में सार्वजनिक शिक्षा के वित्तपोषण' पर व्याख्यान दिया।9-10 अक्टूबर 2023.

बठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एचएक्यू: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स द्वारा आयोजित बालिका शिक्षा वित्तपोषण पर राष्ट्रीय परामर्श पैनल में शामिल। 27 अप्रैल 2023.

- नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित 'उच्च शिक्षा में वित्तीय संसाधन प्रबंधन' पर एक विशेषज्ञ पैनल के भाग के रूप में 'उच्च शिक्षा वित्तपोषण में संरचनात्मक समायोजन और प्रतिमान बदलाव: मैक्रोट्रेंड्स और पैटर्न' पर एक पेपर प्रस्तुत किया। 13-14 फरवरी 2024.
- एनआईपीएफपी में एक आंतरिक सेमिनार में 'मानव विकास, वृद्धि और वितरण: भारत के लिए एक मैक्रो-राजकोषीय ढांचा' पर एक प्रस्तुति दी। 21 मार्च 2024.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- ट्रस्टी, सहयोगी अनुसंधान और प्रसार (सीओआरडी)
- सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड, एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन।
- सदस्य, कोर ग्रुप, राइट टू एजुकेशन (आरटीई) फोरम।

सुरांजलि टंडन

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत कार्यरत अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति-प्रबंधन और उभरते मुद्दों' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कराधान के क्षेत्रों में सुधार और नई प्रगति' पर व्याख्यान दिया। 24 मई 2023.

आमंत्रित व्याख्यान

- नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद में 'जलवायु परिवर्तन, हरित वित्तपोषण, कराधान' पर व्याख्यान दिया। 7 मई 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में पॉलिसी सर्किल द्वारा आयोजित इंडिया सस्टेनेबिलिटी शिखर-सम्मेलन में 'जलवायु निधि का दोहन' पर चर्चा में पैनलविद। 26 जुलाई 2023.
- अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता द्वारा आयोजित 'भारत के सतत ऊर्जा संक्रमण का वित्तपोषण: साधन, बाजार और सिद्धांत' पर एक ऑनलाइन चर्चा में पैनलविद। 17 अगस्त 2023.
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), नई दिल्ली द्वारा आयोजित संयोजनता, स्थिरता, समृद्धि-भारत की जी20 अनिवार्यता को आगे बढ़ाना' विषय पर गोलमेज चर्चा में भाग लिया। 24 अगस्त 2023.
- क्लाइमेट ट्रेंड्स, नई दिल्ली द्वारा 'क्लाइमेट फाइनेंस 101-क्लाइमेट फाइनेंस के प्रवाह को कौन रोक रहा है?' पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में वक्ता। 5 सितंबर 2023.
- सीयूटीएस इंडिया द्वारा 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ड्राइविंग फैक्टर के रूप में अभिनव वित्त तंत्र' पर आयोजित पॉडकास्ट में भाग लिया। 12 सितंबर 2023.
- ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव, नई दिल्ली द्वारा 'जी20 के बाद की प्राथमिकताएं भारतीय सतत वित्त रोडमैप' पर आयोजित गोलमेज चर्चा में भाग लिया। 22 सितंबर 2023.

- एशियाई विकास बैंक, मनीला द्वारा एशिया-प्रशांत सामाजिक संरक्षण सप्ताह के हिस्से के रूप में 'जस्ट ट्रांजिशन' पर आयोजित ऑनलाइन सत्र में भाग लिया। 26 सितंबर 2023.
- जर्मन वॉच द्वारा 'भारत के जस्ट ट्रांजिशन में निवेश-संभावना और अभ्यास के बीच' पर आयोजित ऑनलाइन चर्चा में पैनलविद। 16 अक्टूबर 2023.
- जलवायु, खाद्य, ऊर्जा और पर्यावरण के अर्थशास्त्र पर शोध केंद्र, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली और बजट और शासन जवाबदेही केंद्र, नई दिल्ली द्वारा 'भारत के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण नीति की स्थापना: आगे का रास्ता' पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में वक्ता। 19 अक्टूबर 2023.
- संयुक्त राष्ट्र फोरम फॉर सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा 'सतत व्यापार और मानकों' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'जलवायु वित्त पहलों के मापनीय प्रभाव का निर्माण – व्यवहार में निगरानी और मूल्यांकन उपकरण' पर आयोजित चर्चा में पैनलविद। 1 नवंबर 2023.
- ओआरएफ और स्वीडिश एंटरप्राइज कन्फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली स्थित स्वीडन के दूतावास में 'भारत और यूरोपीय संघ 2030 में - एक करीबी आर्थिक संबंध का निर्माण' विषय पर फेयर रिपोर्ट के सह-आयोजित लॉन्च पर वक्ता। 22 नवंबर 2023.
- ग्लोबटैक्सगव, यूनिवर्सिटी ऑफ लीडेन और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन द्वारा 'ओईसीडी बनाम यूएन' पर आयोजित वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन में वक्ता। 23 नवंबर 2023.
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, नई दिल्ली द्वारा 'सस्टेनेबल फाइनेंस: की टू बिजनेस ग्रोथ इन द न्यू एज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी' पर आयोजित उच्च स्तरीय पैनल में वक्ता और पैनलविद। 15 दिसंबर 2023.
- आईआईटी मद्रास, चेन्नई में 5वें एनर्जी फाइनेंस कॉन्फ्रेंस, इंडिया में 'एनर्जी फाइनेंस' पर एक वक्ता के रूप में भाग लिया। 19 जनवरी 2024.
- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन में ग्रांथम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के जस्ट ट्रांजिशन फाइनेंस लैब के शुभारंभ पर वक्ता। 20 फरवरी 2024.
- क्लाइमेट बॉन्ड्स, इंडीक और एसिया सेंटर, नई दिल्ली द्वारा 'राज्यों के लिए ग्रीन ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने के लिए नए वित्तीय रास्ते खोलना: विकल्प और रणनीति' पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में वक्ता। 26 फरवरी 2024.
- एसआईपीए, कोलंबिया द्वारा आयोजित वार्ता में 'क्लाइमेट फाइनेंस, पॉलिसी और जस्ट ट्रांजिशन' पर ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत किया। 5 अप्रैल 2023.
- सीयूटीएस द्वारा 'क्लाइमेट फाइनेंस के लिए यूनिवर्सल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स' पर आयोजित वेबिनार में वक्ता। 21 अप्रैल 2023.
- इंडस लॉ और चेस इंडिया, नई दिल्ली द्वारा 'क्या भारत की जी20 प्रेसीडेंसी क्रिप्टो विनियमन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगी?' पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 29 मई 2023.
- अंतर्राष्ट्रीय कर एवं विकास केंद्र और केन्या स्कूल ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी, नैरोबी, केन्या द्वारा 'ग्लोबल टैक्स गवर्नेंस एट क्रॉसरोड्स' में 'कर सेवाओं' पर आयोजित पैनल चर्चा में संचालक और 'धनवानों का कराधान' पर गोलमेज सम्मेलन में पैनलविद। 5-6 जून 2023.
- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन में 'भारत के जी20 वर्ष में सतत वित्त: नीति और व्यवहार में नवीनतम विकास' पर एक प्रस्तुति दी। 23 जून 2023.

- ‘हरित परिवर्तन के लिए कर नीति’ पर एक प्रस्तुति दी और लोरेंट्ज़ सेंटर, लीडेन विश्वविद्यालय, नीदरलैंड द्वारा ‘वैश्विक शासन को पुनर्परिभाषित करना: यूरोपीय संघ और उससे आगे कर, व्यापार और निवेश परिप्रेक्ष्य’ पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। 26-28 जून 2023.
- अंतर्राष्ट्रीय कर अनुसंधान और विश्लेषण फाउंडेशन के 7वें वार्षिक सम्मेलन में ‘हरित परिवर्तन के लिए कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाना’ पर एक पेपर ऑनलाइन प्रस्तुत किया। 30 जून 2023.
- ऑस्ट्रिया के विएना में इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रियन और इंटरनेशनल टैक्स लॉ द्वारा आयोजित आरयूएसटीसम्मेलन में ‘क्रिप्टो एसेट्स: टैक्स लॉ एंड पॉलिसी इन इंडिया’ पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 29 जून से 2 जुलाई 2023 तक।
- कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कैम्ब्रिज टैक्स लॉ कॉन्फ्रेंस में ‘क्या जीएएआर कानून के नियमों का उल्लंघन है’ पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 3-4 जुलाई 2023.
- कर्नाटक के मैसूर में टी-20 सचिवालय द्वारा आयोजित थिंक 20 शिखर सम्मेलन में ‘ऊर्जा संक्रमण: स्वच्छ और न्यायसंगत भविष्य की ओर’ पर पैनल चर्चा में मॉडरेटर। 1 अगस्त 2023.
- विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ‘अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में युआन का डी-डॉलरीकरण और उद्भव’ पर एक प्रस्तुति के लिए चर्चाकर्ता। 21 अगस्त 2023.
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में विशेषज्ञों के साथ प्री-सीओपी28वार्ता में भाग लिया। 22 नवंबर 2023.
- आईबीडीटी (ब्राजील इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स लॉ), साओ पाउलो, ब्राजील द्वारा आयोजित एक वर्चुअल ग्लोबल टैक्स संगोष्ठी में ‘ग्लोब: सहयोग की संभावित लागत’ पर पत्र पर चर्चा। 4 दिसंबर 2023.
- आईबीडीटी, साओ पाउलो द्वारा आयोजित एक वर्चुअल ग्लोबल टैक्स संगोष्ठी में ‘मोबाइल पर कर लगाना’ पर एक पेपर प्रस्तुत किया। 4 दिसंबर 2023.
- वर्चुअल टैक्स इंस्पायर सम्मेलन में पैनलिस्ट। 6 दिसंबर 2023.
- ब्रुसेल्स में यूरोपीय प्रगतिशील अध्ययन फाउंडेशन के साथ ‘रणनीतिक खुलापन? सीबीएएम के समावेशी कार्यान्वयन की ओर’ विषय पर एक हाइब्रिड गोलमेज सम्मेलन का सह-आयोजन किया।12 अक्टूबर 2023.

राधिका पांडे

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति - प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय नीति में मुद्दों का परिचय' पर व्याख्यान दिया। 24 मई 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय नीति में मुद्दे' पर परिचयात्मक व्याख्यान दिया। 18 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'धन की मांग और आपूर्ति' पर एक व्याख्यान दिया। 19 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला बैंक प्रबंधकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'मैक्रो इकोनॉमी का अवलोकन' और 'बैंकिंग में नियामक उपकरण' पर दो व्याख्यान दिए। 21 और 24 नवंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति - प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय नीति में मुद्दों का परिचय' और 'धन की मांग और आपूर्ति' विषयों पर दो व्याख्यान दिए। 4 और 12 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस, एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजितप्रशिक्षण कार्यक्रम में 'मूल्य सूचकांक की मूल बातें' पर एक व्याख्यान दिया। 13 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवाओं (एमएफए) के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करना' पर आयोजितप्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राज्य स्तर पर ऋण प्रबंधन' और 'राज्य स्तरीय मुद्रास्फीति' विषयों पर दो व्याख्यान दिए। 9 और 12 जनवरी 2024.
- एनआईपीएफपी में बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख जिला बैंक प्रबंधकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दों' परआयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'मैक्रोइकॉनमी का अवलोकन', 'अर्थव्यवस्था में आरबीआई और वित्तीय स्थिरता' और 'बैंकिंग में नियामक उपकरण' विषयों पर तीन व्याख्यान दिए। 16, 17 और 19 जनवरी 2024.

आमंत्रित व्याख्यान

- नागपुर के राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में 'सार्वजनिक वित्त और नीति' पर पांच-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में 'मौद्रिक अर्थशास्त्र' पर व्याख्यान दिया। 4 जुलाई 2023.

- इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएमपीआरआई), नई दिल्ली में 'डेटा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन' पर दो महीने के सर्टिफिकेट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 'राज्य बजट और सार्वजनिक वित्त' पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 15 जुलाई 2023.
- नई दिल्ली के नीति अनुसंधान और शासन केंद्र में 'सार्वजनिक नीति के मूल सिद्धांत' (तीसरा संस्करण) पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के भाग के रूप में 'सार्वजनिक वित्त और बजट की समझ बनाना' पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 28 अक्टूबर 2023.
- भारती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय की इकोनॉमिक्स सोसाइटी द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के भाग के रूप में 'भारतीय अर्थव्यवस्था: विकास के लिए चुनौतियों और संभावनाओं को नेविगेट करना' पर एक व्याख्यान दिया। 30 अक्टूबर 2023.
- हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के वित्त और अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति: संभावनाएँ और चुनौतियाँ' पर व्याख्यान दिया। 2 दिसंबर 2023.
- बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए 'प्रगति के लिए बजट' पर बजट के बाद आयोजित चर्चा में व्याख्यान दिया। 6 फरवरी 2024.
- दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में 'बजट और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव' विषय पर व्याख्यान दिया। 12 फरवरी 2024.
- सरकारी लेखा और वित्त संस्थान, लेखा महानियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'सरकारी लेखा और वित्तीय प्रबंधन' पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए आयोजित आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'मैक्रो-इकोनॉमिक पैरामीटर: हालिया रुझान (जीडीपी आदि)' पर व्याख्यान दिया। 13 फरवरी 2024.
- आईएमपीआरआई, नई दिल्ली में एक महीने के इमर्सिव ऑनलाइन परिचयात्मक प्रमाणपत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 'भारत के सार्वजनिक वित्त में प्रमुख रुझान और मुद्दे' पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 8 मार्च 2024.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एनआईपीएफपी में 'भारत कैसा प्रदर्शन कर रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्य-वर्षीय मैक्रो आर्थिक समीक्षा' पर आयोजित चर्चा में पैनलिस्ट । 11 अगस्त 2023.
- जीडी गोयनका विश्वविद्यालय के परास्नातक और स्नातक छात्रों के नए बैच के लिए 'मानविकी और सामाजिक विज्ञान में कैरियर के अवसरों' पर ऑनलाइन चर्चा में पैनलिस्ट । 4 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में एक आंतरिक संकाय संगोष्ठी में 'विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में रिबाउंड को डिकोड करना' पर एक पत्र प्रस्तुत किया । 22 जनवरी 2024.
- आदित्य बिड़ला समूह द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित एबीजी फॉरेक्स और ट्रेजरी कॉन्फ्रेंस 'इको विस्टा - शेपिंग पर्सपेक्टिव्स फॉर एक्सीलेंस' में 'भारत में मैक्रो थीम' पर एक वक्ता के रूप में भाग लिया । 25 जनवरी 2024.
- 'अंतरिम बजट, 2024' पर अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता द्वारा आयोजित चर्चा में पैनलविद। 5 मार्च 2024.
- कार्नेगी इंडिया द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 'राजनीतिक अर्थव्यवस्था संवाद, 2024' में 'मुख्य कारक बाजार सुधारों पर गतिरोध को तोड़ना' पर चर्चा में पैनलविद। 11-12 मार्च 2024.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों मे सदस्यता

- आईएमपीआरआई, नई दिल्ली में विजिटिंग सीनियर फेलो (मानद)।
- आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के लिए 'अमृत काल के लिए अवसंरचना के वर्गीकरण और वित्तपोषण' के लिए पृष्ठाधार टिप्पण पर एनआईपीएफपी की ओर से आर. कविता राव के साथ संयुक्त रूप से टिप्पणी की । 18 जुलाई 2023.

मुकेश कुमार आनंद

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति - प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सब्सिडी: वर्गीकरण और भारत में अभ्यास' पर व्याख्यान दिया। 26 मई 2023.
- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए आयोजित 15वें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कृषि की लागत पर जीवाश्म ईंधन की कीमत वृद्धि का प्रभाव - एक इनपुट-आउटपुट अनुप्रयोग' पर व्याख्यान दिया। 12 जून 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सब्सिडी: वर्गीकरण और भारत में अभ्यास' पर व्याख्यान दिया। 20 सितंबर 2023।
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लए 'राजकोषीय नीति-प्रबंधन और उभरते मुद्दों' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'पेंशन और सब्सिडी - व्यय और सुधार' पर व्याख्यान दिया। 7 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस, एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'वृद्धावस्था आय सहायता पर सार्वजनिक व्यय' पर एक व्याख्यान दिया। 20 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवाओं (एमएफए) के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करना' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'पेंशन प्रणाली पर सार्वजनिक व्यय - मिजोरम, भारत, राज्य स्तर पर सुधार विकल्प' पर व्याख्यान दिया। 8 जनवरी 2024.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से 'राजकोषीय नीति - प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम निदेशक/समन्वयक। 24-26 मई 2023.

- अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से एनआईपीएफपी में 'राजकोषीय नीति-प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम निदेशक/समन्वयक। 4-8 दिसंबर 2023.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- रेफरी, *स्प्रिंगर, जर्नलऑफसोशलएंडइकोनॉमिकडेवलपमेंट*।

रॉली कुकरेजा

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए 15वें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'प्रभाव मूल्यांकन' पर दो व्याख्यान दिए। 14 जून 2023.
- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बाजार की विफलता और विनियमन' पर व्याख्यान दिया। 19 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति - प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बाजार और नियामक: विफलताएं, सुधार' पर व्याख्यान दिया। 8 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस के प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बाजार विफलताओं' पर व्याख्यान दिया। 18 दिसंबर 2023.

बैठकों/सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एनआईपीएफपी में आयोजित आंतरिक संगोष्ठी में 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण: अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से अंतर्दृष्टि' विषय पर मीता चौधरी के साथ संयुक्त रूप सेप्रस्तुतीकरण पेश किया। 29 मई 2023.
- एनआईपीएफपी में 'बेहतर परिणामों के लिए स्वास्थ्य वित्तपोषण के केंद्र-राज्य संरेखण' पर आयोजित वार्ता में 'स्थानीय निकायों के माध्यम से पंद्रहवें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदान' पर प्रस्तुतीकरण पेश किया। 24 नवंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में रामलाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इन-कैंपस रेडियो तरंग के लिए एक सामुदायिक रेडियो शो में 'राजनीतिक अर्थव्यवस्था' पर एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। 19 जुलाई 2023.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- *इंडियनइकोनॉमिकजर्नल* के लिए समीक्षक।

माल्विका महेश

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए 15वें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'वित्तीय समावेशन: अर्थ और उपाय' पर व्याख्यान दिया। 15 जून 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति - प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'लिंग उन्नति: आरक्षण, समावेशन, बजट, सशक्तिकरण' पर व्याख्यान दिया। 8 दिसंबर 2023.

बैठकों/सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक। 18-22 सितंबर 2023.

पियाली दास

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन' पर एक व्याख्यान दिया। 18-22 सितंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति-प्रबंधन और उभरते मुद्दों' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन' पर व्याख्यान दिया। 4-8 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए 'सार्वजनिक ऋण में अवधारणाएं और मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 11-15 दिसंबर 2023.

आमंत्रित व्याख्यान

- अशोका विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'अमेरिका के लिए राजकोषीय कुशन की मात्रा निर्धारित करना' विषय पर व्याख्यान दिया। 22 नवंबर 2023.

बैठकों/सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली में आयोजित विंटर स्कूल 2023 में 'राजकोषीय प्रभुत्व और संप्रभु ऋण की इष्टतम परिपक्वता संरचना' पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 14-16 दिसंबर 2023.

रेशम नागपाल

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित 'राजकोषीय नीति- प्रबंधन और उभरते मुद्दों' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'ग्रीन बजटिंग' पर व्याख्यान दिया। 7 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस, एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'ग्रीन बजटिंग' पर व्याख्यान दिया। 21 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवाओं (एमएफए) के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत करना' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'ग्रीन बजटिंग' पर व्याख्यान दिया। 11 जनवरी 2024.

बैठकों/सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) और इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी द्वारा डीएसई, दिल्ली में आयोजित विंटर स्कूल 2023 में 'प्लांट-स्तर पर तकनीकी परिवर्तन और क्षेत्रीय सीमांत कमी लागत का प्रभाव: क्या अंत साधनों को सही ठहराता है?' पर पत्र प्रस्तुत किया। 14-16 दिसंबर 2023.
- इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में आयोजित एशिया मीटिंग में 'प्लांट-स्तर पर तकनीकी परिवर्तन और क्षेत्रीय सीमांत कमी लागत का प्रभाव: क्या अंत साधनों को सही ठहराता है?' पर पत्र प्रस्तुत किया। 13-14 जनवरी 2024.
- सीआईटीडी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'अर्थशास्त्र अनुसंधान में हालिया विकास: सिद्धांत और साक्ष्य' पर दो-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'सीमांत कमी लागत और संतुलन परमिट मूल्य पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव: ढलान और स्तर प्रभाव' पर पत्र प्रस्तुत किया। 8 मार्च 2024.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- *इंडियन इकोनॉमिक जर्नल, सेज पब्लिकेशन्स* के लिए समीक्षक।
- आजीवन सदस्य, भारतीय इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स सोसायटी।

आकांक्षा श्रवण

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) के सेवारत अधिकारियों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए एनआईपीएफपी में डीओपीटी, भारत सरकार के सहयोग से 'राजकोषीय नीति- प्रबंधन और उभरते मुद्दे' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'व्यापार चक्र समन्वय की भूमिका' पर एक व्याख्यान दिया। 8 दिसंबर 2023.
- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'व्यापार नीति और भुगतान संतुलन' पर एक व्याख्यान दिया। 13 दिसंबर 2023.

दिनेश कुमार नायक

बठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और पीईएफए सचिवालय द्वारा एडीबी, मनीला, फिलीपींस में आयोजित 2023 सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही (पीईएफए) फ्लैगशिप प्रशिक्षण सम्मेलन 'पीएफएमइन एशिया' में भाग लिया। 8-10 नवंबर 2023.
- ओडिशा के संबलपुर में भारतीय अर्थमितीय सोसायटी (टीआईईएस), गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'आर्थिक और वित्तीय अनुसंधान में नई सीमाएं' पर दो-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'चालू खाता और राजकोषीय खाता शेष के बीच संबंध: भारतीय संदर्भ में अनुभवजन्य विश्लेषण और नीतिगत निहितार्थ' पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 30-31 जनवरी 2024.
- हावर्ड विश्वविद्यालय, न्यू ऑरलियन्स, लुइसियाना, यूएस द्वारा आयोजित 'एसटीईएएमईशिक्षा में व्यावसायिक विकास' पर राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन फुल एसटीईएएम अहेड सम्मेलन में भाग लिया। 7-10 मार्च 2024.

श्रीहरि नायडू ए.

आमंत्रित व्याख्यान

- चेन्नई के मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पब्लिक फाइनेंस सेंटर में 'पब्लिक फाइनेंस' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण' पर व्याख्यान दिया। 3- 14 जुलाई 2023.
- क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, दिल्ली में 'अंतरिम केंद्रीय बजट 2024' पर व्याख्यान दिया। 31 जनवरी 2024.
- दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में 'अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 और अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर व्याख्यान दिया। 16 फरवरी 2024.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एनआईपीएफपी में राज्य फोरम 2023 में 'भारत में उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय स्थान और सब्सिडी' पर अमरनाथ एच.के. और स्मृति बनती द्वारा सह-लिखित एक पत्र प्रस्तुत
- नीति आयोग, नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर नीति सारांश प्रस्तुत किया। 15 जनवरी 2024.
- एनआईपीएफपी में 'बेहतर परिणामों के लिए स्वास्थ्य वित्तपोषण के केंद्र-राज्य संरेखण' पर आयोजित वार्ता में भाग लिया। 23-24 नवंबर 2023.
- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली में पांच-दिवसीय 'टाइम सीरीज़ और पैनल डेटा' कार्यशाला में भाग लिया। 28 फरवरी - 3 मार्च 2024.
- एनआईपीएफपी में आयोजित आंतरिक संगोष्ठी में 'कर्नाटक में बजटीय सब्सिडी' पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 29 मई 2023.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- *जर्नल ऑफ मिलेनियल एशिया*, सेज पब्लिकेशन्स के लिए समीक्षक।
- *इंडियन इकोनॉमिक जर्नल*, सेज पब्लिकेशन्स के लिए समीक्षक।

भाबेश हज़ारिका

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में मिजोरम सरकार के वित्त और लेखा सेवाओं (एमएफए) के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और बजट प्रबंधन को मजबूत बनाने' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राज्य वित्त में सर्वोत्तम प्रथाओं' पर एक व्याख्यान दिया। 12 जनवरी 2024.

आमंत्रित व्याख्यान

- वाणिज्य विभाग, गड़गांव कॉलेज, सिमालुगुड़ी, असम द्वारा आयोजित 'केंद्रीय बजट 2023-24' पर एक राष्ट्रीय वेबिनार में व्याख्यान दिया। 6 मार्च 2024.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- हॉवर्ड यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफ़ न्यू ऑरलियन्स, लुइसियाना, यू.एस. द्वारा आयोजित 'एसटीईएएम विषयों में हाशिए पर पड़े वर्गों का समावेश' पर नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) फुल एसटीईएएम अहेड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। 7-10 मार्च 2024.
- इंदौर, मध्य प्रदेश में 'जी-20 शेरपा ट्रैक एंड इंडिया: चुनौतियां, अवसर और एसडीजी हासिल करने के लिए रोडमैप' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के पैनलविद। 9 जून 2023.

आकाश गुप्ता

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एनआईपीएफपी में आयोजित एक आंतरिक संगोष्ठी में 'लोकतंत्र में नागरिकों की मतदान शक्ति' पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 15 फरवरी 2024.

एसके एमडी अज़हरुद्दीन

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एनआईपीएफपी में आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए 'सार्वजनिक वित्त' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुविधाप्रदाता। 11-15 दिसंबर, 2023.
- एनआईपीएफपी में बैंक ऑफ इंडिया (चरण-2) के अग्रणी जिला बैंक प्रबंधकों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग के मुद्दे' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुविधाप्रदाता। 15-19 जनवरी, 2024.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- *इंडियन इकोनॉमिक जर्नल*, सेज पब्लिकेशन्स के लिए समीक्षक ।

अनुबंध

अनुबंध I – अध्ययनों की सूचि

पूर्ण किए गए अध्ययन

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
1	मध्य प्रदेश एफआरबी अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा 2019-20 और 2020-21 (जुलाई 2023 से मार्च 2024)	मध्य प्रदेश सरकार	प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
2	सिक्किम के लिए मध्यम अवधि की राजकोषीय योजनाएँ: 2023-24 से 2025-26 (अप्रैल 2023 से मई 2023)	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना
3	सिक्किम सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा (जनवरी 2023 से जून 2023 तक)	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
4	सिक्किम सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राज्य एफआरबीएमए अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा (मार्च 2024)	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
5	वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधान प्रभाग (अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक) (एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (डीईए-एमओएफ), भारत सरकार	आर. कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशीम कपूर, उत्सव सक्सेना, राम्या राजश्री कुमार, रितिका सिंह, सिमरन कौर, राधिका अग्रवाल, मधुर मेहता, कृति वट्टल, आनंदिता गुप्ता, फिरदौस अहमद मलिक, लता बालासुब्रमण्यम, प्रवीण सिंह, एस. भुवन कौशिक, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन, यशोवर्धन चतुर्वेदी, पुलकित शर्मा, अंकित सिंह, अनुकृति चौबे, आशीष राज और सुशील कुमार मोदी
6	अन्य बहुपक्षीय संस्थान प्रभाग (अप्रैल 2022 से मार्च 2024) (एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)	डीईए-वित्त मंत्रालय	आर.कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशीम कपूर, उत्सव सक्सेना, राम्या राजश्री कुमार, रितिका सिंह, सिमरन कौर, राधिका अग्रवाल, मधुर मेहता, कृति वट्टल, आनंदिता गुप्ता, फिरदौस अहमद मलिक, लता बालासुब्रमण्यम, प्रवीण सिंह, एस. भुवन कौशिक, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन, यशोवर्धन चतुर्वेदी, पुलकित शर्मा, अंकित सिंह, अनुकृति चौबे, आशीष राज और सुशील कुमार मोदी

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
7	सिक्का एवं मुद्रा प्रभाग (अप्रैल 2022 से मार्च 2024) (एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)	डीईए-वित्त मंत्रालय	आर.कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशीम कपूर, उत्सव सक्सेना, राम्या राजश्री कुमार, रितिका सिंह, सिमरन कौर, राधिका अग्रवाल, मधुर मेहता, कृति वट्टल, आनंदिता गुप्ता, फिरदौस अहमद मलिक, लता बालासुब्रमण्यम, प्रवीण सिंह, एस. भुवन कौशिक, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन, यशोवर्धन चतुर्वेदी, पुलकित शर्मा, अंकित सिंह, अनुकृति चौबे, आशीष राज और सुशील कुमार मोदी
8	वित्तीय स्थायित्व और साइबर सुरक्षा प्रभाग (अप्रैल 2022 से मार्च 2024) (एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)	डीईए-वित्त मंत्रालय	आर.कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशीम कपूर, उत्सव सक्सेना, राम्याराज श्रीकुमार, रितिका सिंह, सिमरन कौर, राधिका अग्रवाल, मधुर मेहता, कृति वट्टल, आनंदिता गुप्ता, फिरदौस अहमद मलिक, लता बाला सुब्रमण्यम, प्रवीण सिंह, एस. भुवन कौशिक, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन, यशोवर्धन चतुर्वेदी, पुलकित शर्मा, अंकित सिंह, अनुकृति चौबे, आशीष राज और सुशील कुमार मोदी
9	वित्तीय बाजार प्रभाग (अप्रैल 2022 से मार्च 2024)(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)	डीईए-वित्त मंत्रालय	आर.कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशीम कपूर, उत्सव सक्सेना, राम्या राजश्री कुमार, रितिका सिंह, सिमरन कौर, राधिका अग्रवाल, मधुर मेहता, कृतिवट्टल, आनंदिता गुप्ता, फिरदौस अहमद मलिक, लता बालासुब्रमण्यम, प्रवीण सिंह, एस. भुवन कौशिक, बेन्सी रामकृष्णन, निपुण वर्मन, यशोवर्धन चतुर्वेदी, पुलकित शर्मा, अंकित सिंह, अनुकृति चौबे, आशीष राज और सुशील कुमार मोदी
10	पूंजीगत व्यय पर डीईए परियोजना अगस्त 2023 से फरवरी 2024 (अप्रैल 2022 से मार्च 2024) (एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)	डीईए-वित्त मंत्रालय	प्रतापरंजन जेना और अभिषेक सिंह

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
11	संविधान के अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 74 के तहत राज्य सरकारों द्वारा संबंधित स्थानीय निकायों को वित्त के रुझान और हस्तांतरण तंत्र पर राज्यवार रिपोर्ट (अप्रैल 2022 से जनवरी 2024 तक) (एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)	डीईए-वित्त मंत्रालय	मनीष गुप्ता और प्रियांशी गर्ग
12	भारत में सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ और सामाजिक पेंशन पर सार्वजनिक व्यय (दिसंबर 2022) (एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)	डीईए-वित्त मंत्रालय	मुकेश कुमार आनंद और पुलकित कुमार शर्मा
13	राज्यों के स्वयं के कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व पर राज्य-स्तरीय विश्लेषण – वर्ष के दौरान डीईए-एमओएफ के लिए दो रिपोर्ट पूरी की गईं (अप्रैल 2022-मार्च 2024) (एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)	डीईए-वित्त मंत्रालय	भाबेश हजारिका, दिनेश कुमार नायक और अंकित सिंह
14	भारतीय सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी के लिए मैनुअल की तैयारी और तालिकाएँ तैयार करना (2022 से मार्च 2024 तक) (एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)	डीईए-वित्त मंत्रालय	अमरनाथ एच. के. और श्री हरिनायडू ए.
15	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की तृतीय-पक्ष पारदर्शिता लेखापरीक्षा: 2022-23 (जून-अक्टूबर 2023)	राजस्व विभाग (डीओआर), वित्त मंत्रालय ने एनआईपीएफपी (कल्याणार्थ) को यह कार्य सौंपा।	सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला
16	अल्कोहलिक पेय पर करों से राजस्व जुटाना (18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक)	यूनाइटेड किंगडम सरकार के एफसीडीओ ने परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहयोग दिया।	आर. कविता राव, शिवानी बडोला और विवेक जाधव
17	भारतीय राज्यों में यात्री और माल कर (पीजीटी) की राजस्व क्षमता (18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक)	यूनाइटेड किंगडम सरकार के एफसीडीओ ने परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहयोग दिया।	आर. कविता राव, शिवानी बडोला और विवेक जाधव
18	प्रमुख भारतीय राज्यों के लिए कितना ऋण इष्टतम है? आर्थिक विकास बनाम ऋण स्थिरता (अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक)	यूनाइटेड किंगडम सरकार के एफसीडीओ ने परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के	रुद्राणीभट्टाचार्य, सी. प्रशांत, आर. कविता राव

		अध्ययन के लिए सहयोग दिया।	
क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
19	राज्यों के ऋण और बॉन्ड बाज़ारों का विश्लेषण (18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक)	यूनाइटेड किंगडम सरकार के एफसीडीओ ने परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहयोग दिया।	राधिका पांडेय, उत्सव सक्सेना, मधुर मेहता, बेन्सी रामकृष्णन, निपुनावर्मनंद, कृति वट्टल
20	राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के संदर्भ में स्पष्ट सब्सिडी और राजकोषीय स्थान को परिभाषित करना (18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक)	यूनाइटेड किंगडम सरकार के एफसीडीओ ने परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहयोग दिया।	अमरनाथ एच.के., स्मृति बनाती और मीना
21	सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी राज्यों की आवश्यकताएं (18 सितंबर 2023 से 15 अप्रैल 2024)	यूनाइटेड किंगडम सरकार के एफसीडीओ ने परियोजना संख्या 400047 के तहत सोलहवें वित्त आयोग के लिए भारत के राजकोषीय मुद्दों के अध्ययन के लिए सहयोग दिया।	मनीष गुप्ता, मालविका महेश और एसके मोहम्मद अज़हरुद्दीन
22	चयनित राज्यों (ओडिशा और तमिलनाडु) में सार्वजनिक निवेश के प्रबंधन की समीक्षा (मार्च 2023 से जून 2023)	विश्व बैंक	सुप्रियो डे, लेखा चक्रवर्ती, आर.कविता राव, पियाली दास, मयूराक्षी सिन्हा, सीमा मौर्य और दिव्या रुद्र
23	ओडिशा में बाल संरक्षण की सार्वजनिक व्यय समीक्षा (अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023)	यूनिसेफ	लेखाचक्रवर्ती, अमनदीप कौर, जितेश यादव और बालामुरली बी.
24	राज्य स्तर पर स्पष्ट बजटीय सब्सिडी का युक्तिकरण (नवंबर 2023)	नीति आयोग	अमरनाथ एच.के., श्री हरि नायडू ए., मिताली गुरुदत्ता, किशन, आशीष राज और रोहित दत्ता
25	भारतीय राज्यों में राज्य वित्त आयोग के कामकाज की समीक्षा और मूल्यांकन (2024)	यूनिसेफ इंडिया	मनीष गुप्ता

चल रहे अध्ययन

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
1	उत्तराखंड राज्य के लिए सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही (पीईएफए) आकलन (अप्रैल 2023 से जून 2024 तक)	उत्तराखंड सरकार	प्रतापरंजन जेना, दिनेश कुमार नायक और अभिषेक सिंह
2	मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का कर संग्रह, राजस्व और विभिन्न अन्य मापदंडों पर अध्ययन (मार्च 2024- जारी)	मध्य प्रदेश सरकार	सच्चिदानंद मुखर्जी, शिवानी बडोला और विवेक जाधव
3	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की तृतीय-पक्ष पारदर्शिता लेखापरीक्षा: 2022-23 (2023-24)	राजस्व विभाग (डीओआर), वित्त मंत्रालय ने एनआईपीएफपी को यह कार्य (कल्याणार्थ) सौंपा है।	सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला
4	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और स्थानीय सरकारी वित्त पर प्रशिक्षण मॉड्यूल की तैयारी (2021-जारी)	पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (पीडीयू-सीटीआरएफए), उत्तराखंड सरकार	मनीष गुप्ता
5	भारतीय राज्य आर्थिक और सामाजिक प्रदर्शन में क्यों भिन्न हैं? (जुलाई 2022- जारी)	स्व-प्रारम्भिक	रुद्राणी भट्टाचार्य, सुदीप्तो मुंडले (सीडीएस) और दिनेश कुमार नायक
6	कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दे और आधार वर्ष कर्नाटक के जीएसडीपी में परिवर्तन, (नवंबर 2023- जारी)	वित्त विभाग, कर्नाटक सरकार	अमेय सप्रे
7	चौथे राष्ट्रीय संचार, चौथे बीयूआर, प्रथम बीटीआर की तैयारी के लिए अग्रिम संघटन और सीबीआईटी परियोजना का कार्यान्वयन (2023- जारी)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भारत सरकार)	सुरंजलि टंडन
8	भारत में किगाली संशोधन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति रूपरेखा और रणनीति का विकास (2023- जारी)	ओजोन प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भारत सरकार)	सुरांजलि टंडन, अर्चिता श्रीधर, रिधि वर्मा और ज्योत्सना चिक्कारा
9	योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर बार-बार होने वाले चुनावों का प्रभाव (जनवरी 2023 से फरवरी 2024)	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	आर कविता राव, अजय नारायण झा, मालविका महेश और रोली कुकरेजा

10	वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण (ईएफसी) के लिए मैनुअल की तैयारी (अक्टूबर 2022 से मई 2024) *(एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम का भाग)*	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	अमरनाथ एच.के., श्रीहरि नायडू ए., आशीष राज और रोहित दत्ता
11	कर नीति एवं अनुपालन के प्रति दृष्टिकोण का आकलन (जनवरी 2023 से दिसंबर 2024)	स्व-प्रारंभिक	आर. कविता राव
12	पृथक भारतीय विनिर्माण उद्योगों के लिए प्रभावी कर दरों के निर्धारक (अगस्त 2023 से मई 2024 तक)	स्व-प्रारंभिक	आर. कविताराव और एस.के.एम.डी. अजहरुद्दीन
13	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निधियों के उपयोग में सुधार लाने में एकल नोडल खाते (एसएनए) की भूमिका को समझना (नवंबर 2022 से अगस्त 2024)	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)	मीता चौधरी, प्रीतम दत्ता और नित्या चुटानी
14	कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध के दोहरे आघातों के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की गतिशीलता (अगस्त 2023 से अगस्त 2024)	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली	रुद्राणी भट्टाचार्य और शेषाद्री बनर्जी (आरबीआई)
15	सामाजिक व्यय और व्यापक अर्थव्यवस्था: भारत के लिए नीति सिमुलेशन मॉडल (अक्टूबर 2023 और दिसंबर 2024)	एनआईपीएफपी अनुदान	सुकन्या बोस और सैकत बनर्जी
16	स्कूली शिक्षा में जेंडर बजटिंग (दिसंबर 2023 और सितंबर 2024)	राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन (एनसीई)	सुकन्या बोस, एमडी यासीन (आईआईएचएस और एनआईपीएफपी), अर्चना (एनसीई) और नूपुर (एनसीई)
17	भारत में राज्य वित्त के मुद्दों पर पुनर्विचार: कुछ अनुभवजन्य जांच (नवंबर 2021-जारी)	स्व-प्रारंभिक	दिनेश कुमार नायक और भावेश हजारिका
18	सार्वजनिक व्यय, शासन और सतत विकास में क्षेत्रीय असमानता: असम में जिला स्तरीय विश्लेषण - आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित (अप्रैल 2022-जून 2024)	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	भावेश हजारिका और अंकित सिंह
19	भारत में लिंग बजट के आकलन के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (जनवरी 2024-जारी)	स्व-प्रारंभिक	भावेश हजारिका

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
20	एमओएचयूए-एनआईपीएफपी	आवासन और शहरी कार्य	आर.कविता राव, मनीष गुप्ता, अमेय

	अनुसंधान कार्यक्रम, (नवंबर 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)	मंत्रालय (एमओएचयूए),भारत सरकार	सप्रे, आकाश गुप्ता, नीति गुप्ता, सिराज येजदानी और सौम्या अग्रवाल
21	राजकोषीय प्रभुत्व और संप्रभु ऋण प्रबंधन (2023- जारी)	स्व-प्रारंभिक	पियालीदास, चेतन घाटे और सुभदीप हलदर
22	अमेरिका के लिए राजकोषीय कुशन का परिमाणीकरण: 1960-2013 (2023-जारी)	स्व-प्रारंभिक	पियाली दास
23	यूनाइटेड किंगडम के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात का विघटन: 1984-2009 (2023- जारी)	स्व-प्रारंभिक	पियाली दास
24	ब्याज दर की दीर्घकालिक संरचना और आरबीआई मौद्रिक नीति रुख (जनवरी 2023 – दिसंबर 2024)	स्व-प्रारंभिक	लेखा चक्रवर्ती और नेहाला के. शिहाब
25	अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण (आईजीएफटी) के निर्धारकों का विश्लेषण (जनवरी 2024 – सितंबर 2024)	स्व-प्रारंभिक	लेखा चक्रवर्ती

आरंभ किए गए नए अध्ययन

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
1	त्रिपुरा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के संभावित उपायों पर अध्ययन (मार्च 2024-जारी)	त्रिपुरा सरकार	सच्चिदानंद मुखर्जी, आर कविता राव, शिवानी बडोला और विवेक जाधव
2	त्रिपुरा में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का पुनर्गठन (फरवरी 2024 से सितंबर 2024 तक)	त्रिपुरा सरकार	रुद्राणी भट्टाचार्य और आर. कविता राव
3	स्वयं के स्रोत राजस्व सृजन के लिए व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी (31 मार्च-जारी)	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	अमरनाथ एच. के., आकांक्षा श्रवण, सीमा मौर्य, मयूराक्षी मित्रा और स्मृति बनति
4	लिंग और मैक्रो इकॉनॉमिक्स (मई 2024-जारी)	यूएन विमेन	लेखा चक्रवर्ती
5	क्या भारत में मौद्रिक नीति संचरण का अपेक्षित चैनल मौजूद है ? पारंपरिक बनाम अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों की भूमिका (अप्रैल 2024-जारी)	एनआईपीएफपी	रुद्राणी भट्टाचार्य और शेषाद्री बनर्जी (आरबीआई)
6	एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम (अप्रैल 2024 से मार्च 2026)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, राधिका पांडे, रचना शर्मा, आशिम कपूर, मधुर मेहता, उत्सव सक्सेना, आनंदिता गुप्ता, यशोवर्धन चतुर्वेदी, निपुण वर्मन, मनाल शाह, अभिजीत सिंह, निकिता सिंह और एस. भुवन कौशिक
7	भारत में राज्य वित्त के साथ कारक विश्लेषण (मार्च 2024- जारी)	स्व-आरंभिक	पियाली दास

अनुबंध-II- एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र श्रृंखला

क्र. सं .	कार्यकारी पत्र का नाम	लेखक
1	भारतीय जीएसटी का राजस्व प्रदर्शन आकलन (अप्रैल 2023, संख्या 392)	सच्चिदानंद मुखर्जी
2	भारत की कॉर्पोरेट आयकर व्यवस्था में हाल के सुधार : औचित्य, प्रभाव और सुधार (अप्रैल 2023, संख्या 393)	सुप्रियो डे
3	प्रत्यक्ष कर मुकदमेबाजी प्रबंधन और वैकल्पिक विवाद समाधान (अप्रैल 2023, संख्या 394)	सुप्रियो डे
4	क्या भारत में मौद्रिक नीति मुद्रा स्फीति की उम्मीद को सहारा देती है ? (अप्रैल 2023, संख्या 395)	रुद्राणी भट्टाचार्य
5	राजकोषीय व्यवहार और जलवायु परिवर्तन भारत में प्रतिबद्धताएँ : बजट का विश्लेषण विश्वसनीयता (मई 2023, संख्या 396)	लेखा चक्रवर्ती, अजय नारायण झा, जितेश यादव, अमनदीप कौर और बाला मुरली बी.
6	राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और संकलन मुद्दे खाते सांख्यिकी: संक्षिप्त सारांश (जुलाई 2023, संख्या 397)	अमेय सप्रे और वैशाली भारद्वाज
7	बाल संरक्षण योजनाओं का ओईसीडीपी नीतिगत मूल्यांकन: ओडिशा, भारत से साक्ष्य (अगस्त 2023, संख्या 398)	लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर, जितेश यादव और बाला मुरली बी.
8	भारत में वित्तीय उत्तरदायित्व कानून से विचलन को समझना (अगस्त 2023, संख्या 399)	प्रतीक दत्ता, राधिका पांडेय, इला पटनायक और अजय शाह
9	भारत का प्रदर्शन? मध्य-वर्ष मैक्रोइकोनॉमिक समीक्षा (सितंबर 2023, संख्या 400)	रुद्राणी भट्टाचार्य, मनीष गुप्ता, दिनेश कुमार नायक और राधिका पांडे सुदीप्तो मुंडले के साथ सहयोजित
10	जी20 और जलवायु अनुकूल बजटिंग (सितंबर 2023, संख्या 401)	अमनदीप कौर, अजय नारायण झा और लेखा चक्रवर्ती
11	डीप डीकार्बोनाइजेशन और क्षेत्रीय इक्विटी (अक्टूबर 2023, संख्या 402)	संजय मित्रा और रोहित चंद्रा
12	भारतीय जीएसटी का वितरणात्मक प्रभाव (अक्टूबर 2023, संख्या 403)	सच्चिदानंद मुखर्जी
13	लिंग समानता के लिए जीडीपी और सार्वजनिक नीतियों से परे : एशिया प्रशांत में लिंग बजट (दिसंबर 2023, संख्या 404)	लेखा चक्रवर्ती
14	जीएसटी व्यवस्था में बदलाव से भारत में मुद्रास्फीति पर क्या असर पड़ा? (फरवरी 2024, संख्या 405)	रुद्राणी भट्टाचार्य

क्र. सं .	कार्यकारी पत्र का नाम	लेखक
15	कॉप-28 और पर्यावरण संघवाद: उभरती अर्थव्यवस्था, भारत से अनुभवजन्य साक्ष्य (फरवरी 2024, संख्या 406)	लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर, रंजन कुमार मोहंती, दिव्य रंगानंद संजनादास
16	राजकोषीय नियम और ऊर्जा संक्रमण: भारतीय राज्यों में निष्कर्षण कर उछाल का अनुमान लगाना (मार्च 2024, संख्या 407)	लेखा चक्रवर्ती और इमैनुएल थॉमस
17	यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र की संभावित विवक्षाएं (मार्च 2024, संख्या 408)	आनंदिता गुप्ता, राधिका पांडे और संहिता सपटनेकर

अनुबंध III:एनआईपीएफपी: आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला

क. सं.	शीर्षक	समन्वयक	तारीख और स्थान
1	'जी20@2023: भारतीय अध्यक्ष पद के लिए रोडमैप' पर वी. श्रीनिवास (आईएएस), सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संगोष्ठी।	अमेय सप्रे	4 मई 2023, एनआईपीएफपी
2	अशोका यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के विजिटिंग प्रोफेसर गुरबचन सिंह द्वारा 'एक सुलक्षित ब्याज दर नीति की ओर' पर संगोष्ठी	अमेय सप्रे	24 मई 2023, एनआईपीएफपी
3	मेट्रो रेल परियोजनाओं की वित्तीय स्थिरता पर के.वी. प्रताप, आईईएस द्वारा संगोष्ठी ।	अमेय सप्रे	17 जुलाई 2023, एनआईपीएफपी
4	आईआईटी दिल्ली के पब्लिक पॉलिसी स्कूल में कार्यरत प्रोफेसर संजय मित्रा और भारत में ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और मुख्य रूप से राज्य पूंजीवाद पर काम करने वाले एक राजनीतिक वैज्ञानिक और आर्थिक इतिहासकार रोहित चंद्रा द्वारा 'गहन डी कार्बोनाइजेशन और क्षेत्रीय समानता' पर संगोष्ठी।	अमेय सप्रे	23 अगस्त 2023, एनआईपीएफपी
5	एनआईपीएफपी आंतरिक सेमिनार श्रृंखला IV, रुद्राणी भट्टाचार्य द्वारा 'क्या भारत में मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की उम्मीदों को सहारा देती है' पर चर्चा।	अमेय सप्रे	28 अप्रैल 2023, एनआईपीएफपी
6	एनआईपीएफपी आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला वी, श्री हरिनायडू ए. द्वारा 'कर्नाटक में बजटीय सब्सिडी: मुद्दे और चिंताएँ' पर वार्ता और रोली कुकरेजा द्वारा 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण: अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से अंतर्दृष्टि' पर मीता चौधरी के साथ उनके संयुक्त कार्य पर वार्ता।	अमेय सप्रे	29 मई 2023, एनआईपीएफपी
7	एनआईपीएफपी आंतरिक सेमिनार श्रृंखला VI, राधिका पांडे द्वारा 'विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में पुनरुत्थान को डिकोड करना' पर वार्ता।	आकांक्षा श्रवण	29 जनवरी 2024, एनआईपीएफपी
8	एनआईपीएफपी आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला VII, आकाश गुप्ता द्वारा 'लोकतंत्र में नागरिकों की वोटिंग शक्ति' पर वार्ता।	आकांक्षा श्रवण	15 फरवरी 2024, एनआईपीएफपी
9	एनआईपीएफपी आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला VIII, सुकन्या बोस और सैकत बनर्जी द्वारा 'मानव विकास और वितरण' पर व्याख्यान।	आकांक्षा श्रवण	21 मार्च 2024, एनआईपीएफपी

अनुबंध IV: शासी निकाय के सदस्यों की सूची

शासी निकाय ने अपनी 14 मार्च, 2024 को हुई बैठक सं. 117 में निकाय का पुनर्गठन आगे और 4 वर्ष के लिए अर्थात 5 अप्रैल, 2024 से 4 अप्रैल, 2028 तक किया।

1 अगस्त 2023 की स्थिति के अनुसार शासी निकाय

डा. उर्जित पटेल — **अध्यक्ष**
एनआईपीएफपी
18/2 सत्संग विहार मार्ग
विशेष संस्थागत क्षेत्र
नई दिल्ली- 11 0067

<u>नियम 7(ख)(i) के अंतर्गत</u>
<u>वित्त मंत्रालय के तीन नामिती</u>

श्री संजय मल्होत्रा — **सदस्य**
राजस्व सचिव
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
कमरा नं. 128-ए, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001

श्री अजय सेठ, आईएएस — **सदस्य**
सचिव (आर्थिक कार्य)
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
कमरा नं. 130, नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

डा. वी. अनंता नागेश्वरन — **सदस्य**
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
कमरा नं. 132-ए, नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली 110001

<u>नियम 7(ख)(ii) के अंतर्गत</u>
<u>भारतीय रिजर्व बैंक का एक नामिती</u>

डा. राजीव रंजन — **सदस्य**
कार्यकारी निदेशक
मौद्रिक नीति विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
24वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट,मुंबई-400 001

नियम 7(ख)(iii) के अंतर्गत
योजना आयोग का एक नामिती

डॉ. प्रवाकर साहू **सदस्य**
वरिष्ठ लीड (आर्थिक और वित्त)
कमरा नं. 216
नीति आयोग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001.

नियम 7(ख)(iv) के अंतर्गत
प्रायोजक राज्य सरकारों के तीन नामिती

श्री एन. मुरुगनंदम, आईएएस **सदस्य**
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
तमिलनाडु सरकार सचिवालय
चेन्नई – 600 009

श्री शाश्वत मिश्रा, आईएएस प्रधान सचिव **सदस्य**
वित्त विभाग
ओडिशा सरकार,
ओडिशासचिवालयसेवा भवन
भुवनेश्वर -751001

श्री जे.पी गुप्ता, आईएएस **सदस्य**
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
गुजरात सरकार
ब्लॉक नं. 4/5, नया सचिवालय
गांधीनगर – 382 010

नियम 7(ख)(vi) के अंतर्गत
आईसीआईसीआई बैंक का एक नामिती

श्री बी. प्रसन्ना **सदस्य**
प्रधान– ग्लोबल मार्केट्स
आईसीआईसीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक टावर्स
बांद्रा-कुर्ला परिसर, बांद्रा पूर्व
मुंबई-400 051

<u>नियम 7(ख)(vii) के अंतर्गत</u>
<u>संस्थाओं के दो नामिती</u>

श्री दीपक सूद **सदस्य**
महासचिव
एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
चौथा तल, वाईएमसीए कल्चरल सेंटर एंड लाइब्रेरी बिल्डिंग,
1 जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

डॉ. अनीश शाह **सदस्य**
अध्यक्ष
फेडेरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
फेडेरेशन हाउस, 1, तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली -110 001

<u>नियम 7(ख)(viii) के अंतर्गत</u>
<u>तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री</u>

डा. माला लालवानी **सदस्य**
प्रोफेसर
मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई
विश्वविद्यालय
विद्यानगरी परिसर, कलीना
सांताक्रूज़ (पूर्व)
मुंबई- 400 098

डा. एम. गोविंद राव **सदस्य**
पूर्व निदेशक, एनआईपीएफपी,
8बी, शोभा एमेराल्ड, जक्कुर,
बेंगलूर-560064

डा. ज्योत्स्ना जालान **सदस्य**
अर्थशास्त्र प्रोफेसर
सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेज़, कलकत्ता
आर–1, बाईशनाबघाटा पाटुली टाउनशिप,
कोलकाता – 700 094

<u>नियम 7(ख)(ix) के अंतर्गत</u>
<u>सहयोगी संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि</u>

डा. पूनम गुप्ता **सदस्य**
महानिदेशक
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च

11, परिशिला भवन
आई.पी. एस्टेट, रिंग रोड
नई दिल्ली – 110 002

डॉ. श्रीनिवास चोक्काकुला **सदस्य**
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च
धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-110 021

नियम 7(ख)(x) के अंतर्गत
शासी निकायों से सहयोजित किए जाने वाले दो सदस्य

सीए सुश्री केमिशा सोनी **सदस्य**
आईसीएआई परिषद की सदस्य
404, मेगनेट टावर,
6/1,न्यू प्लासिया इंदौर–452001

नियम 7(ख)(xi) के अंतर्गत
संस्थान का निदेशक (पदेन)

डा. आर. कविता राव **सदस्य**
निदेशक, एनआईपीएफपी,
नई दिल्ली

नियम 7(ख)(xii) के अंतर्गत
संस्थान का एक प्रोफेसर चक्रानुक्रम में

डॉ. मीता चौधरी **सदस्य**
प्रोफेसर
एनआईपीएफपी, नई दिल्ली

विशेष आमंत्रिती

श्री रवि अग्रवाल **सदस्य**
अध्यक्ष
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

श्री संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
वित्त मंत्रालय भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

सदस्य

अनुबंध V: समूल्य प्रकाशनों की सूची

1	**भारत में अप्रत्यक्ष कराधान की घटनाएं 1973-74,** आर जे चेलिया और आर.एन. लाल(1978) INR 10. हिंदी संस्करण(1981) INR 20
2	**भारतीय संघीय वित्त में रुझान और मुद्दे**,* आर जे चेलिया एंड एसोसिएट्स (एलाइड पब्लिशर्स) (1981) INR 60.
3	**बिहार में बिक्री कर प्रणाली**,* आर जे चेलिया और एम सी पुरोहित (सोमैया प्रकाशन) (1981) INR 80.
4	**राज्य सरकारों के कर प्रयास का मापन 1973-76**, आर जे चेलिया और एन सिन्हा (सोमैया प्रकाशन) (1982) INR 60.
5	**व्यक्तिगत आयकर का प्रभाव**, अनुपम गुप्ता और पवन के अग्रवाल (1982) INR 35.
6	**निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में संसाधन जुटाना**, विनय डी. लाल, श्रीनिवास मधुर और के के अत्री (1982) INR 50.
7	**वित्तीय प्रोत्साहन और कॉर्पोरेट कर बचत**, विनय डी. लाल(1983) INR 140.
8	**निजी ट्रस्टों का कर उपचार**, के. श्रीनिवासन(1983) INR 140.
9	**केंद्र सरकार का व्यय : विकास, संरचना और प्रभाव (1950-51 से 1977-78),** के एन रेड्डी, जेवीएम सरमा और एन. सिन्हा(1984) INR 80.
10	**चुंगी के विकल्प के रूप में प्रवेश कर**, एम.जी. राव(1984) INR 40 पेपरबैक, INR 80 हार्डकवर।
11	**सूचना प्रणाली और तमिलनाडु में बिक्री कर की चोरी**, आर जे चेलिया और एम सी पुरोहित (1984) INR 50.
12	**भारत में उत्पाद शुल्क की चोरी: तांबे, प्लास्टिक और सूती वस्त्रों के कपड़े का अध्ययन**, ए.बागची एट.अल. । (1986) INR 180.
13	**भारत में काली अर्थव्यवस्था के पहलू (जिसे 'ब्लैक मनी रिपोर्ट भी कहा जाता है)**, शंकर एन.आचार्य एंड एसोसिएट्स, आर.जे.चेलिया द्वारा योगदान के साथ (1986) पुनर्मुद्रण संस्करणINR 270.
14	**मुद्रा स्फीति लेखा और कॉर्पोरेट कराधान**, तापस कुमार सेन(1987) INR 90.
15	**पश्चिम बंगाल में बिक्री कर प्रणाली**, ए.बागची और एस.के.दास(1987) INR 90.
16	**ग्रामीण विकास भत्ता (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 CC)**: एक समीक्षा, एच.के.सोंधी और जे.वी.एम.सरमा(1988) INR 40.
17	**दिल्ली में बिक्री कर प्रणाली**, आर.जे.चेलिया और के.एन.रेड्डी (1988) INR 240.
18	**निवेश भत्ता (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 ए): एक अध्ययन**, जे.वी.एम.सरमा और एच.के. सोंधी (1989) INR 75 पेपर बैक, INR 100 हार्डकवर ।
19	**धर्मार्थ योगदान के लिए कर प्रोत्साहन के अनुकरणीय प्रभाव: भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का एक अध्ययन**, पवन के.अग्रवाल (1989) INR 100.
20	**भारत में डाक सेवाओं का मूल्य निर्धारण**, राघवेंद्र झा, एम.एन.मूर्ति और सत्यपॉल(1990) INR 100.
21	**भारत में घरेलू बचत- रुझान और मुद्दे**,# उमा दत्ता रॉय चौधरी और अमरेश बागची (सं.) (1990) INR 240.
22	**मध्य प्रदेश में बिक्री कराधान**,# एम.गोविंदा राव, के.एन.बालासुब्रमण्यम और वी.बी.तुलसीधर(विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) INR 125.
23	**मोडवैट का संचालन**,# ए.वी.एल.नारायण, अमरेश बागची और आर.सी. गुप्ता (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) INR 250.
24	**राजकोषीय प्रोत्साहन और संतुलित क्षेत्रीय विकास**: धारा 80 एच.एच.का मूल्यांकन, # पवन के. अग्रवाल और एच.के.सोंधी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) INR 195.
25	**चयनित देशों में प्रत्यक्ष कर: एक प्रोफ़ाइल (वॉल्यूम । और II)** INR 100.
26	**भारत में एल्युमीनियम उद्योग के लिए प्रभावी प्रोत्साहन मोनोग्राफ श्रृंखला-1**, बीगोल्डर(1991) INR 100.
27	**भारत में राजकोषीय संघवाद पर अनुसंधान का सर्वेक्षण मोनोग्राफ श्रृंखला- II**, एम. गोविदा राव आर.आर.जे.चेलिया (1991) INR 100.

28	**राजस्व और व्यय अनुमान : मूल्यांकन और कार्यप्रणाली**,# वी.जी.राव, अतुल सरमा द्वारा संशोधित और संपादित (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1992) INR 195.
29	**भारत में बिक्री कर प्रणाली : एक प्रोफाइल**(1991) INR 150
30	**भारत में राज्य वित्त #**, अमरेश बागची, जे.एल.बजाज और विलियम ए., बर्ड(सं.) (1992) INR 450.
31	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए राजकोषीय नीति**,# महेश सी. पुरोहित, सी. साई कुमार, गोपीनाथ प्रधान और ओ.पी. बोहरा (1992) INR 225.
32	**विनिर्माण क्षेत्र मोनोग्राफ श्रृंखला- III में आयात प्रतिस्थापन**, हाशिम एन.सलीम (1992) INR 150.
33	**भारत में बिक्री कर प्रणाली : एक प्रोफाइल** (1993) INR 150.
34	**नौवां वित्त आयोग: मुद्दे और सिफारिशें (कागजात का चयन) (1993)** INR 490.
35	**चयनित देशों में प्रत्यक्ष कर : एक प्रोफ़ाइल (खंड-III),** के. कन्नन और ममता शंकर द्वारा संकलित(1993)INR 80.
36	**आर्थिक विकास और जीवन स्तर में अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय बदलाव (मोनोग्राफ सीरीज-IV) (1993)**उमादत्तारॉयचौधरीINR 200.
37	**विकासशील देशों में कर नीति और योजना**,* अमरेश बागची और निकोलस स्टर्न (सं.) (1994) (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) INR 435.
38	**भारत में घरेलू व्यापार करों में सुधार: मुद्दे और विकल्प अध्ययन दल (1994)** INR 250.
39	**निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र: धन का सृजन और पुनर्जनन**, उमा दत्ता रॉय चौधरी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1996) INR 395.
40	**प्रदूषण को नियंत्रित करना : प्रोत्साहन और विनियम**, शेखर मेहता, सुदीप्तो मुंडले और यू. शंकर (सेज प्रकाशन) (1997) INR 250.
41	**भारत: नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कर नीति (1997-98 से 2001-02)**,# (वित्तीय संसाधन अध्यक्ष पार्थसारथी शोम पर संचालन समूह की करनीति पर कार्यसमूह की रिपोर्ट) (अध्यक्ष पार्थसारथी शोम) (सेंटैक्स प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड) (1997) INR 350.
42	**भारत में मूल्यवर्धित कर : एक प्रगति रिपोर्ट**,# पार्थसारथी शोम(सं.) (सेंटैक्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड) (1997) INR 250.
43	**राजकोषीय नीति सार्वजनिक नीति और शासन**,# पार्थसारथी शोम (सं.) (सेंटैक्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड) (1997) INR 400.
44	**भारत में सरकारी सब्सिडी**, डी.के.श्रीवास्तव और तापसके. सेन(1997) INR 285.
45	**पर्यावरण स्थिरता के लिए आर्थिक उपकरण**, यू. शंकर और ओम प्रकाश माथुर(1998) INR150.
46	**भारत: शहरी शासन की चुनौती**, ओम प्रकाश माथुर(सं.) (1999) INR 400.
47	**राज्य वित्तीय अध्ययन- असम**, डी.के. श्रीवास्तव, सौमेन चट्टोपाध्याय और टी.एस. रंगमन्नार(1999) INR 200.
48	**राज्य वित्तीय अध्ययन- पंजाब**, इंदिरा राजारमन, एच. मुखोपाध्याय और एच.के. अमरनाथ(1999) INR 200.
49	**राज्य वित्तीय अध्ययन- केरल**, डी. के. श्रीवास्तव, सौमेन चट्टोपाध्याय और प्रताप रंजन जेना(1999) INR 200.
50	**दिल्ली राजकोषीय अध्ययन**, ओम प्रकाश माथुर और टी.एस. रंगमन्नार (2000) INR 250.
51	**भारत में राजकोषीय संघवाद ग्यारहवें वित्त आयोग के समक्ष समसामयिक चुनौतियां मुद्दे**, डी.के. श्रीवास्तव(सं.) (हर आनंद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड) (2000) INR 695.
52	**राज्य वित्तीय अध्ययन- हरियाणा**, तापस के. सेन, आर. कविताराव(2000) INR 200
53	**सार्वजनिक धन का नियंत्रण : विकासशील देशों में राजकोषीय तंत्र**,* ए.प्रेमचंद(ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) (2000) INR 745.
54	**मूल्यवर्धित कर पर प्राइमर**,# आर.जे. चेलिया, पवन, के. अग्रवाल, महेश सी. पुरोहित और आर. कविता राव (हर आनंद पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड) (2001) INR 195.
55	**भारत में केंद्रीय बजटीय सब्सिडी**, डी.के. श्रीवास्तव और एच.के. अमरनाथ (2001) INR 170.

56	**राज्यनगर पालिका वित्तीय संबंधों के लिए दृष्टिकोण : विकल्प और परिप्रेक्ष्य**, ओम प्रकाश माथुर(2001) INR 200.
57	**व्यापार और उद्योग: एनआईपीएफपी-फोर्ड फाउंडेशन फेलो द्वारा निबंध,#** ए.के.गुहा, के.एल. कृष्णा और अशोक, के. लाहिरी (सं.) (विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड) (2001) INR 450.
58	**भारत के लिए स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण और विनियम: अनुमोदन और विकल्प,#** एस.पी. सिंह और अमरेश बागची आर.के. बजाज द्वारा योगदान के साथ (यू बी एस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड) (2002) INR 395.
59	**विदेशी उत्पादों की तुलना में घरेलू का भेदभावपूर्ण कर व्यवहार : एक आकलन**, पवन के. अग्रवाल और वी. सेल्वाराजू (2002) INR 200.
60	**नियमन का अभ्यास और राजनीति: भारतीय विद्युत में नियामक शासन**,* नवरोज के. दुबाशं और डी. नरसिम्हा राव (2007) INR 290.
61	**मानव विकास पर गरीबी की कमी से निपटना : मध्य प्रदेश में वित्तीय रणनीतियाँ (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्त पोषण)**, तापस के.सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और अनीत मुखर्जी(2007) INR 150.
62	**तमिलनाडु में मानव विकास का वितपोषण: उपलब्धि पर समेकित और निर्माण (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वितपोषण)**, तापस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और अनीत मुखर्जी (2008) INR 150.
63	**भारतीय संघ में स्वास्थ्य व्यय का अंतर-राज्यीय समानता**, एम. गोविंदा राव और मीता चौधरी (2008) INR 75.
64	**भारत में व्यय प्रबंधन के 50 वर्षों के इनकार के आराम क्षेत्र में फंस गया**, ए.प्रेमचंद(2008) INR 150.
65	**राजकोषीय विकेंद्रीकरण और जेंडर बजटिंग**, एम. गोविंदा राव, लेखा चक्रवर्ती, अमरेश बागची(2008) INR 250.
66	**वित्तीय सुधार, लगातार गरीबी और मानव विकास: उड़ीसा का मामला (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण)**, तापस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और प्रोतिया कुंडू(2008) INR 150.
67	**पश्चिम बंगाल में मानव विकास के सार्वजनिक वित्त पोषण पर वित्तीय बाधाओं से निपटना (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण) –** तापस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और प्रोतिवा कुडू(2009) INR 150.
68	**भारत के निम्न कार्बन आर्थिक विकास की संभावनाएं और नीतियां**, राम प्रसाद सेन गुप्ता(2010) INR 150.
69	**भारत में निम्न कार्बन और उच्च विकास प्राप्त करने के लिए नीतिगत साधन,** यू. शंकर (2010) INR 150.
70	**राजस्थान: आर्थिक और मानव विकास को समवर्ती रूप से बढ़ावा देना (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्त पोषण),** तापस के., सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010) INR 150.
71	**भारत: सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही-सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट,** प्रताप रंजन जेना (2010) INR 150.
72	**हिमाचल प्रदेश में सतत मानव विकास के लिए संसाधन (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तपस के. सेन, एच.के, अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीतदास (2010) INR 150.
73	**एक युवा राज्य का परिपक्वता में तेजी से संक्रमण: छत्तीसगढ़ में मानव विकास के लिए संसाधन (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास(2010) INR, 150.
74	**केरल में मानव विकास का वित्तपोषण: मुद्दे और चुनौतियाँ (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण)**, पिनाकी चक्रवर्ती, लेखा चक्रवर्ती, एच.के.अमरनाथ, और सोना मित्रा(2010) INR.150.
75	**अपने आर्थिक विकास के साथ पूरे महाराष्ट्र में मानव विकास का मिलान (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तापस के. सेन, अमरनाथ एच.के., मीता चौधरी और सुरजीत दास(2010) INR 150.
76	**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अव्ययित शेष और निधि प्रवाह तंत्र,** एन.आर.भानुमूर्ति, एच.के.अमरनाथ, अखिलेश वर्मा और आदर्श गुप्ता (2014) INR 200. (स्टॉक में: 98)
77	**राज्य के वित्त में उभरते मुद्दे चौदहवें वित्त आयोग के बादः राज्य बजट 2016-17 का विश्लेषण**, मनीष गुप्ता, लेखा चक्रवर्ती और पिनाकी चक्रवर्ती (2018). INR 200. (स्टॉक में: 163)
78	**राज्य के बजट 2017-18 का विश्लेषण : उभरते मुद्दे (विद्युत क्षेत्र के ऋण का प्रभाव- राज्य के वित्त पर उदय),**

	पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर (2018) INR 200. (स्टॉक में: 112)
79	**राज्य के बजट 2018-19 का विश्लेषण- प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ (बजट विश्वसनीयता और वित्तीय पूर्वानुमान त्रुटियाँ)** मनीष गुप्ता, लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर(2020). INR 200. (स्टॉक में: 98)
80	***आरटीई और संसाधन अपेक्षाएं : भावी मार्ग,*** सुकन्या बोस**,** प्रियंका घोष और अरविंद सरदाना (2020) INR 200.

*संबंधित प्रकाशकों के साथ सह-प्रकाशित/उपलब्ध।

* सह-प्रकाशित।

ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के खिलाफ प्रकाशन भेजे गए। डाकखर्च 80 रु. प्रति प्रति।

अनुबंध VI : एनआईपीएफपी संकाय द्वारा प्रकाशित सामग्री

(पुस्तकें, जर्नल, मोनोग्राफ और अन्य लोकप्रिय लेख)

आर.कविता राव

1. 'राज्यों का पूंजीगत व्यय: आशय बनाम उपलब्धियां', सम्मेलन-पत्र, राज्य फोरम 2023, 2-3 नवंबर 2023.
2. 'संसाधन जुटाने के तरीकों में विविधता लाना - सार्वजनिक वित्त, निजी निवेश, बहुपक्षीय संस्थान सामुदायिक वित्तपोषण' (सह-लेखक अजय नारायण झा और राधिका पांडे), प्रस्तावित एनईसी विज़न दस्तावेज़ 2027, जनवरी 2024 के लिए 'उत्तरपूर्वी राज्यों का सार्वजनिक वित्त: रूपांतरण 1 के लिए संसाधन ढूँढना' में।

अन्य क्रियाकलाप/लोकप्रिय लेखन

3. 'क्या ऑनलाइन गेमिंग के लिए कर व्यवस्था उचित है?' *बिजनेसलाइन*, 21 जुलाई 2023.
4. 'सरकार को पुरानी कर व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए', *इनफॉर्मिस्ट* को साक्षात्कार, 16 जनवरी 2024.
5. 'एक आश्वस्त और आशावादी रिपोर्ट', *बिजनेस स्टैंडर्ड*, 2 फरवरी 2024.

लेखा चक्रवर्ती

1. 'जी20 और जलवायु अनुकूल बजटिंग' (सह-लेखक अमनदीप कौर और अजय नारायण झा), एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 401, सितंबर 2023.
2. 'भारत में न्यायोचित परिवर्तन और राजकोषीय रुख: निष्कर्षण क्षेत्र की कर संवृद्धि का विश्लेषण' (सह-लेखक इमैनुएल थॉमस), कार्यकारी पत्र सं. 1047, लेवी इंस्टीट्यूट, अप्रैल 2024.
3. 'जलवायु परिवर्तन और राजकोषीय निशानेबाजी: एक उभरते देश, भारत से साक्ष्य' (सह-लेखक अजय नारायण झा, जितेश यादव, बालमुरली बी और अमनदीप कौर), कार्यकारी पत्र सं. 1023, लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, अन्नाडेल-ऑन-हडसन, न्यूयॉर्क wp_1023.pdf (levyinstitute.org), जुलाई 2023.
4. 'ओईसीडी नीति लागू करना भारत में बाल संरक्षण योजनाओं के लिए मूल्यांकन मानदंड' (सह-लेखक जितेश यादव, बालमुरली बी. और अमनदीप कौर), कार्यकारी पत्र सं. 1032, लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, अन्नाडेल-ऑन-हडसन, न्यूयॉर्क, अक्टूबर 2023.
5. 'सीओपी28 और पर्यावरण संघवाद: एक उभरती अर्थव्यवस्था, भारत से अनुभवजन्य साक्ष्य' (सह-लेखक अमनदीप कौर, रंजन कुमार मोहंती, दिव्यरंगन और संजना दास), कार्यकारी पत्र सं. 1040, लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, अन्नाडेल-ऑन-हडसन, न्यूयॉर्क, फरवरी 2024.
6. 'जीडीपी से परे और लैंगिक समानता के लिए सार्वजनिक नीतियां: एशिया प्रशांत में लैंगिक बजट', चर्चा पत्र, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (https://x.com/LSE_ID/status/1709510882533720521linktoLSEpaperLekha_Chakraborty_Beyond_GDP_and_Public_Poliicies_for_gender_equality_.docx (live.com)
7. 'भारत में पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण और राज्य स्तरीय बजटीय खर्च: फ्लाईपेपर प्रभाव विश्लेषण' (सह-लेखक अमनदीप कौर, रंजन कुमार मोहंती और दिव्य रंगन), इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 58 (14), 8 अप्रैल 2023.
8. 'जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन पर सार्वजनिक व्यय, और भारत से राजकोषीय निशाने बाजी साक्ष्य' (सह-लेखक अजय नारायण झा, अमनदीप कौर, जितेश यादव और बाल मुरली बी.), आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 58(51), 23 दिसंबर 2023.
9. 'जीडीपी और लैंगिक समानता के लिए सार्वजनिक नीतियों से परे एशिया प्रशांत में लैंगिक बजट', भारत में आर्थिक विकास (संपादक उमा कपिला), खंड 265.
10. एनआईपीएफपी माइमोग्राफ यूनिसेफ परियोजना रिपोर्ट।

अन्य क्रियाकलाप/लोकप्रिय लेखन

11. 'किसी को पीछे न छोड़ें: अंतरिम बजट के पीछे का दर्शन', *मनीकंट्रोल*, 2 फरवरी 2024.
12. 'निरंतर घाटे के उपयोग', *बिजनेसलाइन*, 2 फरवरी 2024.

13. 'अंतरिम बजट से क्या उम्मीद करें? बड़े कर छूट की संभावना नहीं, कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है', *मिंट*, 2 फरवरी 2024.
14. 'केंद्रीय बजट 2024: वैश्विक चुनौतियों के बीच, तर्कहीन उम्मीदों के लिए कोई जगह नहीं है', *मनीकंट्रोल*, 24 जनवरी 2024.
15. 'एमपीसी बैठक: बहुत सारे जोखिमों के बीच, नीति दरों में यथास्थिति का स्वागत है', *मनीकंट्रोल*, 9 दिसंबर 2023।
16. 'सोलहवां वित्त आयोग और "जीडीपी से परे" प्रतिमान', *मनीकंट्रोल*, 7 नवंबर 2023.
17. 'अर्थशास्त्र नोबेल और श्रमबल में महिलाएँ: नीति निर्माताओं को गोल्डिन के काम पर विचार क्यों करना चाहिए', *मनीकंट्रोल*, 10 अक्टूबर 2023.
18. 'ऋण स्थिरता: जी20 को विकास दर से कम ब्याज दरों की तलाश करनी चाहिए', *मनीकंट्रोल*, 25 अगस्त 2023.
19. 'राजस्व घाटे के लक्ष्य का पीछा क्यों करें?' *बिजनेसलाइन*, 15 अगस्त 2023.
20. 'राजकोषीय नियमों पर पुनर्विचार: परामर्श प्रक्रिया की आवश्यकता', *डेक्कन हेराल्ड*, 12 जून 2023.
21. '2000 रुपये का प्रतिबंध: व्यापार करने में आसानी में संक्रमणकालीन व्यवधान की संभावना', *मनीकंट्रोल,* 21 मई 2023.
22. 'युद्ध और संकट के समय मौद्रिक नीति बनाते समय केंद्रीय बैंकों को क्या विचार करना चाहिए',*मनीकंट्रोल*, 10 मई 2023.
23. 'हमें पुरानी पेंशन योजना पर बहस करने की आवश्यकता क्यों है – ओपीएस राजकोषीय स्थिरता और अंतर-पीढ़ीगत असमानताओं के बारे में चिंताएँ बढ़ाता है', *द हिंदू*, 5 अप्रैल 2023.
24. 'भारत की आर्थिक वृद्धि रिकवरी', पहली बार ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट (राष्ट्रीय सेवा प्रभाग: आकाशवाणी: सभी बाहरी सेवाएँ) के रूप में जारी किया गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 15 जून 2023.

प्रताप रंजन जेना

1. 'ग्रीन बजटिंग: भारत का अनुभव' (सह-लेखक रेशम नागपाल), सम्मेलन पत्र, *राज्य मंच 2023: एक संग्रह*, एनआईपीएफपी, नवंबर 2023.
2. 'भारत में नियोजित बजट को लागू करने की राज्यों की क्षमता: पीईएफए फ्रेमवर्क का उपयोग करके एक आकलन', *इंडियन इकनॉमिक जर्नल*, 0(0)। https://doi.org/10.1177/00194662241238575
3. 'भारत में संस्थागत गुणवत्ता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: एक अर्थमितीय विश्लेषण' (सह-लेखक निखिल कुमार कनोडिया और दीप्ति रंजन महापात्रा), *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, खंड 58(37), 16 सितंबर 2023.
4. 'भारतीय हवाई अड्डों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विश्लेषण: चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं' 26, *रवींद्र भारती पत्रिका,* खंड 26, रवींद्र भारती विश्वविद्यालय, जून 2023.

मीता चौधरी

1. 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई): डिजाइन रूपरेखा, उभरते पैटर्न और सरकार की लागत' (सह-लेखक प्रीतम दत्ता, द्वीपोबोटी ब्रह्मा, रुचिरा अग्रवाल, निशांत जैन, विपुल अग्रवाल, किरण गोपाल वास्का और सिद्धार्थ सेठी), कार्यकारी पत्र सं. 019, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, अगस्त 2023.

अन्य क्रियाकलाप/लोकप्रिय लेखन

2. 'रोगी के लिए एक अस्पताल' (सह-लेखक नित्या चुटानी और विस्मय बसु), *द इंडियन एक्सप्रेस,* 28 जुलाई 2023।

सच्चिदानंद मुखर्जी

1. 'भारतीय जीएसटी का वितरणात्मक प्रभाव', एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र संख्या 403, अक्टूबर 2023.
2. 'भारतीय जीएसटी का राजस्व प्रदर्शन आकलन', एनआईपीएफपी कार्यपत्र संख्या 392, अप्रैल 2023.
3. '2023-24 का राज्य बजट विश्लेषण: भारतीय राज्य वित्त की स्थिति', एमपीआरए पत्र संख्या 117925, जुलाई 2023.

4. 'भारत में कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) का राजस्व पूर्वानुमान' (सह-लेखक रुद्राणी भट्टाचार्य), *इंडियन इकनॉमिक रिव्यू*, खंड-। 58:329-349, 2023.https://doi.org/10.1007/s41775-023-00203-x
5. 'भारतीय राज्य वित्त पर जीएसटी की राजस्व विवक्षाएं', *इंडियाज़ कंटेम्पररी मैक्रोइकॉनोमिक थीम्स। इंडिया स्टडीज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स* (संपादक डी.के. श्रीवास्तव और के.आर. शनमुगम), स्प्रिंगर, सिंगापुर। https://doi.org/10.1007/978-981-99-5728-6_6, 23 नवंबर 2023।
6. 'वर्तमान दशक में भारत में राज्य वित्त की स्थिति', सम्मेलन पत्र, *स्टेट फोरम 2023: एक संग्रह,* 17-41, एनआईपीएफपी, नवंबर 2023.

अमरनाथ के.

1. 'भारत में राज्य स्तर पर सिकुड़ता राजकोषीय स्थान और इसका कल्याण व्यय और सब्सिडी पर प्रभाव' (सह-लेखक श्री हरि नायडू ए. और मिताली गुरदत्ता), *एफपीआई जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस*, 18 मई 2023.

मनीष गुप्ता

1. 'भारत का प्रदर्शन? मध्य-वर्षीय मैक्रोइकॉनोमिक रिव्यू' (सह-लेखक रुद्रानी भट्टाचार्य, दिनेश कुमार नायक और राधिका पांडे सुदीप्तो मुंडले के सहयोग से), एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र संख्या 400, सितंबर 2023। साथ ही, खंड 264:29-69, अकादमिक फाउंडेशन, 2023.
2. 'अर्थव्यवस्था की स्थिति: तिमाही आकलन और दृष्टिकोण-जनवरी-मार्च 2023' (सह-लेखक रुद्रानी भट्टाचार्य, सुदीप्तो मुंडले और राधिका पांडे), *इकनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया*(संपादक उमा कपिला), खंड 262:155-210, अकादमिक फाउंडेशन, 2023.

रुद्राणी भट्टाचार्य

1. 'क्या भारत में मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की उम्मीद को सहारा देती है?', एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 395, अप्रैल 2023.
2. 'भारत का प्रदर्शन? मध्य-वर्षीय आर्थिक समीक्षा' (सह-लेखक मनीष गुप्ता, राधिका पांडे, दिनेश कुमार नायक और सुदीप्तो मुंडले), एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 400, सितंबर 2023.
3. 'जीएसटी व्यवस्था में बदलाव ने भारत में मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित किया?' एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 405, फरवरी 2024.
4. 'भारत में कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) का राजस्व पूर्वानुमान' (सह-लेखक सच्चिदानंद मुखर्जी), *इंडियन इकनॉमिक रिव्यू*, खंड 58:329-349, दिसंबर 2023.
5. 'भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को एकीकृत करने में ई-एनएएम कितना प्रभावी है? प्याज बाजार से साक्ष्य', (सरबानी चौधरी के साथ सह-लेखक), *इकनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली*, खंड 58(35), 2 सितंबर 2023.
6. 'भारत का प्रदर्शन*?* मध्य-वर्षीय मैक्रोइकॉनोमिक रिव्यू' (सह-लेखक मनीष गुप्ता*,* राधिका पांडे*,* दिनेश कुमार नायक और सुदीप्तो मुंडले)*,* एनआईपीएफपी नीति संक्षिप्त संख्या *42,* सितंबर *2023.*
7. 'प्रमुख भारतीय राज्यों के लिए कितना ऋण इष्टतम है*?* आर्थिक विकास बनाम ऋण स्थिरता' (सह-लेखक सी. प्रशांत और आर. कविता राव)*,* माइमोग्राफ।
8. *8.* 'भुगतान संतुलन की स्थिति' (दिनेश कुमार नायक के साथ सह-लेखक)*, इकनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया - क्वार्टर्ली अपडेट,*खंड *262:204-210,* अकादमिक फाउंडेशन*,* नई दिल्ली।

सुकन्या बोस

1. 'शिक्षा का अधिकार और केंद्रीय बजट: नए सिरे से फोकस की आवश्यकता', *इकानॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली*, खंड 59 (10): 14-17, 9 मार्च 2024.

सुरंजलि टंडन

1. 'युद्ध और संकट के दौरान कर', संकट और पुनर्प्राप्ति के समय में कर कानून (संपादक डोमिनिक डी कोगन, एलेक्सिस ब्रासी और पीटर हैरिस), मई 2023.
2. 'भारत में अनिवार्य प्रकटीकरण नियम', अनिवार्य प्रकटीकरण नियम (संपादक जॉर्ज कोफ्लर एट अल।), अंतर्राष्ट्रीय राजकोषीय प्रलेखन ब्यूरो, जून 2023.
3. 'भारत का अंतिम तथ्य-खोज प्राधिकरण: स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण मुकदमेबाजी', *टैक्सनोट्स इंटरनेशनल*, 10 जुलाई 2023.
4. 'अंतर्राष्ट्रीय कर अभ्यास और ओईसीडी ढांचे के प्रकाश में सहकारी अनुपालन के लिए भारत के दृष्टिकोण की समीक्षा' (सह-लेखक मारियो मार्टिनी), *इंटरटैक्स*, खंड 51 (10): 667-681.
5. 'विकासशील देशों के लिए राशि', टैक्सनोट्स इंटरनेशनल, 23 अक्टूबर 2023।
6. 'कार्बन टैक्स फॉर ग्रीन ट्रांज़िशन' *न्यू रेंज एंड ऑर्थोडॉक्स कंसर्न इन इंटरनेशनल टैक्सेशन* में (एड. पार्थसारथी शोम), जनवरी 2024.

अन्य क्रियाकलाप/लोकप्रिय लेखन

7. 'आरबीआई की रिपोर्ट में भारत की भविष्य की धीमी कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई है', *मोंगाबे*, 7 जून 2023.
8. 'एंजल टैक्स: घरेलू और विदेशी निवेशकों के बीच भेदभाव क्यों?', एनडीटीवी प्रॉफिट, 16 जून 2023.
9. 'जलवायु वित्तपोषण को और अधिक समावेशी कैसे बनाया जाए', *बिजनेसलाइन,* 20 जून 2023.
10. 'नेटजीरो चैलेंज', *द इंडियन एक्सप्रेस*, 25 जून 2023.
11. 'यूरोप की कार्बन समस्या', *द इंडियन एक्सप्रेस*, 27 जुलाई 2023.
12. 'कर अंतर को कम करना', *द इंडियन एक्सप्रेस*, 16 सितंबर 2023.
13. 'कनाडा में ग्रीन ट्रांजिशन की उम्मीद वांछित गति से की जा सकती है, और, इससे भी अधिक, इसका भुगतान कौन करेगा?', *द इकोनॉमिक टाइम्स*, 26 अक्टूबर 2023.
14. 'कर संधि समस्या', *द इंडियन एक्सप्रेस*, 2 नवंबर 2023.
15. 'बजट 2024: भविष्य के कर सुधारों के लिए दिशा-निर्देश तय करना', *लाइव मिंट*, 2 फरवरी 2024.
16. 'भारत में ग्रीन इकोनॉमी की ओर उचित बदलाव जोर पकड़ रहा है', एलएसई ब्लॉग, 1 मार्च 2024.
17. 'आरबीआई और नेट-जीरो ट्रांजिशन - ग्रीन इंडिया के लिए एक रोडमैप', *द इंडियन एक्सप्रेस*, 8 मार्च 2024.

राधिका पांडे

1. 'यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र की संभावित विवक्षाएं' (सह-लेखक अनंदिता गुप्ता और संहिता सपटनेकर), एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 408, मार्च 2024.
2. 'तमिलनाडु पब्लिक फाइनेंस में विद्युत अवरोध' (सह-लेखक चार्मी मेहता, रेणुका साने और अजय शाह), फरवरी 2024. https://papers.xkdr.org/papers/MehtaPSS2024_tn_pf_electricity.pdf
3. 'भारत का प्रदर्शन? मध्य वर्षीय मैक्रोइकॉनोमिक रिव्यू' (सह-लेखक रुद्राणी भट्टाचार्य, मनीष गुप्ता और दिनेश कुमार नायक, सुदीप्तो मुंडले के सहयोग से), एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 400, सितंबर 2023.
4. 'भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधि से विचलन को समझना' (सह-लेखक प्रतीक दत्ता, इला पटनायक और अजय शाह), एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 399, अगस्त 2023.

अन्य क्रियाकलाप/लोकप्रिय लेखन

5. भारत में वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रास्फीति को समझना' (सह-लेखक रचना शर्मा और प्रमोद सिन्हा), एनआईपीएफपी ब्लॉग, 5 अप्रैल 2023.

6. 'अधिकाधिक वायदे, कम-खर्च: राज्य अपने बजट का कैसे उपयोग कर रहे हैं और यह उनके राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है?' (सह-लेखक रचना शर्मा), भारत में वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रास्फीति को समझना' (सह-लेखक रचना शर्मा और प्रमोद सिन्हा), एनआईपीएफपी ब्लॉग, 5 अप्रैल 2023.
7. 'अधिकाधिक वायदे, कम-खर्च: राज्य अपने बजट का कैसे उपयोग कर रहे हैं और यह उनके राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है' (सह-लेखक रचना शर्मा), *द प्रिंट,* 7 अप्रैल 2023.
8. 'आईएमएफ की विकास दर में गिरावट उल्लेखनीय है, लेकिन विकासशील देशों के बढ़ते ऋणस्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है', द प्रिंट, 14 अप्रैल 2023.
9. 'क्या अडानी, अंबानी और अन्य दिग्गज विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के पीछे हैं? मेटल सेगमेंट से पता चलता है कि ऐसा नहीं है' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट,* 21 अप्रैल 2023.
10. 'मंद आय और बढ़ती ब्याज लागत का बोझ – शुरुआती Q4 कॉर्पोरेट परिणाम हमें क्या बता रहे हैं ?' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 28 अप्रैल 2023.
11. 'कोर सेक्टर की धीमी वृद्धि के बावजूद, नया वित्त वर्ष भारत के आर्थिक पुनरुद्धार के बारे में आशावादी होने के कारण लेकर आया है' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 5 मई 2023, 7 अप्रैल 2023.
12. 'आईएमएफ की विकास दर में गिरावट उल्लेखनीय है, लेकिन विकासशील देशों के बढ़ते ऋण स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है', *द प्रिंट*, 14 अप्रैल 2023.
13. 'क्या अडानी, अंबानी और अन्य दिग्गज विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के पीछे हैं? मेटल सेगमेंट से पता चलता है कि ऐसा नहीं है' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 21 अप्रैल 2023.
14. 'मंद आय और बढ़ती ब्याज लागत का बोझ – शुरुआती Q4 कॉर्पोरेट परिणाम हमें क्या बता रहे हैं' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 28 अप्रैल 2023.
15. 'कोर सेक्टर की धीमी वृद्धि के बावजूद, नया वित्त वर्ष भारत के आर्थिक पुनरुद्धार के बारे में आशावादी होने के कारण लेकर आया है' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 5 मई 2023.
16. 'कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हाइपरइन्फ्लेशन, आर्थिक उथल-पुथल लोगों को क्रिप्टो अपनाने के लिए कैसे प्रेरित कर रही है'?, *द प्रिंट*, 12 मई 2023.
17. 'अमेरिकी ऋण सीमा की समस्याएँ सुरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर की छवि को धूमिल कर सकती हैं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती हैं', *द प्रिंट*, 19 मई 2023.
18. 'मुद्रास्फीति कम हो सकती है, लेकिन निकट भविष्य में जोखिम बढ़ने का मतलब है कि आरबीआईको ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखना चाहिए' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 26 मई 2023.
19. 'विनिर्माण पुनरुद्धार, कृषि और निर्माण विस्तार - 7.2% जीडीपी वृद्धि के पीछे क्या है?' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 2 जून 2023.
20. 'मुद्रास्फीति कम हुई, लेकिन यहाँ बताया गया है कि आरबीआईकी अपरिवर्तित नीति रेपो दर कुछ समय तक क्यों रहने की संभावना है', द प्रिंट, 9 जून 2023.
21. 'राजकोषीय स्वास्थ्य जांच-भारत के 4 बड़े सर्वेक्षण वाले राज्यों की स्थिति कैसी है', *द प्रिंट*, 16 जून 2023.
22. 'भारत-अमेरिका व्यापार संबंध गहरा रहे हैं, लेकिन मोदी को संरक्षणवादी नीतियों को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए', *द प्रिंट*, 23 जून 2023.
23. 'हीटवेव और भारी बारिश या सामान्य वार्षिक उछाल? टमाटर की कीमतों में उछाल का क्या कारण है?' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 30 जून 2023.
24. 'बैंकिंग क्षेत्र में तेजी और नए निजी निवेश के साथ, भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है', *द प्रिंट*, 7 जुलाई 2023.
25. 'सिर्फ टमाटर नहीं। भारत की खाद्य मुद्रास्फीति के पीछे दालें, अनाज और मसाले हैं – मई में 3.35% से जून में 4.7%', *द प्रिंट*, 14 जुलाई 2023.
26. 'भारत वैश्विक स्तर पर रुपया चाहता है, लेकिन मुद्रा के लिए कम भूख और चीनी युआन की वृद्धि में बाधाएँ हैं', *द प्रिंट*, 21 जुलाई 2023.

27. 'आशावादी आईएमएफ ने वैश्विक विकास के लिए अपने अनुमान को बरकरार रखा है, लेकिन अभी जश्न न मनाएँ...', *द प्रिंट*, 28 जुलाई 2023.
28. 'भारत को चीन और आगामी आरबीआई मौद्रिक नीति की चिंता है, न कि अमेरिकी रेटिंग में गिरावट की', *द प्रिंट*, 4 अगस्त 2023.
29. आरबीआई विकास के मोर्चे पर चिंतित नहीं है, लेकिन खाद्य और तेल की कीमतों में उछाल अभी भी मंडरा रहा है', *द प्रिंट*, 11 अगस्त 2023.
30. 'वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में कर संग्रह में कमी ने राजकोषीय घाटा बढ़ाया, सरकार का ध्यान अभी भी पूंजीगत व्यय पर', *द प्रिंट*, 18 अगस्त 2023.
31. 'स्वस्थ ऋण वृद्धि, आरामदायक पूंजी स्थिति - बैंकिंग क्षेत्र के चल रहे सपनों के पीछे क्या है', *द प्रिंट*, 25 अगस्त 2023.
32. 'मजबूत सेवा वृद्धि, उपभोग मांग में पुनरुद्धार और मजबूत पूंजीगत व्यय ने क्यू1 जीडीपी वृद्धि को 7.8% बढ़ाया' (सह-लेखिका रचना शर्मा), *द प्रिंट*, 1 सितंबर 2023.
33. 'क्रिप्टोकरेंसी विनियमन, ऋण समाधान और अधिक-भारत की जी20 अध्यक्षता के संभावित प्रमुख परिणाम' (सह-लेखिका आनंदिता गुप्ता), *द प्रिंट*, 8 सितंबर 2023.
34. 'सरकार की गैरजिम्मेदारी पर अंकुश कैसे लगाएं' (सह-लेखक प्रतीक दत्ता, इला पटनायक और अजय शाह), *द इंडियन एक्सप्रेस*, 8 सितंबर 2023.
35. 'सस्ती सब्जियां खाद्य और खुदरा मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करती हैं, लेकिन अनाज और दालें चिंता का कारण बनी हुई हैं', *द प्रिंट*, 15 सितंबर 2023.
36. 'भारत के निर्यात में एशियाई देशों की हिस्सेदारी गिर रही है, यूरोप बढ़ रहा है। यह चिंताजनक क्यों है', (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 22 सितंबर 2023.
37. 'परिवार कम बचत कर रहे हैं और अधिक उधार ले रहे हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो', *द प्रिंट*, 29 सितंबर 2023.
29. 'वैश्विक सूचकांकों में भारतीय बांडों को शामिल करने से भारत के वित्तीय बाजार की क्षमता कैसे सामने आ सकती है', *द प्रिंट*, 6 अक्टूबर 2023.
30. 'भारत वित्त वर्ष 24 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, लेकिन इजरायल-हमास युद्ध सरकार के राजकोषीय गणित को नुकसान पहुंचा सकता है', *द प्रिंट*, 13 अक्टूबर 2023.
31. 'मैन्युफैक्चरिंग कम है या संदिग्ध डेटा? सरकारी आंकड़े भारत के कुछ उत्पादन को 2011-12 के स्तर से नीचे दिखाते हैं', *द प्रिंट*, 20 अक्टूबर 2023.
32. 'मैन्युफैक्चरिंग मंदी को डिकोड करना: भारतीय उद्योग का क्षेत्रीय विश्लेषण' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), पॉलिसी सर्किल, 20 अक्टूबर 2023.
33. 'इजरायल-हमास युद्ध पर अनिश्चितता, अमेरिकी बांड क्षेत्रों में वृद्धि से निकट भविष्य में शेयर बाजारों पर असर पड़ेगा' *दप्रिंट*, 27 अक्टूबर 2023.
34. 'भारत में विकास की गति बढ़ने से उपभोक्ता विश्वास 4 साल के उच्चतम स्तर पर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को निरंतर प्रोत्साहन की आवश्यकता है' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 3 नवंबर 2023.
35. 'राज्य बेहतर खर्च कर रहे हैं, कई लोग पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन केंद्र पर निर्भर लोग तनाव का सामना कर सकते हैं', *द प्रिंट*, 10 नवंबर 2023.
36. 'मतदान वाले राज्यों में मुद्रास्फीति कम या अधिक, दर्दनाक। पार्टियों ने बढ़ती कीमतों को कम करने का आश्वासन दिया', *द प्रिंट*, 17 नवंबर 2023.
37. 'हालांकि सुधार हुआ है, केंद्र और राज्यों का कर्ज अभी भी कोविड से पहले के स्तर से अधिक है। इसे कैसे प्रबंधित किया जा सकता है', *द प्रिंट*, 24 नवंबर 2023.
38. 'कुछ चिंता पैदा करने के बाद, विनिर्माण दूसरी तिमाही में सुखद आश्चर्य लेकर आया। लेकिन उपभोग एक चिंता का विषय है' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 1 दिसंबर 2023.

39. 'अक्टूबर में कर राजस्व में कम वृद्धि और 2024 के चुनावों के करीब आने पर अधिक खर्च सरकारी वित्त पर दबाव डाल सकता है' (सह-लेखक रचना शर्मा), *द प्रिंट*, 8 दिसंबर 2023.
40. 'खाद्य मुद्रास्फीति अधिक लगातार और व्यापक होती जा रही है और दुर्भाग्य से, इसमें कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 15 दिसंबर 2023.
41. 'आईएमएफ का दावा है कि आरबीआई द्वारा अत्यधिक विनियमित रुपया कमजोर है, लेकिन बेहतर राजकोषीय लक्ष्यों पर सलाह उपयोगी है' (सह-लेखक उत्सव सक्सेना), *द प्रिंट*, 22 दिसंबर 2023.
42. 'वैश्विक मंदी, कॉरपोरेट्स का लचीलापन, मुद्रास्फीति में कमी - 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था को क्या आकार देगा' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 29 दिसंबर 2023.
43. 'बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और बेहतर पूंजी स्थिति, लेकिन भारत के वित्त क्षेत्र को 2024 में अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है', *द प्रिंट*, 5 जनवरी 2024.
44. 'विनिर्माण, निवेश भारत के वित्त वर्ष 24 के विकास अनुमान को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन खपत में उछाल की आवश्यकता है' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), *द प्रिंट*, 12 जनवरी 2024.
45. 'उच्च ऋण बोझ और केंद्र पर निर्भरता - उत्तर-पूर्वी राज्यों की अनूठी राजकोषीय बाधाएँ', *द प्रिंट*, 19 जनवरी 2024.
46. 'अंतरिम बजट से क्या उम्मीद करें? बड़े कर छूट की संभावना नहीं, कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है' (सह-लेखिका रचना शर्मा), *द प्रिंट*, 26 जनवरी 2024.
47. 'अंतरिम बजट में सरकार का पूंजीगत व्यय पर ध्यान जारी है, ग्रामीण संकट को कम करने के लिए मनरेगा के लिए अधिक आवंटन किया गया' (सह-लेखिका रचना शर्मा), *द प्रिंट*, 2 फरवरी 2024.
48. 'खाद्य और तेल की कीमतों पर अनिश्चितता-क्यों भारत ने अन्य देशों की तरह अपनी नीतिगत दरें स्थिर रखीं' (सह-लेखिका मधुर मेहता), *द प्रिंट*, 9 फरवरी 2024.
49. 'भारत की लचीली अर्थव्यवस्था को लाल सागर, अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति और चीन में अनियमित सुधार से जोखिम का सामना करना पड़ रहा है', *द प्रिंट*, 16 फरवरी 2024.
50. 'घरेलू उपभोग और ग्रामीण बिक्री में धीमी वृद्धि लेकिन कंपनियाँ धीरे-धीरे बढ़ने को लेकर आशावादी', *द प्रिंट*, 23 फरवरी 2024.
51. 'औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित होकर भारत की जीडीपी तीसरी तिमाही में 8.4% कैसे बढ़ी' (सह-लेखिका रचना शर्मा), *द प्रिंट*, 1 मार्च 2024.
52. 'खाद्य पदार्थों पर कम, परिवहन और टिकाऊ वस्तुओं पर अधिक-पिछले दशक में उपभोग पैटर्न कैसे बदले' (सह-लेखिका रचना शर्मा), *द प्रिंट*, 8 मार्च2024.
53. 'केंद्रीय अनुदानों में कमी से व्यय की खराब गुणवत्ता-बिहार, पंजाब और यू.पी. के बजट क्या दर्शाते हैं' (सह-लेखिका रचना शर्मा), *द प्रिंट*, 15 मार्च 2024.
54. 'माल और सेवाओं का निर्यात बढ़ा, व्यापार घाटा घटा-भारत के निर्यात में कैसे उछाल आया' (सह-लेखक रचना शर्मा), *द प्रिंट*, 22 मार्च 2024.
55. '17 साल बाद जापान की सकारात्मक ब्याज दरों पर वापसी विश्व अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित कर सकती है' (सह-लेखक उत्सव सक्सेना), 29 मार्च2024.

रॉली कुकरेजा

1. 'क्या प्रतिनिधित्व राजनीतिक संस्थाओं में विश्वास को प्रभावित करता है?: भारत में पुनर्वितरण से साक्ष्य', *वर्ल्ड डेवलपमेंट*, खंड 179, 2024https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106563)

रमेश नागपाल

1. 'ग्रीन बजटिंग – भारत का अनुभव' (सह-लेखक प्रताप रंजन जेना), राज्य फोरम 2023: *ए कम्पेंडियम*, एनआईपीएफपी, 2023.

आकांक्षा श्रवण

1. 'बजट 2024-25: राजकोषीय नीति के लिए एक प्रतिचक्रीय दृष्टिकोण', आइडियाज फॉर इंडिया, एनआईपीएफपी, 26 मार्च 2024.

दिनेश कुमार नायक

1. 'भारत का प्रदर्शन? मध्य-वर्षीय मैक्रोइकॉनोमिक रिव्यू' (सह-लेखक मनीष गुप्ता, राधिका पांडे और सुदीप्तो मुंडले), एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 400, सितंबर 2023, *इकनॉमिक डेवलेपमेंट इन इंडिया - क्वार्टर्ली अपडेट*में भी (संपादक उमा कपिला), खंड 264:29-69, अकादमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।
2. 'बाहरी व्यापार, और घरेलू क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ: जनवरी-मार्च, 2023', *इकनॉमिक डेवलेपमेंट इन इंडिया - क्वार्टर्ली अपडेट* (संपादक उमा कपिला), खंड 262:185-189, अकादमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।
3. 'भुगतान संतुलन की स्थिति' (सह-लेखक रुद्राणी भट्टाचार्य), *इकनॉमिक डेवलेपमेंट इन इंडिया - क्वार्टर्ली अपडेट* (संपादक उमा कपिला), खंड 262:204-210, अकादमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।

श्रीहरि नायडू ए.

1. 'भारत में राज्य स्तर पर सिकुड़ता राजकोषीय स्थान और इसका कल्याण व्यय और सब्सिडी पर प्रभाव' (सह-लेखक अमरनाथ एच.के. और मिताली गुरदत्ता), *अर्थिका चर्चे – एफपीआई जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस*, खंड 8(1), जनवरी-जून 2023. 18 मई 2023.

भाबेश हज़ारिका

1. 'भारतीय उप-राष्ट्रीय में सार्वजनिक व्यय, शासन और मृत्यु दर संभावना: एक दो-स्तरीय यादृच्छिक अवरोधन विश्लेषण', *जर्नल ऑफ डेवलपिंग एरियाज़*, खंड57 (4): 55-75, 2023.

अन्य क्रियाकलाप/लोकप्रिय लेखन

2. '2024-25 के लिए लिंग बजट आवंटन कुल बजटीय परिव्यय का 6.5 प्रतिशत पार करने का अनुमान', *द टेलीग्राफ।* https://www.telegraphindia.com/business/gender-budget-allocation-for-2024-25-projected-to-be-at-6-5-per-cent-of-total-budgetary-outlay/cid/1998031

अमनदीप कौर

1. 'जी20 और जलवायु उत्तरदायी बजट' (सह-लेखक अजय नारायण झा और लेखा चक्रवर्ती), एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र संख्या 401, सितंबर 2023.
2. 'जलवायु परिवर्तन और राजकोषीय प्रबंधन: एक उभरते देश, भारत से साक्ष्य' (सह-लेखक लेखा चक्रवर्ती, अजय नारायण झा, जितेश यादव और बालमुरली बी.), कार्यकारी पत्र संख्या 1023, लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, अन्नाडेल-ऑन-हडसन, न्यूयॉर्क, जुलाई 2023.
3. 'भारत में बाल संरक्षण योजनाओं के लिए ओईसीडी नीति मूल्यांकन मानदंडों को लागू करना' (सह-लेखक लेखा चक्रवर्ती, जितेश यादव और बालमुरली बी.), कार्यकारी पत्र संख्या 1032, लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, अन्नाडेल-ऑन-हडसन, न्यूयॉर्क, अक्टूबर 2023.
4. 'कॉप-28 और पर्यावरण संघवाद: एक उभरती अर्थव्यवस्था, भारत से अनुभवजन्य साक्ष्य' (सह-लेखक लेखा चक्रवर्ती, रंजन कुमार मोहंती, दिव्य रंगन और संजना दास), कार्यकारी पत्र संख्या 1040, लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, अन्नाडेल-ऑन-हडसन, न्यूयॉर्क, फरवरी 2024।

5. 5. 'भारत में पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण और राज्य स्तरीय बजटीय खर्च: फ्लाईपेपर इफेक्ट्स' (सह-लेखक लेखा चक्रवर्ती, रंजन कुमार मोहंती और दिव्य रंगन), *इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली*, खंड 58(14), 8 अप्रैल 2023.
6. 'जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन पर सार्वजनिक खर्च और भारत से राजकोषीय निशानेबाजी साक्ष्य' (सह-लेखक लेखा चक्रवर्ती, अजय नारायण झा, जितेश यादव और बालमुरली बी.), *इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली*, खंड 58(51), 23 दिसंबर 2023.

आकाश गुप्ता

1. 'लोकतंत्र में नागरिकों की वोटिंग शक्ति', *अर्थनीति: जर्नल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस*, 0(0), 27 जुलाई 2023.

अनुबंध VII: 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार स्टाफ सदस्यों की सूची

संकाय

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डॉ. आर. कविता राव	निदेशक
2	डॉ. सुप्रियो डे	प्रोफेसर (आरबीआई चेयर)(19/06/2023 को कार्यमुक्त)
3	डॉ. एनआर भानुमूर्ति	प्रोफेसर (22/06/2020 से प्रतिनियुक्ति पर)
4	डॉ.सुश्री लेखा एस चक्रवर्ती	प्रोफेसर
5	डॉ. प्रताप रंजन जेना	प्रोफेसर
6	डॉ. सुश्री मीता चौधरी	प्रोफेसर
7	डॉ. सच्चिदानंद मुखर्जी	प्रोफेसर
8	डॉ. अमरनाथ एच.के.	एसोसिएट प्रोफेसर
9	डॉ. रेणुका साने	एसोसिएट प्रोफेसर (31/12/2023 को कार्यमुक्त)
10	डॉ. मनीष गुप्ता	एसोसिएट प्रोफेसर
11	डॉ. रुद्राणी भट्टाचार्य	एसोसिएट प्रोफेसर
12	डॉ. अमेय सप्रे	एसोसिएट प्रोफेसर
13	डॉ. सुरंजलि टंडन	एसोसिएट प्रोफेसर (29/05/2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
14	डॉ. सुकन्या बोस	एसोसिएट प्रोफेसर (29/05/2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
15	डॉ. राधिका पांडे	एसोसिएट प्रोफेसर (31/05/2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
16	डॉ. मुकेश कुमार आनंद	एसोसिएट प्रोफेसर (06/03/2024 को कार्यभार ग्रहण किया)
17	डॉ. रॉली कुकरेजा	सहायक प्रोफेसर
18	डॉ. पियाली दास	सहायक प्रोफेसर
19	डॉ. मालविका महेश	सहायक प्रोफेसर
20	डॉ. आकांक्षा श्रवण	सहायक प्रोफेसर (28/07/2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
21	डॉ. रेशम नागपाल	सहायक प्रोफेसर (07/08/2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
22	डॉ. दिनेश कुमार नायक	अर्थशास्त्री
23	डॉ. ए. श्रीहरि नायुडू	अर्थशास्त्री
24	डॉ. भावेश हज़ारिका	अर्थशास्त्री
25	सुश्री अमनदीप कौर	अर्थशास्त्री
26	श्री आकाश गुप्ता	अर्थशास्त्री (11/04/2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
27	श्री एस के एमडी अज़हरुद्दीन	अर्थशास्त्री (11/07/2023 को कार्यभार ग्रहण किया)

प्रशासनिक स्टाफ

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री पंकज कुमार सिन्हा	सचिव (11/04/2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
2	श्री विक्रम सिंह चौहान	निदेशक के निजी सचिव
3	श्रीबीएस रावत	लेखा अधिकारी
4	सुश्री प्रोमिला राजवंशी	आशुलिपिक ग्रेड I (11/03/2024 से प्रतिनियुक्ति पर)
5	सुश्री कविता इस्सर	आशुलिपिक ग्रेड.I
6	श्रीअनुरोध शर्मा	आशुलिपिक ग्रेड.I
7	श्री दर्शन सिंह पँवार	आशुलिपिक ग्रेड.II
8	सुश्री अमित मनहास	आशुलिपिक ग्रेड.II
9	श्री कपिल कुमार आहूजा	आशुलिपिक ग्रेड.II
10	सुश्री रुचि आनंद	सहायक
11	सुश्री उषा माथुर	आशुलिपिक ग्रेड. II
12	सुश्री वसीम अहमद	आशुलिपिक-टंकक (01/07/2021 से प्रतिनियुक्ति पर)
13	सुश्री शुभम कुमार वर्मा	लिपिक (लेखा)

14	सुश्री दीपिका राय	सहायक
15	सुश्री मोनिका माथुर	स्वागतकर्ता-सह-टेलीफोन प्रचालक
16	श्री परशुराम तिवारी	चालक
17	श्री मोहन सिंह बिष्ट	फोटोकॉपी प्रचालक (29/02/2024 को सेवानिवृत्त)
18	श्री के.एन. मिश्रा	हॉस्टल अटेंडेंट
19	श्री शिव प्रताप	माली
20	श्री रमेश कुमार	माली
21	श्री हरीश चंद	संदेशवाहक
22	श्री अजय कुमार	संदेशवाहक
23	श्री मुकेश	संदेशवाहक
24	श्री राजेन्द्र कुमार	संदेशवाहक (01/03/2022 से प्रतिनियुक्ति पर)
25	श्री बिशम्बर पांडे	सुरक्षाकर्मी
26	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	सुरक्षाकर्मी

कंप्युटर एकक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री रोबी थॉमस	ईडीपी प्रबंधक (13/03/2024 को कार्यभार ग्रहण किया)

पुस्तकालय कर्मी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डॉ. सोनम सिंह	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
2	सुश्री सारिका गौड़	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (06/12/2021 से प्रतिनियुक्ति पर)
3	सुश्री मंजु ठाकुर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
4	सुश्री आजाद कौर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
5	श्री राजन ढाका	वरिष्ठ पुस्तकालय अटेंडेंट
6	श्री नदीम अली	कनिष्ठ पुस्तकालय अटेंडेंट
7	श्री पूरन सिंह	संदेशवाहक

शैक्षणिक स्टाफ : संविदात्मक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री ए.एन. झा	वरिष्ठ फ़ेलो (31.01.2024 को कार्यमुक्त)
2	डॉ. राधिका पांडे	वरिष्ठ फ़ेलो (30.05.2023 को कार्यमुक्त)
3	श्री प्रमोद सिन्हा	फ़ेलो-II(5.01.2024 को कार्यमुक्त)
4	सुश्री रचना शर्मा	फ़ेलो-II
5	श्री प्रीतम दत्ता	फ़ेलो-II
6	डॉ. करण सचदेवा	परियोजना प्रबंधक (10.08.2023 को कार्यमुक्त)
7	श्री आशिम कपूर	रिसर्च फेलो
8	श्री रोहित दत्ता	रिसर्च फेलो
9	सुश्री शिवानी बडोला	रिसर्च फेलो
10	सुश्री अर्चिता श्रीधर	रिसर्च फेलो (23.06.2023 को कार्यमुक्त)
11	सुश्री मार्गी पाण्ड्या	रिसर्च फेलो (02.07.2023 को कार्यमुक्त)
12	श्री आदम हुसैन	रिसर्च फेलो (11.05.2023 को कार्यमुक्त)
13	श्री उत्सव सक्सेना	रिसर्च फेलो
14	श्री कीर्ति वट्टल	रिसर्च फेलो
15	सुश्री अनिन्दिता गुप्ता	रिसर्च फेलो
16	सुश्री नित्या चुटानी	रिसर्च फेलो
17	सुश्री वैशाली भारद्वाज	रिसर्च फेलो (15.01.2024 को कार्यमुक्त)
18	श्री विस्मय बासु	रिसर्च फेलो
19	सुश्री खुशबू आहूजा	रिसर्च फेलो

20	श्री अंकित सिंह	रिसर्च फेलो
21	श्री सुशील कुमार मोदी	रिसर्च फेलो (31.01.2024 को कार्यमुक्त)
22	श्री आशीष राज	रिसर्च फेलो (29.02.2024 को कार्यमुक्त)
23	डॉ. फ़िरदौस अहमद मालिक	रिसर्च फेलो (31.5.2023 को कार्यमुक्त)
24	सुश्री प्रियांशी गर्ग	रिसर्च फेलो (29.03.2024 को कार्यमुक्त)
25	सुश्री अनुकृति चौबे	रिसर्च फेलो (17.11.2023 को कार्यमुक्त)
26	सुश्री हरसिमर कौर साहनी	रिसर्च फेलो
27	श्री विष्णु एन. रमानी	रिसर्च फेलो (03.04.2023से 02.10.2023)
28	श्री पुलकित कुमार शर्मा	रिसर्च फेलो (03.04.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
29	श्री अतुल कुमार	रिसर्च फेलो (26.03.2024 को कार्यमुक्त)
30	सुश्री राधिका अग्रवाल	रिसर्च फेलो (28.04.2023 को कार्यमुक्त)
31	सुश्री सीमा मौर्य	रिसर्च फेलो
32	सुश्री मधुर मेहता	रिसर्च फेलो
33	श्री सिराजुल इस्लाम याज़दानी	रिसर्च फेलो (26.02.2024 को कार्यमुक्त)
34	सुश्री नीति गुप्ता	रिसर्च फेलो
35	श्री प्रवीण सिंह	रिसर्च फेलो (12.10.2023 को कार्यमुक्त होना है)
36	सुश्री मयूराक्षी मित्रा	रिसर्च फेलो
37	सुश्री सौम्या अग्रवाल	रिसर्च फेलो
38	सुश्री दिव्या रुद्रा	रिसर्च फेलो (07.05.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
39	श्री अभिषेक सिंह	रिसर्च फेलो (13.04.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
40	श्री केनेथ रूड़ी गोम्स	रिसर्च फेलो (01.05.2023 से 04.02.2024)
41	सुश्री आरती बंसल	रिसर्च फेलो (01.06.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
42	सुश्री मिताली गुरदत्ता	कनिष्ठ परामर्शक (26.06.2023 को कार्यमुक्त)
43	सुश्री बेंसी रामकृष्णन	रिसर्च फेलो (28.06.2023को कार्यभार ग्रहण किया)
44	सुश्री निपुण वर्मन	रिसर्च फेलो (03.07.2023को कार्यभार ग्रहण किया)
45	सुश्री स्मृति बनाती	रिसर्च फेलो (20.09.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
46	डॉ. सैकत बनर्जी	रिसर्च फेलो (अंशकालिक)(05.10.23को कार्यभार ग्रहण किया)
47	श्री विवेक जाधव	रिसर्च फेलो (01.11.2023 से 14.02.2024)
48	श्री परसनाथ सी.	रिसर्च फेलो (10.11.2023को कार्यभार ग्रहण किया)
49	सुश्री आकांक्षा घोष	रिसर्च फेलो (05.12.2023to29.12.2023)
50	श्री यशोवर्धन चतुर्वेदी	रिसर्च फेलो (08.01.2024को कार्यभार ग्रहण किया)

प्रशासनिक कर्मचारी - संविदात्मक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	सुश्री लता बालासुब्रमण्यम	कार्यक्रम सहायक (02.06.2023 को कार्यमुक्त)
2	श्री रोहित भदोरिया	परामर्शक (15.12.2023 को कार्यमुक्त)
3	श्री हरिशंकर गुप्ता	परामर्शक
4	श्री नवीन भल्ला	परामर्शक
5	श्री राजू	ड्राइवर (30.11.2023 को कार्यमुक्त)
6	श्री रजनेश जून	परामर्शक
7	श्री विपिन कुमार	परामर्शक
8	श्री भुवनकौशिक श्रीपद	परामर्शक - कार्यक्रम सहायक (23.06.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
9	सुश्री मीना	डेटा एंट्री ऑपरेटर
10	सुश्री मुमताज़	डेटा एंट्री ऑपरेटर
11	सुश्री प्रिंशिका	डेटा एंट्री ऑपरेटर (21.04.2023 से 20.09.2023)

अनुबंध VIII: 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक, कारपोरेट, स्थायी और सामान्य सदस्यों की सूची

क. प्रायोजक सदस्य

राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. कर्नाटक
5. केरल
6. महाराष्ट्र
7. उड़ीसा
8. पंजाब
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिम बंगाल

अन्य

1. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
2. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
3. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ख. स्थायी सदस्य - राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

1. अरुणाचलप्रदेश
2. गोवा, दमन एवं दीव
3. हिमाचलप्रदेश
4. मध्यप्रदेश
5. मेघालय
6. मणिपुर
7. नागालैंड

ग. साधारण सदस्य - राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

1. हरियाणा
2. त्रिपुरा सरकार

घ. अन्य

1. मैसर्सहिंदुस्तानयूनीलीवरलिमिटे

अनुबंध IX: वित्त और लेखे

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संस्थान के लेखाओं का विवरण,
संस्थान के लेखा परीक्षकों, मैसर्स अनिल कक्कड़ एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित

अनिल कक्कड़ एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट

402,चौथा4तल, अंसल भवन, 16,कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001

फोन : 011-49872883 | ई-मेल : akca.tax@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के सामान्य निकाय के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (इकाई) के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी है, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र, समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां शामिल हैं।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 तक इकाई की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार संचालित की। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र इकाई हैं और हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इकाई की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष परिदृश्य प्रदान करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो एक उचित और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन इकाई की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने तथा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने, जहां लागू हो, के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन इकाई को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

शासन का प्रभार संभालने वाले लोग संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में कि क्या वित्तीय विवरण पूरी तरह से भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, उचित आश्वासन प्राप्त करना और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा भौतिक गलत बयान का पता लगाएगा जब हमेशा एक भौतिक गलत बयान मौजूद हो। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को उचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार, लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षाके दौरान पेशेवर दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और उनका पालन करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की उचितता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो इकाई की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण इकाई चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यहदेखना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह विवरण भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उन सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करने के लिए तैयार हैं, जिनके बारे में उचित रूप से सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपाय भी करते हैं।

अन्य अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

ii. हमारी राय में, जहां तक बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, संस्था द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बहियाँ रखी गई हैं, और

iii. इस रिपोर्ट द्वारा जाँचे गए तुलन-पत्र तथा आय और व्यय खाते लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

अनिल कुमार एंड एसोसिएट्स के लिए

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)
फर्म पंजीकरण संख्या 006022N

हस्ता./-
(अनिल कक्कड़)
पार्टनर
सदस्यता सं. : 084882
यूडीआईएं:24084882BKEQQW7302
स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 03/09/2024

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

राशि रु. में

	अनुसूची	31 मार्च 24 की स्थिति	31 मार्च 23 की स्थिति
कायिक/पूंजीगत निधि एवं देनदारियां			
कायिक/पूंजीगत निधि	**1**	14,53,74,080	14,29,99,759
आरक्षित और अधिशेष	**2**	26,58,10,714	24,58,10,714
आस्थगित आय	**3**	1,73,88,311	1,72,98,924
धर्मादा/विनिश्चित निधियां	**4**	41,98,73,865	39,96,17,394
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	**5**	11,10,80,802	12,63,07,081
कुल		**95,95,27,772**	**93,20,33,872**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	**6**	6,22,89,147	6,18,24,994
निवेश- धर्मादा/विनिश्चित निधियां	**7**	41,70,74,660	42,80,26,926
निवेश - अन्य	**8**	38,10,42,457	35,59,72,892
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**9**	9,91,21,508	8,62,09,060
योग		**95,95,27,772**	**93,20,33,872**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**18**		
लेखाओं पर टिप्पणियां	**19**		

अनुसूची 1 से 19 लेखाओं का अभिन्न अंग हैं

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के लिए

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(बी.एस. रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डा. आर.कविता राव)	(डा. उर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

अनिल कक्कड़ एवं एसोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए
फर्म पंजीकरण सं. 006022N

हस्ता./-
(अनिल कक्कड़)
पार्टनर
एम.सं.: 084882
यूडीआईएन: 24084882BKEQQX7302
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 03/09/2024

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रु. में

	अनुसूची	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2023
आय			
केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान	**10**	9,49,01,183	8,58,51,283
अकादमिक क्रियाकलापों से आय	**11**	10,17,21,322	11,19,32,342
अर्जित ब्याज	**12**	2,35,31,958	2,21,49,702
अन्य आय	**13**	1,43,89,666	1,60,73,415
योग		**23,45,44,129**	**23,60,06,742**
व्यय			
स्थापना व्यय	**14**	8,50,06,255	7,21,87,220
अकादमिक क्रियाकलापों पर व्यय	**15**	8,52,98,390	9,00,40,685
प्रशासनिक व्यय	**16**	3,84,37,658	3,91,52,960
प्रकाशन स्टॉक में कमी		2,077	-
मूल्यह्रास	**6**	34,08,596	29,59,821
योग		**21,21,52,976**	**20,43,40,686**
वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष		2,23,91,153	3,16,66,056
घटाएं : पूर्व अवधि की मदें		16,832	2,400
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष		2,23,74,321	3,16,63,656
घटाएं : अतिरिक्त दायित्व के लिए रिजर्व से अंतरित राशि		1,00,00,000	1,00,00,000
घटाएं : सामान्य रिजर्व को अंतरित राशि		1,00,00,000	1,50,00,000
कायिक/पूंजीगत निधि से ले जाए गए अधिशेष राशि का शेष		**23,74,321**	**66,63,656**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**18**		
लेखाओं पर टिप्पणियां	**19**		

अनुसूची 1 से 19 लेखाओं का अभिन्न अंग हैं

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के लिए

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(बी.एस. रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डा. आर.कविता राव)	(डा. उर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

अनिल कक्कड़ एवं एसोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए
फर्म पंजीकरण सं. 006022N

हस्ता./-
(अनिल कक्कड़)
पार्टनर
एम.सं.: 084882
यूडीआईएन: 24084882BKEQQX7302

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 03.09.2024

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

		31 मार्च, 24 की स्थिति		31 मार्च, 23 की स्थिति
अनुसूची 1 - कायिक/पूंजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष	14,29,99,759		13,63,36,103	
जोड़ें : आय और व्यय लेखा से अंतरित अधिशेष	23,74,321		66,63,656	
		14,53,74,080		14,29,99,759
कुल		**14,53,74,080**		**14,29,99,759**
अनुसूची 2 - रिजर्व और अधिशेष				
क. अतिरिक्त देनदारी के लिए रिजर्व				
पिछले लेखा के अनुसार	10,21,89,863		9,21,89,863	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	1,00,00,000		1,00,00,000	
		11,21,89,863		10,21,89,863
ख. सामान्य रिजर्व				
पिछले लेखा के अनुसार	14,31,20,851		12,81,20,851	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	1,00,00,000		1,50,00,000	
		15,31,20,851		14,31,20,851
ग. मृतक कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रिजर्व		5,00,000		5,00,000
योग		**26,58,10,714**		**24,58,10,714**
अनुसूची 3 - आस्थगित आय				
अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए भवन के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से अनुदान				
पिछले लेखा के अनुसार	1,55,02,900		1,58,16,779	
घटाएं : आय और व्यय लेखा में अंतरित ऐसी आस्तियों के मूल्यह्रास के समतुल्य राशि	3,13,879		3,13,879	
		1,51,89,021		1,55,02,900
विभिन्न प्रायोजकों से अनुदान पूंजीगत आस्तियों के लिए प्रयुक्त				
पिछले लेखा के अनुसार	17,96,024		4,26,737	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	9,99,000		16,28,340	
घटाएं: ऐसी आस्तियों के मूल्यह्रास के समतुल्य राशि आय और व्यय लेखा को अंतरित	5,95,734		2,59,053	
		21,99,290		17,96,024
योग		**1,73,88,311**		**1,72,98,924**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4 - धर्मादा/विनिर्धारित निधियां

राशि रु. में

विवरण	फोर्ड फाउंडेशन धर्मादा निधि	सरकारी धर्मादा निधि	भारतीय रिजर्व बैंक धर्मादा निधि	वैज्ञानिक अनुसंधान निधि	आजीवन सदस्यता निधि	बिमला बागची अवार्ड निधि	जोखन मौर्य निधि	सरकारी कायिक निधि	राजा चेल्लैया वार्षिक व्याख्यान माला और अतिथि प्रोफेसरशिप निधि	कुल
प्रारंभिक निधि	61,77,924	1,00,00,000	10,00,00,000	7,27,406	4,20,000	50,000	29,300	12,00,00,000	2,00,00,000	
(क) निधियों का अथशेष	1,71,47,747	1,00,00,000	10,11,62,525	30,24,695	17,41,188	1,29,752	73,576	22,50,93,998	4,12,43,914	39,96,17,395
(ख) निधियों में अभिवृद्धियां										
(i) अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निवेश से आय	9,29,608	7,60,805	77,58,870	2,12,255	1,23,723	8,969	5,844	1,62,51,221	28,68,547	2,89,19,842
योग (क+ख)	**1,80,77,355**	**1,07,60,805**	**10,89,21,395**	**32,36,950**	**18,64,911**	**1,38,721**	**79,420**	**24,13,45,219**	**4,41,12,461**	**42,85,37,237**
(ग) निधि के प्रयोजनों के लिए उपयोग/व्यय	1,39,839	7,60,805	16,31,133	-	-	35,000	-	60,96,594		86,63,372
योग (ग)	**1,39,839**	**7,60,805**	**16,31,133**	**-**	**-**	**35,000**	**-**	**60,96,594**	**-**	**86,63,372**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख)-(ग)	**1,79,37,516**	**1,00,00,000**	**10,72,90,262**	**32,36,950**	**18,64,911**	**1,03,721**	**79,420**	**23,52,48,625**	**4,41,12,461**	**41,98,73,865**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

		31 मार्च, 24 की स्थिति	**31 मार्च, 23 की स्थिति**
अनुसूची 5 - वर्तमान देनदारियां और प्रावधान			
क. वर्तमान देनदारियां			
1	माल और सेवाओं के लिए विविध लेनदार	64,04,118	36,56,330
2	बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	8,55,735	9,48,277
3	अप्रयुक्त परियोजना अनुदान (देखिए अनुसूची 5(क))	1,97,28,093	5,74,70,944
	अनुप्रयुक्त सहायता अनुदान (एमओएफ अनुसूची 5 (ख) देखें)	1,19,89,592	-
4	सांविधिक देय	54,96,437	41,58,902
5	अन्य वर्तमान देनदारियां	1,20,75,781	1,24,29,168
	योग	**5,65,49,756**	**7,86,63,621**
ख. प्रावधान			
1	छुट्टी नकदीकरण	5,45,31,046	4,76,43,460
	योग	**5,45,31,046**	**4,76,43,460**
	सकल योग	**11,10,80,802**	**12,63,07,081**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5(क) - परियोजना अनुदान राशि रु. में

क्र.सं.	विवरण	1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त	1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार वसूली योग्य	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	योग	वापस किया गया अनुप्रयुक्त अनुदान	प्रयुक्त/प्राप्त की गई और आय और व्यय लेखा में क्रेडिट की गई	प्रयुक्त और आस्थगित आय में जमा की गई	योग	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार वसूलीयोग्य	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त
1	स्वास्थ्य पर अनुसंधान और नीतियों में सुधार और उसका वित्त-पोषण - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	1,00,95,979	-	-	1,00,95,979	-	-	-	-	-	1,00,95,979
2	अनुदान के लिए ब्याज आबंटन - स्वास्थ्य पर अनुसंधान और नीतियों में सुधार और उसका वित्त-पोषण - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	69,40,566	-	9,01,376	78,41,942	-	-	-	-	-	78,41,942
3	राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण - यूएनडीपी	5,12,553	-	-	5,12,553	-	-	-	-	-	5,12,553
4	डिजिटल लैंड का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन - एनसीईआर उप-अनुदान	9,27,993	-	-	9,27,993	-	-	-	-	-	9,27,993
5	एनआईपीएफपी - टीएआरआई सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम	42,521	-	-	42,521	-	-	-	टिप्पणी-1 देखें	-	-
6	क्या मौद्रिक नीति भारत में वित्तीय स्थायित्व की दिशा में कार्य कर सकती है - आईसीएसएसआर	1,61,916	-	-	1,61,916	-	-	-	-	-	1,61,916
7	भारत में स्वास्थ्य के लोक वित्त-पोषण के दृष्टिकोण : भावी मार्ग - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	3,27,49,860	-	-	3,27,49,860	-	3,27,49,860	-	3,27,49,860	-	-
8	अनुदान के लिए ब्याज आबंटन - भारत में स्वास्थ्य के लोक वित्त-पोषण के दृष्टिकोण : भावी मार्ग - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	40,90,304	-	7,92,863	48,83,167	-	48,83,167	-	48,83,167	-	-
9	राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण - यूएनडीपी-II	1,87,710	-	-	1,87,710	-	-	-	-	-	1,87,710
10	हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए सहयोगी सेवा, हिमाचल प्रदेश - यूएनडीपी	-	21,366	-	(21,366)	-	-	-	-	21,366	-
11	एनआईपीएफपी - डीईए अनुसंधान कार्यक्रम - आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 2020-21	-	53,72,574	1,72,89,045	1,19,16,471	-	1,54,12,988	5,55,000	1,59,67,988	40,51,517	-
12	राज्य वित्त आयोग - यूनिसेफ	17,61,546	-	-	17,61,546	-	-	-	टिप्पणी-2 देखें	-	-
13	सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों में सार्वजनिक व्यय, शासन और क्षेत्रीय असमानता : असम में जिलास्तरीय विश्लेषण - आईसीएसएसआर	-	2,447	1,50,000	1,47,553	-	2,98,890	-	2,98,890	1,51,337	-
14	एनआईपीएफपी-एमओएचयूए शोध कार्यक्रम - आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	-	14,19,982	1,14,06,850	99,86,868	-	1,38,91,633	4,44,000	1,43,35,633	43,48,765	-
15	16वें वित्त आयोग-विदेशी राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ), यूके को समर्थन प्रदान करना	-	-	26,66,022	26,66,022	-	63,49,474	-	63,49,474	36,83,452	-
	कुल	**5,74,70,948**	**68,16,369**	**3,32,06,156**	**8,38,60,735**	**-**	**7,35,86,012**	**9,99,000**	**7,45,85,012**	**1,22,56,437**	**1,97,28,093**

टिप्पणी-1 अप्रयुक्त अनुदान 45521 बट्टे खाते में डाला गया | टिप्पणी-2 अप्रयुक्त अनुदान 17,61,546 बटटे खाते में डाला गया

अनुसूची 5(ख) : केंद्रीय सरकार से अप्रयुक्त अनुदान राशि रु. में

	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
अप्रयुक्त अनुदान का आदिशेष	(2,09,225)	(1,04,57,942)
जोड़ें : वेतन और भत्तों के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	10,50,00,000	9,50,00,000
	8,45,42,058	**8,45,42,058**
	10,47,90,775	8,45,42,058
घटाएं : वेतन और भत्तों के लिए अप्रयुक्त अनुदान (आय और व्यय लेखा में आय के रूप में विचार किया गया)	9,28,01,183	8,47,51,283
योग - अप्रयुक्त/(वसूलीयोग्य) अनुदान	**1,19,89,592**	**(2,09,225)**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 6 - स्थायी परिसंपत्तियां राशि रुपए में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 23 के अनुसार	जोड़	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 24 के अनुसार	1 अप्रैल 23 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 24 तक	31 मार्च 24 के अनुसार	31 मार्च 23 के अनुसार
स्वयं की निधियों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां										
1 पट्टा भूमि	1,88,09,202	-	-	1,88,09,202	-	-	-	-	1,88,09,202	1,88,09,202
2 भवन	3,39,05,360	-	-	3,39,05,360	1,55,02,854	8,35,123	-	1,63,37,977	1,75,67,383	1,84,02,506
3 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	3,17,49,333	14,89,609	12,80,814	3,19,58,128	3,01,00,643	6,12,197	12,63,704	2,94,49,135	25,08,993	16,48,690
4 कार्यालय उपकरण	1,00,92,719	14,757	32,334	1,00,75,142	96,91,215	1,87,681	32,334	98,46,562	2,28,580	4,01,504
5 फर्नीचर और जुड़नार	1,26,01,539	37,305	88,676	1,25,50,168	1,13,74,804	1,98,220	88,676	1,14,84,348	10,65,820	12,26,735
6 छात्रावास, पुस्तकालय, कम्प्यूटर एवं सेमिनार कक्ष फर्नीचर	36,41,172		-	36,41,172	36,39,786	406	-	36,40,192	980	1,386
7 एयर कंडीशनर और वाटर कूलर	92,01,546	61,041	1,16,699	91,45,888	63,76,987	3,70,675	1,16,699	66,30,963	25,14,925	28,24,560
8 विद्युत संस्थापनाएं	71,49,686	63,107	53,513	71,59,280	65,03,460	1,14,251	53,513	65,64,198	5,95,082	6,46,226
9 वाहन	14,24,148	12,32,000	6,69,219	19,86,929	8,79,303	1,75,965	6,69,219	3,86,049	16,00,880	5,44,845
10 बागवानी उपकरण	1,33,280	-	-	1,33,280	1,12,863	4,465	-	1,17,328	15,952	20,417
कुल	**12,87,07,985**	**28,97,819**	**22,41,255**	**12,93,64,549**	**8,41,81,915**	**24,98,983**	**22,24,145**	**8,44,56,752**	**4,49,07,797**	**4,45,26,071**
केंद्रीय सरकार अनुदानों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां										
1 भवन - अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	2,12,89,579	-	-	2,12,89,579	57,86,679	3,13,879	-	61,00,558	1,51,89,021	1,55,02,900
2 विद्युत, अग्निशामक एवं एचवीएसी कार्य-अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	69,00,850	-	12,50,000	56,50,850	69,00,850	-	12,50,000	56,50,850	-	-
कुल	**2,81,90,429**	**-**	**12,50,000**	**2,69,40,429**	**1,26,87,529**	**3,13,879**	**12,50,000**	**1,17,51,408**	**1,51,89,021**	**1,55,02,900**
परियोजना अनुदानों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां										
1 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण-डीईए	48,84,715	5,55,000	-	54,39,715	40,48,124	2,42,194	-	42,90,318	11,49,397	8,36,591
2 कार्यालय उपकरण	2,16,380	-	-	2,16,380	2,07,206	-	-	2,07,206	9,174	9,174
3 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - आईसीएसएसआर	51,500	-	-	51,500	48,925	-	-	48,925	2,575	2,575
4 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण-एमएमएसएसपीएसवाई, एमपी से साक्ष्य	89,000	-	-	89,000	68,875	15,675	-	84,550	4,450	20,125
5 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - आरबीआई	1,06,650	-	-	1,06,650	89,473	11,844	-	1,01,317	5,333	17,177
6 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - एमओएचयू	-	4,44,000	-	4,44,000	-	9,245	-	9,245	4,34,755	-
कुल	**53,48,245**	**9,99,000**	**-**	**63,47,245**	**44,62,603**	**2,78,958**	**-**	**47,41,561**	**16,05,684**	**8,85,642**
स्थायी परिसंपत्तियां - एफसीआरए										-
1 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	9,880	-	-	9,880	9,880	-	-	9,880	-	-
2 फर्नीचर और जुड़नार	15,23,860	-	-	15,23,860	15,23,860	-	-	15,23,860	-	-
3 बागवानी उपकरण	6,24,980	-	-	6,24,980	6,24,980	-	-	6,24,980	-	-
कुल	**21,58,720**	**-**	**-**	**21,58,720**	**21,58,720**	**-**	**-**	**21,58,720**	**-**	**-**
परियोजना अनुदानों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां - एफसीआरए										
1 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - आईडीआरसी	1,54,571	-	1,39,200	15,371	1,46,842	-	1,32,240	14,602	769	7,729
2 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - बीएमजीएफ-II	16,80,963	-	-	16,80,963	7,87,524	3,16,776	-	11,04,300	5,76,663	8,93,439
3 कार्यालय उपकरण - एनसीईएआर उप-अनुदान	22,000	-	-	22,000	20,900	-	-	20,900	1,100	1,100
4 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - बीएमजीएफ-III	1,62,250	-	-	1,62,250	1,54,137	-	-	1,54,137	8,113	8,113
कुल	**20,19,784**	**-**	**1,39,200**	**18,80,584**	**11,09,403**	**3,16,776**	**1,32,240**	**12,93,939**	**5,86,645**	**9,10,381**
सकल योग	**16,64,25,163**	**38,96,819**	**36,30,455**	**16,66,91,527**	**10,46,00,170**	**34,08,596**	**36,06,385**	**10,44,02,380**	**6,22,89,147**	**6,18,24,994**
पिछला वर्ष	**16,21,39,303**	**44,96,611**	**2,10,749**	**16,64,25,164**	**10,18,40,868**	**29,59,821**	**2,00,520**	**10,46,00,170**	**6,18,24,994**	

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
अनुसूची 7 - निवेश - धर्मादा/विनिर्धारित निधियां		
दीर्घकालिक निवेश		
सरकारी प्रतिभूतियों में	11,45,54,000	12,74,04,000
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	28,55,03,684	24,39,82,160
वर्तमान निवेश		
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,70,16,976	5,66,40,766
कुल	**41,70,74,660**	**42,80,26,926**
अनुसूची 8 - निवेश - अन्य		
दीर्घकालिक निवेश		
सरकारी प्रतिभूतियों में	4,49,96,000	7,04,46,000
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	29,28,31,939	21,40,64,963
वर्तमान निवेश		
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	4,32,14,518	7,14,61,929
कुल	**38,10,42,457**	**35,59,72,892**

अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

वर्तमान परिसंपत्तियां :				
क.				
1. वस्तु-सूची				
प्रकाशनों का स्टॉक		17,640		19,717
2. विविध लेनदार		2,33,896		2,52,728
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/अप्रदाय सहित)		17,137		35,510
4. बैंक शेष				
अनुसूचित बैंको के साथ - बचत खाते				
केनरा बैंक जीत सिंह मार्ग खाता सं.1484101001555	2,84,52,589		3,52,00,983	
केनरा बैंक जीत सिंह मार्ग खाता सं. 1484106026094	18,792		2,806	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेएनयू खाता सं.10596549875	19,710		19,186	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा एसबी खाता सं. 40070210371	10,705		55,580	
अनुसूचित बैंकों के साथ - चालू खाते				
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेएनयू एफ.सी.खाता सं. 10596547368	59,78,307		68,59,688	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेएनयू चालू खाता सं. 10596547335	40,711		41,360	
		3,45,20,814		4,21,79,603
		4,21,79,603		4,21,79,603
ख.. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां :-				
1. अग्रिम और अन्य राशियां नकद अथवा सामान अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के रूप में वसूलीयोग्य				
क) पूर्वसंदत्त व्यय	88,49,244		55,17,600	
ख) स्टाफ को अग्रिम/व्यय	42,261		97,388	
ग) अन्य अग्रिम	20,53,233		40,76,701	
घ) निर्दिष्ट निक्षेप	17,16,164		5,75,479	
ड) इनपुट कर क्रेडिट	5,23,913		4,57,151	
		1,31,84,815		1,07,24,319
2. उद्भूत आय				
क) निवेश आय - विनिर्धारित/धर्मादा निधियां	76,44,164		57,44,642	
ख) निवेश आय - अन्य	29,76,219		22,40,527	
ग) राज्य सरकार का अनुदान	1,00,000		-	
घ) पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना आय	83,48,707		40,37,620	
ड.) परियोजना अनुदान (अनुसूची 5(क) देखें)	1,22,56,437		68,16,369	
च) अप्रयुक्त/(प्राप्तियोग्य) अनुदान - एमओएफ (अनुसूची 5(ख) देखें)	-		2,09,225	
		3,13,25,527		1,90,48,383
3. प्राप्तियोग्य दावे				
क) प्राप्तियोग्य आयकर		1,98,21,679		1,39,48,800
कुल		**9,91,21,508**		**8,62,09,060**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 10 - केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान		
क. **केंद्रीय सरकार से अनुदान**		
वेतन अनुदान (अनुसूची 5(ख) देखें)	9,28,01,183	8,47,51,283
योग (क)	**9,28,01,183**	**8,47,51,283**
ख. **राज्य सरकारों से अनुदान**		
सामान्य सहायता अनुदान		
ओडिशा सरकार	5,00,000	5,00,000
महाराष्ट्र सरकार	1,00,000	1,00,000
गुजरात सरकार	10,00,000	-
नागालैण्ड सरकार	5,00,000	5,00,000
योग (ख)	**21,00,000**	**11,00,000**
सकल योग (क+ख)	**9,49,01,183**	**8,58,51,283**
अनुसूची 11- अकादमिक क्रियाकलापों से आय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना आय	2,71,36,310	2,92,50,666
प्रयुक्त सीमा तक परियोजना अनुदान (अनुसूची 5(क) देखें)	7,45,85,012	8,26,81,676
योग	**10,17,21,322**	**11,19,32,342**
अनुसूची 12 - अर्जित ब्याज		
अर्जित ब्याज - बैंक/वित्तीय संस्थाएं		
अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा पर	35,63,178	26,91,621
अनुसूचित बैंकों के साथ बचत खातों पर	5,01,040	4,69,255
सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों पर	1,93,86,620	1,84,18,558
आयकर वापसी पर ब्याज	-	5,03,460
अन्य ब्याज	81,120	66,808
योग	**2,35,31,958**	**2,21,49,702**
अनुसूची 13 - अन्य आय		
वसूलियां	1,29,50,699	1,48,02,047
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ	1,31,825	1,719
विविध आय	2,17,311	4,43,755
मकान किराया वसूलियां	1,43,067	90,849
एनआईपीएफपी स्टाफ से प्राप्त परामर्श शुल्क	-	1,55,570
विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ	37,151	6,543
आस्थगित आय से अंतरित राशि (अनुसूची 3 देखें)	9,09,613	5,72,932
योग	**1,43,89,666**	**1,60,73,415**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 14 -स्थापना व्यय		
वेतन और भत्ते	9,03,33,756	7,69,66,081
पीएफ और पेंशन निधि अंशदान	89,94,760	75,47,188
उपदान	23,63,968	22,30,066
छुट्टी वेतन	74,26,353	32,01,000
कर्मचारी लाभ और कल्याण	41,96,179	44,47,734
ईडीएलआई और प्रशासनिक प्रभार	1,90,376	1,65,905
परामर्श शुल्क	42,35,486	37,80,373
	11,77,40,878	**9,83,38,347**
घटाएं : अकादमिक क्रियाकलापों के लिए प्रभारित	3,27,34,623	2,61,51,127
कुल	**8,50,06,255**	**7,21,87,220**
अनुसूची 15 - अकादमिक क्रियाकलापों पर व्यय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना व्यय	1,07,13,378	73,59,009
परियोजना अनुदानों का उपयोग (अनुसूची 5(क) देखें)	7,45,85,012	8,26,81,676
कुल	**8,52,98,390**	**9,00,40,685**
अनुसूची 16 - प्रशासनिक व्यय		
यात्रा और परिवहन	6,77,504	3,54,895
दरें और कर	13,64,040	11,67,188
विद्युत प्रभार	59,83,487	60,11,985
जल प्रभार	6,25,652	3,79,619
मुद्रण और लेखन-सामग्री	6,32,763	4,94,330
डाकशुल्क और टेलीफोन	7,66,515	8,02,924
मरम्मत और अनुरक्षण	1,80,77,204	1,39,65,865
कार संचालन और अनुरक्षण	2,28,952	2,64,455
लेखापरीक्षा शुल्क	1,07,825	1,66,716
लेखापरीक्षा शुल्क- आंतरिक	1,06,177	1,33,599
लेखापरीक्षा शुल्क (पीएफ न्यास)	25,083	24,000
लेखापरीक्षा शुल्क (उपदान न्यास)	20,763	25,960
विविध व्यय	3,22,263	2,60,733
विधिक व्यय	10,500	9,558
विज्ञापन व्यय	1,13,558	2,70,384
पीएफ की परिपक्वता/उपदान न्यास निवेश पर हानि	8,95,230	3,76,057
ब्याज में कमी और अन्य व्यय (पीएफ न्यास)	5,74,790	-
पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,15,35,485	1,02,45,198
प्रकाशन की लागत	1,39,148	1,81,678
बैठकें और संगोष्ठियां	2,93,106	1,99,278
सामान्य/शासी निकाय की बैठक	2,06,163	1,32,390
बीमा व्यय	98,007	1,25,296
वसूलीयोग्य बट्टे खाते में डाला गया	2,29,820	73,44,130
व्यावसायिक शुल्क	1,64,428	67,331
25वीं वर्षगांठ पर व्यय	-	60,000
	4,31,98,463	4,30,63,569
घटाएं : धर्मादा/निर्धारित निधियों के लिए प्रभारित	7,60,805	7,10,609
घटाएं : धर्मादा/निर्धारित निधियों के लिए प्रभारित	40,00,000	32,00,000
कुल	**3,84,37,658**	**3,91,52,960**
अनुसूची 17 - प्रकाशनों की वस्तु-सूचियों में परिवर्तन		
वर्ष की समाप्ति पर वस्तु सूचियां		
प्रकाशन	17,640	19,717
कुल	**17,640**	**19,717**
वर्ष की समाप्ति पर वस्तु सूचियां		
प्रकाशन	19,717	19,717
कुल	**19,717**	**19,717**
निवल (वृद्धि)/कमी	**2,077**	**-**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18–लेखांकन नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत उपार्जन आधार पर तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुसार चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए जाते हैं, सिवाय बचत बैंक ब्याज के, जिसे नकद आधार पर दर्ज किया गया है।

2. संस्थान में आरबीआई चेयर के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान की गई कायिक निधि सहित दीर्घकालिक और वर्तमान निवेश, जब प्रीमियम पर प्राप्त किए जाते हैं, तो अंकित मूल्य पर वर्णित की जाते हैं। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान की गई प्रीमियम राशि को निवेश से उत्पन्न ब्याज आय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

3. प्रकाशनों की मानसूची का मूल्यांकन लागत पर किया गया है। लागत का निर्धारण एफआईएफओ आधार पर किया गया है। दस वर्ष से अधिक पुराने प्रकाशनों का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है। वर्ष के दौरान खरीदी/सब्सक्राइब की गई पत्रिकाओं और ई-संसाधन सामग्री को राजस्व के संबंध में पूर्णतः प्रभारित किया गया है।
4. अचल परिसम्पतियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया गया है जिसमें अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल हैं। अचल परिसम्पतियों का मूल्यांकन लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर किया गया है।
5. प्रबंधन द्वारा पाँच प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य पर विचार के पश्चात परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोज्यता काल के आधार पर सरल रेखा पद्धति से मूल्यहास प्रभारित किया गया है। परिसम्पत्तियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार है:-

परिसम्पत्ति विवरण	**उपयोज्यता काल**
भवन	60 वर्ष
डेटा संसाधन उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर एवं जुड़नार	10 वर्ष
होस्टल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर एवं सेमिनार कक्ष फर्नीचर	8 वर्ष
एयर कंडीनर एवं वाटर कूलर	10 वर्ष
विद्युत संस्थापनाएं	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
बागवानी उपकरण	5 वर्ष

6. अल्पावधिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के आय एवं व्यय के लेखे में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें संबंधित सेवाए प्रदान की गई थी।
7. रोजगार के बाद के और अन्य दीर्घावधिक लाभों को उस वर्ष के आय व्यय लेखे में छूट न दी गई राशि पर हुए व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की गई है। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए निर्धारित देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी गई है। रोजगार-पश्चात और अन्य दीर्घावधिक लाभों के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानियों को राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

8. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को सामान्यतः संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर लेखा पुस्तिकाओं में लेखाबद्ध किया गया है।

9. चिह्नित/वृत्ति निधियों से निवेशों पर आय का उपयोग निधियों के विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है। अप्रयुक्त राशि के शेष को, यदि कोई हो, संबंधित चिह्नित/वृत्ति निधियों में दर्शाया गया है।

10. विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभिक तौर पर देनदारी माना गया है और वर्ष के दौरान उपयोगिता के अनसार समायोजित किया गया है। अनुदानों को, मूल्यह्रास के योग्य परिसम्पत्तियों के लिए प्रयुक्त सीमा तक, आस्थगित आय माना गया है और इन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक आधार पर आय और व्यय लेखे में स्वीकृति दी गई है। राजस्व व्ययों के लिए प्रयुक्त सीमा तक वेतनों और परियोजना अनुदानों को वर्ष की आय माना गया है। आवर्ती व्ययों के लिए अनुदानों को वर्ष की आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

11. प्रावधानों को वहां स्वीकृति दी गई है जब विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देनदारी हो तथा जिसके लिए यह संभव हो कि देनदारी के समाधान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होगा और विश्वसनीय प्राक्कलन संभव हो सकेगा। देनदारी के समाधान के लिए अपेक्षित प्रावधानों की नियमित रूप से समीक्षा की गई है और जहां देनदारी के चालू सर्वोत्तम प्राक्कलन के लिए आवश्यक हो, समायोजित किया गया है।

12. वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए ऐसे अनुमान और धारणाएँ आवश्यक हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। हालाँकि ऐसे अनुमान और धारणाएँ सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित और विवेकपूर्ण आधार पर बनाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं और ऐसे अंतर उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें परिणाम क्रिस्टलीकृत होते हैं।

13. प्रबंधन द्वारा इस संबंध में आवधिक रूप से आकलन किए जाते हैं कि क्या किसी परिसम्पत्ति का क्षय होने का अंदेशा है। ऐसे क्षय के किसी संकेत के मामले में, प्रबंधन द्वारा परिसम्पति के माध्यम से वसूलीयोग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी वाहित राशि से कम है, तो परिसम्पत्ति की वाहित राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और अंतर को अक्षमता हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 19– लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियां

संस्थान के विरूद्ध एवं संस्थान द्वारा दायर किए न्यायिक मामलों के संबंध में देयता : राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः आकस्मिक देयता की राशि शून्य ली गई है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं : शून्य रु. (पिछले वर्ष : शून्य रु.)
3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उस परिमाण के अनुसार देयताएं जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के खंड 22 में अनुपालन में पहचानी गई हैं और संस्थान में उपलब्ध हैं:

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के अंत में एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को चुकता न की गई मूल राशि।	1,194,471	1,151,083
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देयब्याज तथा वर्ष के अंत में चुकता न की गई बकाया राशि।	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात न्यास द्वारा आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदात्ता को तथा एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार भुगतान की राशि के साथ चुकता की गई ब्याज की राशि।	-	-
भुगतान किए जाने में देरी की अवधि के लिए देय एवं बकाया व्याज (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता किया गया है) जिसे एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना चुकता किया गया है।	-	-
वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को उससे संबंधित उद्भूत और चुकता न किया गया ब्याज	-	-
आगामी वर्षों में भुगतान न किए जाने के कारण देय और भुगतान किए जाने योग्य बढ़त ब्याज की राशि जिसे ऐसी तारीख तक, जब ऊपर उल्लिखित ब्याज देय को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यमों को वास्तविक रूप से चुकता किया जाना है।	-	-

4. संस्थान के प्रबंधन के मतानुसार, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कारोबार के सामान्य क्रम में कम से उस राशि के समान है जिस पर इनका उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है, जब तक किअन्यथा उल्लेख न किया गया हो। अन्य सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान वित्तीय विवरणों में किया गया है।

5. 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 19,821,679 रु. के वसूलीयोग्य आयकर में से, 3,877,569 रु. की वसूलीयोग्य आयकर की राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 और पूर्व वित्तीय वर्षों से संबंधित है।

6. बंदोबस्ती/निर्धारित निधि के निवेश में 203,018,957 रु. का उद्धृत निवेश (बाजार मूल्य 206,683,589 रु.) और 293,261,494रु. का गैर-उद्धृत निवेश शामिल है।अन्य निधियों के निवेश में 87,780,963 रु. का उद्धृत निवेश (बाजार मूल्य 88,554,598 रु.) और 31,76,87,929 रु. के गैर-उद्धृत निवेश शामिल हैं। उद्धृत निवेशों के बाजार मूल्य में ऐसी वृद्धि के संबंध में बहियों में कोई समायोजन नहीं किया गया है, क्योंकि ये दीर्घकालिक निवेश के रूप में धारित परिसंपत्तियां हैं तथा लाभ/हानि ऐसे निवेशों की बिक्री/परिपक्वता के समय दर्ज की जाती है।

7. वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यताप्राप्त परिभाषित अंशदायी योजना में योगदान का विवरण निम्नानुसार है:
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 8,364,760 रु. (पिछले वर्ष 6,875,333 रु.)
पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान 630,000 रु. (पिछले वर्ष 664,941 रु.)

न्यास द्वारा प्रबंधित कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना एक परिभाषित लाभ योजना है। देनदारी के वर्तमान मूल्य का निर्धारण प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के रूप में स्वीकृत किया गया है और अंतिम देनदारी निर्मित करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा गया है। छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारी को इसी तरीके से ग्रेच्युटी के रूप में मान्यता दी गई है।

बीमांकक रिपोर्ट के अनुसार तुलन-पत्र की तारीख को मूल बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नानुसार है:

(क) आर्थिक अनुमान

मूल पूर्वानुमान इस प्रकार हैं (1) छूट की दर (2) वेतन वृद्धि। छूट की दर लेखाकरण तारीख को सरकारी बंधपत्रों पर उपलब्ध बाजार अर्जन पर आधारित है जिसमें वह शर्त शामिल हैं जो देयताओं की शर्तों से मिलती हो और वेतन वृद्धि में मूल्यवृद्धि, वरिष्ठता, प्रोन्नति और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथापि, अक्षमता के लिए कोई सुस्पष्ट भते का उपयोग नहीं किया गया है।

	विवरण	**31 मार्च 2024**	**31 मार्च 2023**
i)	छूट की दर	7.25 % प्रतिवर्ष	7.50% प्रतिवर्ष
ii)	भावी वेतन वृद्धि	9.75% प्रतिवर्ष	9.75% प्रतिवर्ष
iii)	उपदान के लिए योजना परिसम्पत्तियों की प्रत्याशित प्रतिफल दर (वित्त-पोषित)	7.25% प्रतिवर्ष	7.50% प्रतिवर्ष
ख)	**जनसांख्यिकी अनुमान**	**31 मार्च 2024**	**31 मार्च 2023**
i)	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
ii)	मृत्यु सारणी	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14

iii)	निकासी दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%

8. एनआईपीएफपी को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अपने मुख्य कर्मचारियों के वेतन व्यय के 90 प्रतिशत के बराबर वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है। वेतन, प्रशासनिक और पूंजीगत व्यय का शेष हिस्सा संस्थान द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा किया जाता है।

9. संस्थान की नीति के अनुसार, आय और व्यय में दर्शाया गया अधिशेष वित्तीय विवरणों में निम्नानुसार आवंटित किया गया है: -

अतिरिक्त देयता के लिए रिजर्व में स्थानांतरित की गई राशि	10,000,000
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित की गई राशि	10,000,000
शेष राशि अधिशेष होने पर उसे कायिक/पूंजी कोष में ले जाया जाता है	2,374,322
योग	**22,374,322**

10. परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के बराबर ₹ 595,734 की राशि को आय और व्यय खाते में आस्थगित आय से अन्य आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

11. संस्थान की नीति के अनुसार, ₹1 करोड़ की सरकारी बंदोबस्ती निधि का उपयोग संस्थान के सामान्य व्यय के लिए किया जा सकता है, ताकि इसकी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वर्ष के दौरान, ऐसी सरकारी बंदोबस्ती निधि से सामान्य व्यय के लिए ₹760,806 की राशि विनियोजित की गई है।

12. स्थापना व्यय से ₹32,734,623 की राशि विशिष्ट परियोजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों की शैक्षणिक क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय के लिए आवंटित की गई है।

13. कुल ₹131,825 की राशि "परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ" के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में जमा की गई है। यह राशि निम्नलिखित परिसंपत्तियों के निपटान से उत्पन्न होती है:

- पुराने कंप्यूटर
- पुरानी कार
- पुराने कार्यालय उपकरण

इन निपटानों से प्राप्त सम्पूर्ण प्राप्तियों को लाभ के रूप में दर्ज किया गया है, तथा बहियों में इनका कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं है।

14. पीएनबी हाउसिंग एफडी में निवेश की गई राशि के लिए ब्रिवन कंसल्टेंट्स (पी) लिमिटेड से प्राप्त ₹118,644 की प्रोत्साहन राशि और पीएनबी एफडी पर प्रोत्साहन के लिए इंटेलेक्ट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स (प्रा.) लिमिटेड से प्राप्त ₹88,984 को विविध आय के रूप में दिखाया गया है।

15. वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लिए खरीदी गई/सबस्क्राइब की गई पुस्तकों, पत्रिकाओं और ई-संसाधन सामग्री की राशि ₹11,760,387 रुपये थी, जिसे पूर्ण रूप से राजस्व में डाल दिया गया है।

16. चालू वर्ष के वित्तीय विवरण में ₹ 16,832 का पूर्व अवधि व्यय दर्ज किया गया है।

विवरण	राशि

बैठकों एवं सम्मेलन पर व्यय	5,683
मरम्मत और अनुरक्षण	4,048
यात्रा एवं परिवहन - स्थानीय	1,701
कंप्यूटर अनुरक्षण	5,400
योग	**16,832**

17. "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत अप्रयुक्त शेष और निधि प्रवाह तंत्र" बही में 98 पुस्तकों के स्टॉक का मूल्यांकन ₹17,640 (98 पुस्तकें x ₹180 प्रति पुस्तक) है। ₹19,717 की प्रारंभिक गणना गलत तरीके से दिखाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप ₹2,077 का अंतर है, जिसे अब प्रकाशन स्टॉक में कमी के रूप में लिखा गया है।

18. (i) उपरि वसूलियाँ: अनुदान-सहायता/यूसी-आधारित परियोजनाओं पर लगाए गए उपरि व्यय को आय के साथ व्यय का मिलान करने के लिए लेखांकन प्रविष्टि के कारण लाभ और हानि खाते में आय के भाग के रूप में दिखाया जाता है, जबकि इसे जीएसटी पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए समेकित बिक्री चालान के कर योग्य मूल्य में पहले से ही शामिल किया जाता है।

(ii) संस्थान द्वारा जनता के लाभ के लिए प्राप्त अनुदान को छूट प्राप्त बिक्री के अंतर्गत दर्शाया जाता है, जो जीएसटी के दायरे से बाहर है।

(iii) संस्थान की गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यसरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को जीएसटी रिटर्न में दर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अनुदान शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं हैं।

19. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः तैयार, पुनः समूहीकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

अनुसूची 1 से 19 के हस्ताक्षरकर्ता
राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(बी.एस. रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डा. आर. कविता राव)	(डा. ऊर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

अनिल कक्कड़ एवं एसोसिएट चार्टेड एकाउंटेंट के लिए
फर्म की पंजीकरण संख्या 006022एन

हस्ता./-

अनिल क्कड़
पार्टनर
एम.सं. 084882
यूडीआईएन: 24084882BKEQQW7302
स्थान: नई दिल्ली
तारीख:03/09/2024

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

पता .: 18/2, सत्संग विहार मार्ग विशेष इंस्टिट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू) नई दिल्ली 110067
दूरभाष .: 011 26569303, 26569780, 26569784
वेबसाइट .: https://www.nipfp.org.in